हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

अस्पताल पर हमला

रमजान के पाक महीने में काबुल में यह कत्लेआम इंसानियत पर ऐसा हमला है, जिसे भुलाया न जा सकेगा। पाकिस्तान ने हमला दो हजार बिस्तर वाले एक ऐसे बड़े अस्पताल पर किया, जहां हजार से ज्यादा मरीज अपना इलाज करा रहे थे। यह अफगानिस्तान का शायद सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र भी है। यहां नशा छोड़ने और नई जिंदगी की उम्मीद लिए भर्ती मरीजों का ऐसा बेरहम अंत बेहद दुखद और निंदनीय है। तालिबान के एक प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह हमला रात के नौ बजे हुआ, जब मरीज सो चुके थे या सोने की तैयारी में थे। हमले में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मतलब, मृतकों की संख्या बढ़ना तय है। पाकिस्तान के इस हमले से अफगानिस्तान में नाराजगी का जो आलम होगा, उससे दोनों देशों के बीच रिश्ते शायद लंबे समय तक सुधर न पाएंगे। हमले का ही नतीजा है कि तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने एलान कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई कूटनीति या बातचीत नहीं होगी। इशारा साफ है, तालिबान जवाबी कार्रवाई करेगा।

वास्तव में, पाकिस्तान के पास वायु सेना है, जबकि अफगानिस्तान इस मामले में बेहद कमजोर है। अफगानिस्तान के पास मिसाइलें हैं, पर विमान नहीं हैं। यह हमला उसके लिए एक सबक है, किसी भी देश को फिजूल की चीजों से बचते हुए सबसे पहले अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करना चाहिए। युद्ध केवल इरादे से नहीं, इंतजाम से लड़े जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा तनाव की पहली घटना 27 फरवरी को सामने आई थी, जब पाकिस्तानी हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 22 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हुई थी, पर उसके बाद के 24 घंटे में 274 तालिबानी अधिकारी व लड़ाके मारे गए थे। पाकिस्तानी हमले का सिलसिला टूट नहीं रहा है और तालिबान भी अपनी सीमा में नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के अलावा आतंकियों की आवाजाही भी तनाव का कारण बनी हुई है। सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अस्पताल पर हमले से तनाव में इजाफा ही होगा।

कोई मजहब, कोई कानून और कोई नैतिकता किसी अस्पताल व उसके मरीजों को जान-बूझकर निशाना बनाने को उचित नहीं ठहरा सकती।

दोनों ही देशों से रणनीतिक संबंध रखने वाले चीन ने अभी 12 मार्च को दोनों को संयम बरतने का पैगाम दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने शायद इस पैगाम को अनसुना कर दिया। अब चीन ने फिर सब्र की नसीहत दी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि दोनों देश कदम पीछे खींचेंगे। जहां तक भारत की बात है, तो विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को बर्बर, कायरतापूर्ण और अमानवीय बताया है। साथ ही, पाकिस्तान पर नरसंहार को सैन्य अभियान का रूप देने का आरोप भी लगाया है। जाहिर है, कोई मजहब, कोई कानून और कोई नैतिकता किसी अस्पताल व उसके मरीजों को जान-बूझकर निशाना बनाने को उचित नहीं ठहरा सकती। विडंबना देखिए, आतंकवाद को अपनी रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा मानने वाला देश पाकिस्तान काबुल पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगा रहा है। कोई शक नहीं कि इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान ने ही आतंकी नेटवर्क तैयार किया है और अब उसे जब इस नेटवर्क से परेशानी हो रही है, तब उसे सचमुच ऐसे कदम उठाने चाहिए, ताकि दक्षिण एशिया से आतंकवाद की जड़ें उखड़ जाएं। यही एक उपाय है कि पाकिस्तान आतंक की जड़ों को उखाड़ दे, ताकि उसे अक्सर उसके जहर का स्वाद न चखना पड़े।

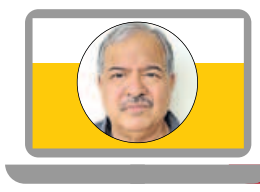

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 18 मार्च, 1951

एशियाई खेलों का समापन

एशियाई खेल-कूद जिस उत्साह व उमंग के साथ प्रारंभ हुए थे, उसी भव्य समारोह के साथ समाप्त भी हुए। अन्तिम दिन राष्ट्रीय क्रीड़ास्थल (स्टेडियम) में ग्यारह देशों से आये हुए खिलाड़ी अपने-अपने देशों के झंडे लेकर प्रयाण करते हुए आगे बढ़े और नेहरूजी ने सलामी ली। उसके बाद ग्यारह तोपों की गड़गड़ाहट के बीच एशियाई खेल-कूद का झंडा उतार दिया गया और ज्योति बुझा दी गई।

इस खेल-कूद प्रतियोगिता की विशेषता यह रही कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम आने के पुरस्कार-स्वर्णपदक किसी एक या दो देशों के खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि सात देशों में बंट गये। उदाहरणार्थ, कसरत के खेलों के अधिकांश स्वर्ण पदक जापान को मिले और भारत का नम्बर दूसरा रहा। फुटबाल में भारत प्रथम रहा तो फिलिपाइन तैरी में प्रथम रहा। ईरान की विशेषता यह थी कि वजन उठाने के सातों खेलों के स्वर्ण पदक उसे मिले। सिंगापुर को भी कसरत, तैरी तथा वजन उठाने के खेलों में स्वर्ण पदक मिले। जहां तक इंडोनेशिया तथा बर्मा का संबंध है, उन्हें रजत व कांस्य पदकों से ही सन्तोष करना पड़ा।

सांस्कृतिक सम्मेलन : राजधानी में एशियाई खेलों की चहल-पहल समाप्त हुई थी कि सांस्कृतिक सम्मेलन की चहल-पहल शुरू हो गई। ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित इस सम्मेलन में 500 लेखक, कलाकार व भाषाशास्त्री भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि भारत में दिखाई देने वाली 'विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है, जैसे रेशम का धागा सुन्दर मणियों अथवा फूलों को पिरो कर एक सुन्दर हार तैयार कर देता है।' उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का स्रोत अनन्त काल से इस देश में बहता रहा है और 'वह अपनत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यावश्यक हो गया है।' प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति ऐसी होनी चाहिए, जो कि संपूर्ण विश्व को अपील करे।

हम इस जंग की कितनी कीमत चुकाएंगे

अमेरिका-ईरान युद्ध से भारत को बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर देश इस जंग में उतरना नहीं चाहते। होर्मुज का रास्ता जैसे ही खुलेगा, आर्थिक तनाव घटने लगेगा।

यहां स्कैन करें

मनोज पंत | पूर्व कुलपति एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री

हर जंग की एक कीमत होती है। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की भी है। हालांकि, अन्य देशों को इससे कितना नुकसान हो रहा है, इसका आकलन इससे होगा कि यह युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित कर रहा है। इस लिहाज से देखें, तो ईरान युद्ध का बेशक कुछ परोक्ष असर है, लेकिन विश्व व्यवस्था इससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो रही।

इसके कुछ कारण हैं। दरअसल, ईरान आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से तेल के सिवाय बहुत ज्यादा वैश्विक व्यापार नहीं करता। विश्व आर्थिकी में उसका योगदान बमुश्किल 0.3 से 0.7 प्रतिशत है, जिसमें तेल की हिस्सेदारी ही सबसे अधिक है। रही बात अमेरिका की, तो उसकी क्षमता काफी ज्यादा है, इसलिए आर्थिक मुश्किलों को झेलना फिलहाल उसके लिए आसान है। हां, ईरान की आर्थिक स्थिरता, स्थानीय जनजीवन, बुनियादी ढांचे आदि पर युद्ध का प्रभाव जरूर पड़ रहा है, लेकिन यह उसकी घरेलू परिस्थितियां हैं। जब तक विश्व व्यवस्था पर कोई देश असरंदाज नहीं होता, उसकी समस्या दुनिया को परेशान नहीं करती।

ऐसा हमने रूस-यूक्रेन युद्ध में भी देखा है। यूक्रेन मक्के के बड़े निर्यातकों में से एक है। इसीलिए, युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद ही जब मक्के की आपूर्ति को लेकर सहमति बन गई और दुनिया के तमाम कोनों तक यह पहुंचने लगा, तो इस जंग को लेकर चर्चाएं सिमटने लगीं। अब कमोबेश तमाम मुल्क इसे सिर्फ अमेरिका, यूरोप और रूस की लड़ाई मान रहे हैं। इराक युद्ध का भी यही हश्र दिखा था। उसका भी वैश्विक असर नहीं के बराबर था।

रही बात भारत की, तो हमें भी ईरान युद्ध से सीधा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तेहरान पर वर्षों से प्रतिबंध आयद है। उसके साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, पर द्विपक्षीय कारोबार पर हमने कम ही ध्यान दिया है। वहां नई दिल्ली ने बंदरगाह बनाए हैं और बुनियादी ढांचों में निवेश किया है। हम उससे मूलतः तेल आयात करते थे, वह भी बीते चार-पांच साल में काफी कम कर दिया था। मगर अभी दिक्कत यह है कि होर्मुज जलमार्ग के प्रभावित रहने से मध्य-पूर्व से तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जबकि तेल एक ऐसा उत्पाद माना जाता है, जिसमें 'मार्जिन' से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए, कच्चे तेल के दाम में मामूली बढ़ोतरी भी तुरंत उसकी घरेलू कीमतें बढ़ा देती हैं। अभी यही हो रहा है, जिससे भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश चिंतित हैं।

सोमवार सुबह तक ब्रेंट क्रूड की कीमत 106 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो 27 फरवरी को 72 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी, युद्ध शुरू होने के बाद कीमतों में 40 फीसदी से अधिक का इजाफा हो चुका है। आशंका जताई जा रही है कि यह बढ़कर 150 डॉलर प्रति बैरल के पार भी जा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो निस्संदेह कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। मिसाल के लिए, तेल के घरेलू दाम पांच से दस प्रतिशत तक भी बढ़ते हैं, तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जिससे उत्पादों के दाम परोक्ष रूप से बढ़ सकते हैं। हालांकि, फिलहाल चिंता तेल से अधिक गैस की है। हमारे यहां एलएनजी कतर से आती है और दिक्कत यह है कि 2 मार्च के ईरानी हमले के बाद कतर एनर्जी ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक बाजार पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि कतर दुनिया की 20 प्रतिशत गैस की आपूर्ति करता है। हालांकि, अगर भारत का यह दावा सही है कि एलपीजी लदे दो भारतीय जहाज होर्मुज से सुरक्षित निकल आए हैं, तो यह हमारे लिए पुरसुकून है। इससे अन्य देशों के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं।

वास्तव में, इस युद्ध में ईरान ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत पलटवार किया है। वह जानता है कि आज भू-राजनीति को भू-आर्थिकी खूब प्रभावित करती है और दुनिया सिर्फ आर्थिक नुकसान समझती है। इसीलिए, तेहरान पर जैसे ही हमला हुआ, उसने सीधे जवाब देने के बजाय मध्य-पूर्व के उन देशों को निशाना बनाया, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। साथ ही, उसने होर्मुज जलमार्ग को भी बाधित कर दिया, ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को चोट पहुंचाई जा सके। उसके द्वारा यह एलान किए जाने की भी खबर है कि जो देश ईरान से सीधे नहीं लड़ेंगे, उनके जहाजों को होर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। यह कब होता है, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका एक असर अमेरिका के अपने 'मित्र देशों' में भी अलग-थलग पड़ जाने के रूप में दिखा है। यहां तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज खुलवाने के लिए युद्धपोत भेजने के आह्वान को कई देशों ने सीधे-सीधे खारिज कर दिया है।

अमेरिका के साथ दिक्कत यह भी है कि उसकी लाखों डॉलर की मिसाइलें हजारों डॉलर के ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के चक्कर में बर्बाद हो रही हैं। उसकी घरेलू चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। भारत में जहां तेल कंपनियां सरकार के नियंत्रण में हैं, वहीं इसके विपरीत, अमेरिका में मुक्त बाजार की संकल्पना है। लिहाजा, वहां तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। चूंकि वहां ज्यादातर लोग निजी गाड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बढ़ी कीमत जनता की नाराजगी बढ़ाने लगी है। इसका असर महंगाई पर भी दिखने लगा है। जाहिर है, अमेरिकी हुकूमत इसे जल्द संभालना चाहेगी, क्योंकि वहां लोग राजनीतिक नफा-नुकसान से अधिक आर्थिक लाभ-हानि की सोचते हैं।

यही वह पड़ाव है, जहां युद्ध को बंद करने का दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति पर पड़ेगा। आकलन यह भी है कि होर्मुज का रास्ता जैसे ही खुल जाएगा, यह जंग अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान बनकर रह जाएगी, ठीक यूक्रेन युद्ध की तरह। कोई अन्य देश इसमें शायद ही शामिल होना चाहेगा। फिर, इससे तेल के दाम भी घटकर 75 डॉलर के आसपास हो जाएंगे, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था अपनी गति से बढ़ने लगेगी।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बात करें, तो इस पर तात्कालिक कोई असर शायद ही पड़ेगा। अगर यह जंग एक-दो हफ्ते में खत्म हो जाती है, तो लोगों को निजी तौर पर बेशक दिक्कतें होंगी, लेकिन देश की आर्थिक सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हां, यदि यह एक-दो महीने तक खिंच गई, तो हमारे लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खास तौर से उत्पादन पर असर पड़ेगा। हालांकि, यह युद्ध इतना लंबा चलेगा, इसकी आशंका कम है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लड़ाई में सैनिकों से भी ज्यादा शिकार हो रहीं लड़कियां

यहां स्कैन करें

ऋतु सारस्वत | समाजशास्त्री

पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों से छिड़ी जंग ने पूरे क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिति को अस्थिर कर दिया है। युद्ध और सैन्यवाद को समाज में महिमामंडित करने के लिए युद्ध-वीरों की परेड और स्मारकों जैसी परंपराएं विकसित की गई हैं। किंतु बहुत कम लोगों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि आधुनिक युद्धों में सबसे अधिक हानि सैनिकों की नहीं, नागरिकों की होती है, और उससे भी कम लोग यह स्वीकार करते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां युद्ध से प्रभावित होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की जून 2025 में जारी रिपोर्ट 'ग्लोबल ट्रेंड्सः फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024' संकेत देती है कि समकालीन विश्व में जंग और हिंसा महज सीमाओं के प्रश्न नहीं हैं, बल्कि वे एक गहरे मानवीय संकट का रूप ले चुकी हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2025 तक विश्व में 12.2 करोड़ लोग युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण विस्थापित हो चुके थे। चिंताजनक तथ्य यह है कि इन शरणार्थियों में करीब आधी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है, जबकि लगभग 40 प्रतिशत बच्चे हैं।

आधुनिक युद्धों की हिंसा केवल मोर्चों तक नहीं रहती, वह महिलाओं और बच्चों को कठोर परिस्थितियों से जूझने को मजबूर करती है।

सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जारी 'वूमेन, पीस ऐंड सिक्योरिटी एजेंडा' चेतावनी देता है कि दुनिया भर में लगभग 67.6 करोड़ महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में रह रही हैं, जो संघर्षों से 50 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं। यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि आज विश्व 1946 के बाद सबसे अधिक सक्रिय सशस्त्र संघर्षों का सामना कर रहा है, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए गंभीर जोखिम और अभूतपूर्व पीड़ा का कारण बन रहे हैं। यह स्थिति पिछले दो दशकों में महिला अधिकारों के क्षेत्र में हुई प्रगति को कमजोर कर सकती है।

अमेरिकी नारीवादी कार्यकर्ता सुसान ब्राउनमिलर अपनी किताब *अगेंस्ट आवर विल : मेन, वीमेन ऐंड रेप* में लिखती हैं, 'दुष्कर्म भय पैदा करने की एक सचेत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को निरंतर डर और असुरक्षा की स्थिति में रखा जाता है।' वहीं 2004 में प्रकाशित वेनोना जाइल्स और जेनिफर हाइंडमैन की किताब *साइट्स ऑफ वायलेंस : जेंडर ऐंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स* इराक, सूडान और पूर्व यूगोस्लाविया जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों के उदाहरणों से बताती है कि आधुनिक युद्धों की हिंसा केवल मोर्चों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह नागरिक जीवन में महिलाओं और बच्चों को कठोर परिस्थितियों से जूझने को मजबूर करती है।

इस प्रकार युद्ध केवल एक सैन्य या राजनीतिक संकट नहीं रह जाता, बल्कि वह समाज में पहले से मौजूद लैंगिक विषमताओं को और अधिक गहरा कर देता है। परिणाम यह होता है कि औरतों को मानवीय सहायता की सबसे अधिक दरकार होती है, लेकिन विडंबना यह है कि राहत और पुनर्वास तक उनकी पहुंच ही सबसे अधिक बाधित रहती है। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी महिलाएं अक्सर जोखिम की स्थिति में बनी रहती हैं। लैंगिक हिंसा कई बार संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहती है। संघर्ष के समय सुरक्षा संबंधी खतरों या आर्थिक कठिनाइयों के कारण लड़कियों की शिक्षा रोक दी जाती है, जिससे कम आयु में विवाह होने की आशंका बढ़ जाती है। युद्ध की परिस्थितियों में मानवीय सहायता भी लड़कियों को समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। यौन हिंसा से जुड़ा सामाजिक कलंक इस संकट को और गहरा बना देता है।

ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित महिलाएं अक्सर चुप रहने को विवश होती हैं। वे न तो हिंसा की शिकायत दर्ज करा पाती हैं और न ही जरूरी सहायता प्राप्त कर पाती हैं। आर्थिक असमानता भी इस त्रासदी को और तीव्र करती है। संघर्ष के दौरान अनेक महिलाएं अपने परिवार के उन सदस्यों को खो देती हैं, जिनकी आय पर उनका जीवन निर्भर था और अचानक उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों के साथ गहरी आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। युद्ध की विभीषिका के बीच मानवाधिकार की संकल्पनाएं तब दम तोड़ती नजर आती हैं, जब असहाय महिलाएं और बच्चे जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। निस्संदेह, यह हमारी सभ्यता एवं नैतिकता पर गहरे प्रश्न खड़े करता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

संसार का संचालित होना

एक बार एक साधक ने प्रश्न किया, 'बाबा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है?' हम जिस संसार में रहते हैं, वह असंख्य रूपों और रंगों से भरा हुआ है। पर्वत, नदियां, वन, पशु-पक्षी, मनुष्य, विचार, भावनाएं- सब कुछ अलग-अलग दिखाई देता है। प्रकृति का यह वैविध्य इतना व्यापक है कि पहली दृष्टि में यही लगता है, मानो दुनिया असंख्य स्वतंत्र शक्तियों से संचालित हो रही हो।

हालांकि, भारतीय दर्शन कहता है कि इस समूची सृष्टि के पीछे एक ही परम चेतना कार्य कर रही है। वही चेतना, जिसे परम पुरुष, परम ब्रह्म या सर्वोच्च सत्ता कहा गया है। यही वह मूल आधार है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसके सहारे वह चलती है और अंततः जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। प्राचीन वैदिक वाक्य 'एको ही रुद्रः न द्वितीयाय' इसी सत्य को प्रकट करता है, जिसका अर्थ है कि केवल एक ही परम सत्ता है। संसार में दिखाई देने वाले सभी रूप उसी एक सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं।

सृष्टि के प्रारंभ में केवल वही एक अस्तित्व था- न कोई नाम था, न रूप। जब उसकी इच्छा से सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तब प्रकृति के माध्यम से विविधता का विस्तार होने लगा। इसी प्रक्रिया में धीरे-धीरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और अनगिनत रूप सामने आए। प्रकृति के पांच मूलभूत तत्व- आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस सृजन-प्रवाह के प्रारंभिक आधार बने। इन्हीं तत्वों के संयोजन से ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां और वन बने। समय के साथ विकास हुआ और सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर जटिल जीवों तक का क्रम बना। इसी विकास-यात्रा में पौधे, पशु और अंततः मनुष्य का उदय हुआ।

मानव जीवन का महत्व इसी कारण विशेष है कि उसमें सोचने, समझने व सत्य की खोज करने की क्षमता है। मनुष्य उस मूल चेतना को जानने और अनुभव करने की क्षमता रखता है, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है।

कई लोग सृष्टि के कारण के रूप में समय, प्रकृति, भाग्य या पदार्थ को मानते हैं। हालांकि, ये सभी केवल अभिव्यक्तियां हैं, अंतिम सत्य नहीं। ब्रह्मांड का मूल कारण वही परम चेतना है, जो सबके पीछे सक्रिय है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य भी इसी सत्य को अनुभव करना है। जब मनुष्य साधना, भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर झांकता है, तो उसे धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक गहरी चेतना प्रवाहित हो रही है, जो अनंत और आनंदमय है।

जब मनुष्य साधना, भक्ति और आत्म चिंतन के माध्यम से अपने भीतर झांकता है, तो उसे धीरे-धीरे अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है।

ऐसी अनुभूति व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करती है। उसका मन स्थिर होने लगता है और जीवन के संघर्ष भी भारी नहीं लगते। यही अनुभव उसको आंतरिक संतुलन, शांति और आनंद की ओर ले जाता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

शिवराज सिंह चौहान | केंद्रीय कृषि मंत्री

सरकार-सरकार में फर्क होता है, नेता-नेता में फर्क होता है, नीति-नीयत में फर्क होता है। नेता देशभक्त हो, कल्पनाशील मस्तिष्क का हो, संवेदनशील हो और उसके दिल में देश और जनता की सेवा की तड़प हो, तो नई योजनाएं जन्म लेती हैं।

अनुलोम-विलोम
सोनम वांगचुक

सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे

लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और नवप्रवर्तनकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत लगभग छह महीने तक हिरासत में रखने के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एनएसए के प्रावधानों को वापस लेने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी का कानूनी आधार समाप्त हो गया और रिहाई संभव हो सकी। सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। उनकी भूमिका एक ऐसे जिम्मेदार नागरिक की रही है, जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की बात करते हैं। सरकार द्वारा एनएसए हटाने के निर्णय के पीछे कई कारण समझे जा सकते हैं। मामला न्यायिक समीक्षा में था और यदि अदालत में प्रस्तुत आधार पर्याप्त मजबूत नहीं होते, तो सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा, इस प्रकरण ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जिससे एक संतुलित और विचारशील निर्णय की आवश्यकता और बढ़ गई। प्रशासनिक दृष्टि से भी यह महसूस किया गया होगा कि स्थिति को आगे संवाद और अन्य माध्यमों से बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में कुछ संभावित चूकें भी नजर आती हैं। सबसे प्रमुख यह कि एनएसए जैसे कठोर कानून का प्रयोग ऐसे मामले में किया गया, जहां बाद में उसे वापस लेना पड़ा। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रारंभिक स्तर पर परिस्थितियों का आकलन या तो पर्याप्त स्पष्ट नहीं था या फैसला अपेक्षित सावधानी के साथ नहीं लिया गया। दूसरी बात, यदि किसी मामले में कानूनी आधार लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह पाता, तो यह जांच और प्रक्रिया की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करता है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और ठोस तथ्यों पर आधारित निर्णय अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। खैर, वजह जो भी हो, सोनम वांगचुक की रिहाई को एक ऐसे निर्णय के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सरकार ने परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए अपने कदम पीछे खींचा। यह जहां एक ओर सुधारात्मक निर्णय का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर यह भी बताता है कि प्रारंभिक फैसलों में अधिक सतर्कता और संतुलन की आवश्यकता थी।

विनय मोहन, टिप्पणीकार

सोनम वांगचुक को जिस कानून को आधार बनाकर गिरफ्तार किया गया था, वह उनके मामले में सही नहीं था। अच्छा है कि सरकार नरम पड़ गई, अन्यथा एक बड़ा जनांदोलन आकार लेने लगा था।

अंकुरी मिश्र, टिप्पणीकार

अपनी मर्यादा समझें सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक की रिहाई पर सियासत करना और यह कहना कि उन्होंने पर्यावरण के पक्ष में आवाज उठाने की कीमत चुकाई, सरासर गलत है। भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जहां हर नागरिक को अपनी बात रखने, विरोध दर्ज कराने और सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहां असहमति को भी पर्याप्त स्थान मिलता है। परंतु, इस अधिकार के साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है कि विरोध और आंदोलन संविधान के दायरे में रहकर व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाएं। जब तक वांगचुक ने लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से अपनी मांगों को उठाया, तब तक उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, किंतु जब किसी आंदोलन का स्वरूप उग्र या हिंसक होने लगे और उसके बावजूद नेतृत्व मौन साधे रहे, तो यही संदेश जाता है कि उस हिंसक रुख का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन किया जा रहा है। लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करना हर किसी का अधिकार है, पर कानून और व्यवस्था को चुनौती देकर या हिंसा का सहारा लेकर सरकारों पर दबाव बनाना सही नहीं है। हमें यह समझना ही होगा कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि यह कर्तव्यों और मर्यादाओं का भी तंत्र है। यदि हर समूह अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरकर उग्रता या अव्यवस्था का रास्ता अपनाने लगे, तो कानून-व्यवस्था और सामाजिक संतुलन, दोनों नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। आंदोलन तब तक ही नैतिक शक्ति बनाए रखते हैं, जब तक वे संयम, संवाद और तर्क की शक्ति पर टिके रहते हैं। इतिहास भी यही सिखाता है कि स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन हमेशा शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक प्रयासों से ही संभव हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि कोई भी जनांदोलन अपनी नैतिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हिंसा और टकराव से दूर रहे। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन उस असहमति की अभिव्यक्ति भी संविधान और कानून की मर्यादा के भीतर होनी चाहिए। तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनती है और समाज में विश्वास कायम रहता है।

मुनीष भाटिया, टिप्पणीकार

सोनम वांगुचक जैसे लोग आलोचना को एकमात्र ध्येय समझते हैं, जबकि सरकार किसी आलोचना से परेशान नहीं होती, बल्कि जब कोई नागरिक विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने लगे और अपने देश में अराजकता पैदा करने लगे, तो उसे रोकने के लिए वह कठोर कदम उठाती है।

दीप्ति, टिप्पणीकार

बिना सत्यापन वाले एलपीजी ग्राहक ही 'आधार सत्यापन' कराएं

स्पष्टीकरण

नई दिल्ली, एजेंसी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए अब आधार आधारित ई-केवाईसी (पहचान सत्यापन) जरूरी है, लेकिन यह नियम केवल उन्हीं ग्राहकों पर लागू होगा, जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। सोशल मीडिया पर फैले भ्रम के बाद मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि सभी एलपीजी ग्राहकों को आधार ई-केवाईसी करनी होगी। इसके बिना गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिसे लेकर लोगों में हड़बड़ी फैल गई है। मंत्रालय ने साफ किया है कि यह कोई नया नियम नहीं है। यह पहले से लागू प्रक्रिया का ही हिस्सा है। यह नियम सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है, जिन्होंने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जिन लोगों ने पहले ही सत्यापन करा लिया है, उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है।

इसलिए जरूरी : जो ग्राहक सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए ई-केवाईसी जरूरी है। इसीलिए सरकार ने उपभोक्ताओं से इसे जल्द पूरा करने की अपील की है। यह प्रक्रिया बहुत आसान है और इसे घर बैठे मुफ्त में किया जा सकता है हालांकि, यह भी साफ किया है कि ई-केवाईसी न होने की स्थिति में भी एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए अलग नियम : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह नियम सीमित है। मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के उपभोक्ताओं को यह प्रक्रिया साल में सिर्फ एक बार करनी होती है और वह भी सात सिलेंडर लेने के बाद यानी 8वें और 9वें रिफिल पर सब्सिडी पाने के लिए जरूरी होती है। सरकार का कहना है कि यह कदम असली उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने और गैस सब्सिडी का सही लोगों तक पहुंचना तय करने के लिए उठाया गया है।

ऑनलाइन ई-केवाईसी ऐसे करें
- अपनी एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदाता कंपनी का ऐप डाउनलोड करें।
- आधार फेसआरडी ऐप इंस्टॉल करें।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें या लॉग इन करें।
- होम स्क्रीन पर 'आधार ईकेवाईसी' का विकल्प चुनें
- ऐप आपको लाइव फोटो लेने के लिए कहेगा।
- चेहरे की स्कैनिंग सफल हो जाने के बाद, ईकेवाईसी अनुरोध सबमिट हो जाता है।
- ईकेवाईसी को आमतौर पर 24-48 घंटों के भीतर मंजूरी मिल जाती है।

वेबसाइट से तरीका
- My LPG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- अपनी गैस कंपनी चुनें। लॉगिन करें
- "ई-केवाईसी" या "आधार सत्यापन" विकल्प चुनें
- ओटीपी या बायोमेट्रिक के जरिए सत्यापन करें

क्या-क्या जरूरी होगा
- गैस कनेक्शन से जुड़ा आधार नंबर
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- स्मार्टफोन और इंटरनेट

जरूरत पर ही सिलेंडर बुक करने की अपील

देश में गैस आपूर्ति को लेकर बनी चिंता के बीच इंडियन ऑयल ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे एलपीजी सिलेंडर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बुक करें और घबराकर पहले से बुकिंग न करें। कंपनी ने कहा है कि कुछ लोग डर के कारण जरूरत से पहले ही गैस बुक कर रहे हैं, जिससे मांग अचानक बढ़ रही है और डिलीवरी में देरी हो सकती है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि देश में घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल के दिनों में गैस बुकिंग तेजी से बढ़ी है।

बाजार 30's

शेयर बाजार

सेंसेक्स 76,070 +567.99

निफ्टी 23,581 +172.35

सेंसेक्स: कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
टॉप लूजर		
एटरनल	234.70	5.70
टाटा स्टील	195.40	4.41
टॉप लूजर		
इंफोसिस	1232.50	-1.37
बजाज फाई.	868.60	-1.17

निफ्टी: कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
टॉप गेनर		
एटरनल	234.45	5.59
टाटा स्टील	195.20	4.42
टॉप लूजर		
विप्रो	191.10	-2.06
सिप्ला	1,280.40	-1.51

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,61,300	+1,050
चांदी	2,62,500	+6,000

करेंसी डॉलर/रुपया **92.40 -0.12**

केंद्रीय संचार मंत्री ने भारतीय डाक विभाग की तीन नई विशेष सेवाओं की शुरुआत की

स्पीड पोस्ट तय समय पर नहीं पहुंची तो रकम वापस मिलेगी

सहूलियत

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को डाक विभाग की तीन नई सेवाओं की शुरुआत की है। इनमें 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल तथा 48 स्पीड पोस्ट शामिल हैं। इनके जरिए अब जरूरी दस्तावेज और पार्सल महज 24 घंटे के भीतर गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। देरी होने पर पैसे वापसी की गारंटी भी दी जाएगी।

इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि आज का दिन हमारे विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इंडिया पोस्ट देश के हर नागरिक और वैश्विक ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है।

इस पहल को इंडिया पोस्ट और उसके करोड़ों ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए सिंधिया ने कहा कि ये सेवाएं विश्वसनीयता, जवाबदेही और उत्कृष्ट सेवा के प्रति नई प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। उन्होंने सेवाओं के व्यापक परीक्षण और सुधार में लगे डाक कर्मचारियों के समर्पण की भी सराहना की।

लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिलेगी : भारतीय डाक विभाग की नई सेवाएं भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इनके माध्यम से विभाग एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है तथा प्रमुख महानगरों में विश्वसनीय, सुरक्षित और समयबद्ध डिलीवरी समाधान उपलब्ध करा रहा है।

मंगलवार को डाक विभाग की नई सेवाओं की शुरुआत करने के बाद संबोधित करते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

इन शहरों में मिलेगी सुविधा

डाक विभाग की इन सेवाओं का लाभ फिलहाल देश के छह प्रमुख शहरों में मिलेगा। पहले चरण में यह सेवाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में उपलब्ध होंगी।

सेवा की पांच प्रमुख विशेषताएं

1. समय की गारंटी
24 स्पीड पोस्ट एवं 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा के अंतर्गत अगले दिन डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। 48 स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से दो दिनों में समयबद्ध और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।

2. रविवार की छुट्टी नहीं
पहली बार '24 स्पीड पोस्ट' सेवा के तहत रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी डिलीवरी की जाएगी। साल में केवल तीन राष्ट्रीय अवकाशों (26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) को छोड़कर यह सेवा साल के 362 दिन चालू रहेगी।

3. ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी
पार्सल की डिलीवरी ओटीपी सत्यापन के बाद ही की जाएगी। ग्राहकों को पल-पल की जानकारी एसएमएस अलर्ट और ट्रैकिंग के जरिए मिलती रहेगी।

4. मनी-बैक गारंटी
यदि डाक विभाग तय समय सीमा के भीतर पार्सल डिलीवर करने में विफल रहता है, तो ग्राहकों को मनी-बैक गारंटी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम डाक विभाग की जवाबदेही को और मजबूत करेगा।

5. कारोबारियों के लिए फायदेमंद
छोटे कारोबार और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी यह सेवा उपयोगी होगी। इसमें फ्री बल्क पिकअप, अभी बुक करें-बाद में भुगतान करें और और केंद्रीकृत बिलिंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी

यूपी में अंडों पर उपयोग की आखिरी तारीख जरूरी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश में अंडों पर उसके उत्पादन तिथि से लेकर एक्सपायरी डेट तक लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना भी है। एक अप्रैल से इसे प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी है।

नकली या पुराने अंडों के बढ़ते कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सरकार जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रही है। उद्देश्य यही है कि चाइनीज नकली अंडों के साथ-साथ हानिकारक पुराने अंडों की खरीद-बिक्री पर भी स्थाई रूप से अंकुश लग सके। इसके तहत नई व्यवस्था लागू होने के बाद दुकानदार कई दिनों पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का सामान मिल सकेगा। सोमवार को इस संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पुराने या खराब अंडों को बेचने पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का निर्णय किया गया। पशुपालन निदेशक (विभागाध्यक्ष) डा. मेमपाल ने बताया कि लोगों को ताजे और सुरक्षित अंडे कैसे मिलें, इस पर गहनता से विचार किया गया।

गुलाबी और नीली स्याही

अंडों पर मोहर लगाने के लिए फूड-ग्रेड इंक (स्याही) का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि जिन अंडों को सामान्य तापमान पर रखा जाएगा, उन पर गुलाबी स्याही का इस्तेमाल किया जाए; जबकि जिन अंडों को शीत भंडार गृहों में रखा जाएगा, उन पर मुहर लगाने के लिए नीली स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर अंडों पर कोई मुहर नहीं लगी होगी, तो उन्हें खाने के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा और फिर उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

अंडे की वैधता अवधि

लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के सामान्य तापमान पर रखे गए अंडों का इस्तेमाल, अंडे दिए जाने की तारीख से दो सप्ताह के अंदर कर लेना चाहिए; और जब अंडों को दो डिग्री सेल्सियस से आठ डिग्री सेल्सियस के बीच के रेफ्रिजरेशन तापमान पर रखा जाता है, तो उनका इस्तेमाल अंडे दिए जाने की तारीख से पांच सप्ताह के अंदर किया जा सकता है।

अपर मुख्य सचिव (पशुधन) मुकेश मेश्राम के मुताबिक पहले खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था और कई मामलों में नियमों की अनदेखी सामने आई थी, उपभोक्ता भी इससे अनभिज्ञ थे।

डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी

नई दिल्ली। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) के सचिव एस कृष्णन ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत के जीडीपी में लगभग 13 प्रतिशत का योगदान करती है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि दर विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा (एआई) के बढ़ते उपयोग से और तेज होगी।

मारुति सुजुकी को 5,786 करोड़ का नोटिस

मुंबई। देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन नर्मािता मारुति सुजुकी को आयकर विभाग से 5,786.4 करोड़ रुपये का नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे 16 मार्च 2026 को आयकर विभाग से वत्ति वर्ष 2022-23 के लिए प्रारूप आकलन आदेश प्राप्त हुआ है। कंपनी ने कहा कि वह इसके खिलाफ विवाद समाधान पैनल के समक्ष आपत्ति दर्ज करेगी।

रुपया 12 पैसे टूटकर सर्वकालिक निचले स्तर पर

मुंबई। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया मंगलवार को 12 पैसे टूटकर अपने सबसे निचले स्तर 92.40 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया संकट के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार पूंजी निकासी के कारण रुपये में यह गिरावट आई। देशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान भी रुपये को कमजोर स्तर पर सहारा देने में मदद कर रहा है।

जियो पेमेंट्स बैंक ने नई सुविधा शुरू की

मुंबई। जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (जेपीबीएल) ने मंगलवार को यूपीआई आधारित नकद निकासी सेवा शुरू करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया कि ग्राहक अब बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टचपॉइंट्स पर क्यूआर कोड स्कैन कर नकद निकाल सकेंगे। उन्हें अपना पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड या पारंपरिक एटीएम कार्ड की अब जरूरत नहीं होगी।

रेनो की डस्टर नए अवतार में वापस लौटी

नई दिल्ली। रेनो इंडिया ने मंगलवार को भारत में अपनी मध्यम आकार की एसयूवी 'डस्टर' के पूरी तरह नए अवतार को 10.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया। देशभर में इसकी डिलिवरी अब शुरू हो गई है। नई डस्टर में टर्बो टीसीई 1.0 लीटर और 1.6 लीटर वाले दो इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। इसे मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ भी पेश किया गया है।

पीएनबी रोल्टा के एनपीए की बिक्री करेगा

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने मंगलवार को रोल्टा प्राइवेट लिमिटेड की 450.85 करोड़ रुपये की एनपीए को बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। इन एनपीए में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित करीब 7,800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जमीन और इमारत शामिल है। इस संपत्ति का आरक्षित मूल्य 250 करोड़ रुपये तय किया गया है और बोली लगाने की न्यूनतम राशि 2.5 करोड़ रुपये रखी गई है।

'करार से जुड़ा हार्ड रॉक का फैसला एकतरफा'

नई दिल्ली। जेएसएम ग्रुप ने हार्ड रॉक इंटरनेशनल की तरफ से फ्रेंचाइजी समझौता खत्म करने और भारत में 10 हार्ड रॉक कैफे बंद करने के फैसले को मंगलवार को 'एकतरफा और गैर-कानूनी' करार दिया। पिछले 22 वर्षों से भारत में हार्ड रॉक ब्रांड की साझेदार रहे जेएसएम ग्रुप ने बयान में कहा कि कंपनी की तरफ से किए गए दावे अनुबंध की शर्तों के बाहर हैं और किसी न्यायालय के आदेश पर आधारित नहीं हैं।

वाहन क्षेत्र में खरीद से बाजार उछले

मुंबई, एजेंसी। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख और धातु एवं वाहन शेयरों में खरीदारी के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन मजबूती रही। सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 172 अंक की तेजी रही।

सेंसेक्स 567.99 अंक यानी 0.75 प्रतिशत चढ़कर 76,070.84 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 801.41 अंक बढ़कर 76,304.26 अंक तक पहुंच गया था। निफ्टी भी 172.35 अंक यानी 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,581.15 अंक पर बंद हुआ। टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरटेल और मारुति के शेयरों में भी तेजी रही। दूसरी तरफ, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और एचसीएल टेक के शेयरों में गिरावट का रुख देखा गया।

जेपी के लिए अदाणी की बोली मंजूर

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को दिवाला प्रक्रिया के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. के अधिग्रहण के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज लि. की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. (जेएएल) ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, 'एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने 17 मार्च, 2026 को अपने आदेश में अदाणी एंटरप्राइजेज की समाधान योजना को मंजूरी दी।'

पिछले साल नवंबर में, कर्जदाताओं की एक समिति ने जेएएल के अधिग्रहण को लेकर उद्योगपति गौतम अदाणी की समाधान योजना को मंजूरी दी थी। उसने जेएएल के लिए सफल बोली लगाते हुए वेदांता और डालमिया भारत को पीछे छोड़ दिया है। अदाणी को कर्जदाताओं से अधिकतम 89 प्रतिशत वोट मिले। उसके बाद डालमिया सीमेंट (भारत) और वेदांता समूह का स्थान रहा।

अदाणी को अधिग्रहण से क्या मिला : अदाणी को इस अधिग्रहण के बाद जेपी की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 3985 एकड़ जमीन के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 65 लाख टन की सीमेंट निर्माण क्षमता और जयप्रकाश वेंचर्स में 24 फीसदी हिस्सेदारी मिल जाएगी।

उसके अलावा जेपी के पास कई बड़ी रियल एस्टेट संपत्तियां है जिनमें ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स, जेवर एयरपोर्ट के पास जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी और एनसीआर, मसूरी और आगरा में कई होटल शामिल हैं।

57 हजार करोड़ के कर्ज भुगतान में चूकी थी कंपनी

रियल एस्टेट, सीमेंट विनिर्माण, होटल, बिजली और इंजीनियरिंग एवं निर्माण क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी जेएएल को पिछले साल जून में 57,185 करोड़ रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बाद दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया गया था। शेयरधारिता की बात करें तो प्रवर्तकों के पास 30.12 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, सार्वजनिक शेयरधारिता 69.88 फीसदी की है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक के पास 7.71 फीसदी हिस्सेदारी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास 8.57 फीसदी हिस्सेदारी है। जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर मंगलवार को 2.41 रुपये पर बंद हुए।

चांदी 6000 रुपये तेज, सोना चमका

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को कीमती धातुओं की कीमतों में दो प्रतिशत तक का उछाल आया।

चांदी 6,000 रुपये बढ़कर 2.62 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई जबकि सोना बढ़कर 1.61 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत 6,000 रुपये या 2.34 प्रतिशत बढ़कर 2,62,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने में लगातार तीन दिन की गिरावट का सिलसिला टूट गया।

नॉमिनी के बिना डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों में नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब नॉमिनी का विकल्प 'डिफॉल्ट' होगा। इसका मतलब है कि नॉमिनी जोड़े बिना ये खाते नहीं खोले जा सकेंगे। अगर कोई निवेशक नॉमिनी नहीं रखना चाहता तो उसे साफ तौर पर अलग से इसकी घोषणा करनी होगी।

इससे पहले सेबी ने जनवरी 2025 में नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था लेकिन इनमें कुछ संचालन संबंधी चुनौतियां सामने आई हैं। इसके चलते इन नियमों संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। सेबी ने इन बदलावों पर एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिस पर आम लोगों और अन्य हितधारकों से सात अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव मिलने के बाद सेबी अंतिम नियम तय करेगा।

सेबी के मुताबिक मौजूदा नियमों में कई निवेशक नॉमिनी नहीं बनाते या फॉर्म में पूरी जानकारी नहीं भरते। इसके कारण निवेशक की मृत्यु या किसी आपात स्थिति में निवेश दावे की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इन समस्याओं को कम करने और नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया को बैंकिंग नियमों के अनुरूप बनाने के लिए नियमों में ढील देने का प्रस्ताव रखा गया है।

क्या है प्रस्ताव

1. डीमैट या म्यूचुअल फंड खाता खोलते समय नॉमिनेशन को 'डिफॉल्ट विकल्प' बनेगा।
2. अब नॉमिनी की लंबी-चौड़ी जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। नॉमिनी का नाम और उनके साथ रिश्ता बताना होगा।
3. पता, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी अब वैकल्पिक होगी।
4. अब अधिकतम चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। पहले 10 की बात कही गई थी।
5. यदि निवेशक यह स्पष्ट नहीं करता कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो संपत्ति सभी नॉमिनी के बीच बराबर बांट दी जाएगी।
6. यदि कोई निवेशक नॉमिनेशन नहीं करना चाहता, तो उसे स्पष्ट रूप से एक 'घोषणापत्र' (डिक्लेरेशन) के जरिए इसकी पुष्टि करनी होगी।

PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः पीएसईबी हेड ऑफिस, द मॉल, पटियाला-147001
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U40109PB2010SGC033813
कार्यालयः मुख्य अभियंता/जीजीएसएसटीपी का कार्यालय
प्रापण प्रकोष्ठ-1, रुपनगर, फोन नं. 01881-275289

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

कार्यालय, मुख्य अभियंता/जीजीएसएसटीपी, प्रापण प्रकोष्ठ-1, रुपनगर द्वारा जीजीएसएसटीपी, रोपड़ के लिए पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क के लिए कंसलटेंसी के लिए इच्छुक पक्षों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है। कार्य क्षेत्र का विवरण हमारी वेबसाइट www.pspcl.in पर उपलब्ध है। जमा करने की अंतिम तिथि 01.04.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे है।

नोटः शुद्धिपत्र और संशोधन, यदि कोई हो तो उसे पीएसपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.pspcl.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

RO NO. 1079/12/2025/26/9571 आरटीपी-33/26

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मुरादाबाद
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)
रेलवे हरथला कालोनी, मुरादाबाद (उ.प्र.)
Website: www.kvmoradabad.ac.in, E mail-kvmbdup@gmail.com
दूरभाष: 0591-29740074, के.वि. संख्या 1382, सी.बी.एस.ई. संबद्धता संख्या: 2100071

फा. सं/2-44/ वित्त/निविदा / के.वि.सं/2025-26/945 दिनांक: 17.03.2026

फर्मो के पंजीकरण हेतु सूचना

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मुरादाबाद सत्र 2026-27 एवं 2027-28 के लिए विभिन्न सेवा/सेवायों एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु फर्म/ फर्मो के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है । विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय वेबसाइट https://no1moradabad.kvs.ac.in/ का अवलोकन करें ।

प्राचार्य

KALYAN SINGH SUPER SPECIALTY CANCER INSTITUTE
C.G. City, Sultanpur Road, Lucknow-226002
Website: https://cancerinstitute.edu.in, Email: jdmm.sscih@gmail.com

TENDER NOTICE

On-line offers are invited through Custom bid on GeM portal **GEM/2026/B/7358435 dated: 14-03-2026 for the item- Refrigerated Desk** from Original Equipment Manufacture/Direct Importers/ Authorized Distributors (declared by principal firm only) for the supply & installation of **Refrigerated Desk**.

The Vendors are required to submit their offers on GeM portal only in two bids system i.e. Technical and Financial bid as per norms of GeM Portal with terms and conditions as mentioned against bidding documents.

For more detailed information you may please visit the Gem portal **www.gem.gov.in** or our website **https://cancerinstitute.edu.in**, for reference only.

The Director reserves the right to accept or reject any tender in part or full without assigning any reason thereof.

Advt No. KSSSCI/Tender-31/2025-26 **Joint Director (MM)**

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मुरादाबाद
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)
रेलवे हरथला कालोनी, मुरादाबाद (उ.प्र.)
Website: www.kvmoradabad.ac.in, E mail-kvmbdup@gmail.com
दूरभाष: 0591-29740074, के.वि. संख्या 1382, सी.बी.एस.ई. संबद्धता संख्या: 2100071

फा. सं/2-44/ वित्त/निविदा / के.वि.सं/2025-26/947 दिनांक: 17.03.2026

निविदा सूचना

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मुरादाबाद सत्र 2026-27 एवं 2027-28 में विद्यालय बिल्डिंग रखरखाव और मरम्मत (Civil, Electric, Plumbing & Wooden) वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाएं निविदा आमंत्रित की जाती है । विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय में अथवा विद्यालय वेबसाइट https://no1moradabad.kvs.ac.in/ का अवलोकन करें।

प्राचार्य

उत्तर रेलवे

शुद्धिपत्र - I

वरि० मंडल विद्युत अभियंता / कोचिंग कार्यालय द्वारा जारी निविदा जो कि निम्नलिखित कार्य के लिए थी, जो कि दिनांक 07.04.2026 को 15:01 बजे खोली जानी थी, टेंडर दस्तावेजों में कुछ जोड़ने या हटाने के कारण, फर्म को रेलवे की वेबसाइट से टेंडर दस्तावेज़ डाउनलोड करने होंगे। अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

निविदा संख्या	30-विद्युत-10टी -कोचिंग- 2025- 26
कार्य का विवरण	दिल्ली मंडल के हजरत निजामुद्दीन डिपो के तहत, प्राइमरी-बेस्ड शताब्दी / तेजस / शताब्दी-टाइप / राजधानी / दुरंतो / गतिमान / AC / एक्सप्रेस ट्रेनों में, वॉशिंग लाइन / सिक लाइन पर रखरखाव कार्यों के दौरान और ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रिकल एस्कॉर्टिंग ड्यूटी के दौरान, AC कोचों के ताजी हवा और रिटर्न एयर फिल्टर, AC ग्रिल और कूलिंग / कंडेंसर कॉइल की सफाई का कार्य तीन साल की अवधि के लिए।

अनुमानित लागत (रू०)	बयाना राशि (रू०)	कार्य समापन की अवधि
12,18,74,697.01	7,59,400/-	36 महीने

संख्याः 30-विद्युत-10टी-कोचिंग-2025-26 दिनांक:17.03.2026 911/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

GOVERNMENT OF MEGHALAYA
**DIRECTORATE OF SPORTS AND YOUTH AFFAIRS
JAWAHARLAL NEHRU STADIUM COMPLEX
POLO GROUND, SHILLONG - 793001**

No. NGS.3/2026/107 **Dated: Shillong, the 17th March, 2026**

CORRIGENDUM - 01

Open Tender Enquiry for Development, Management and Maintenance of Website, State Sports & Youth Repository and Games Management System (GMS)

1. In reference to RFP floated by Directorate of Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya for Selection of Agency for Development, Management and Maintenance of Website, State Sports & Youth Repository and Games Management System for Department of Sports & Youth Affairs, Meghalaya vide reference no. NGS.3/2026/1 dated 25th February 2026 Tender ID 2026_DSYA_1936_1, please note the following amendments:-

Sl. No.	Clause Number	Existing Clause	Amended Clause
1.	Clause 1.5 SN. 13 (Data Sheet)	Last Date of Bid Submission: **23rd March 2026 12 noon**	Last Date of Bid Submission: **6th April 2026 17:00**
2.	Clause 1.5 SN. 14 (Data Sheet)	Opening of Technical Proposal: **23rd March 2026 13:00 hrs**	Opening of Technical Proposal: **7th April 2026 12 noon**

2. Rest of the terms and conditions mentioned in the RFP remain the same.

MIPR No.: 3095
Dated: 17-03-2026

Sd/- **Director**
Sports & Youth Affairs, Meghalaya, Shillong

GOVERNMENT OF MEGHALAYA
**DIRECTORATE OF SPORTS AND YOUTH AFFAIRS
JAWAHARLAL NEHRU STADIUM COMPLEX
POLO GROUND, SHILLONG - 793001**

No. NGS.4/2025/107 **Dated: Shillong, the 17th March, 2026**

CORRIGENDUM - 01

Open Tender Enquiry for Selection of Agency for Development and Management of Social Media Activities and Public Relations

1. In reference to RFP floated by Directorate of Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya for Selection of Agency for Development and Management of Social Media Activities and Public Relations for Department of Sports & Youth Affairs, Meghalaya vide reference no. NGS.4/2025/1 dated 25th February 2026 Tender ID 2026_DSYA_1934_1, please note the following amendments:-

Sl. No.	Clause Number	Existing Clause	Amended Clause
1.	Clause 1.5 SN. 13 (Data Sheet)	Last Date of Bid Submission: **20th March 2026 12 noon**	Last Date of Bid Submission: **6th April 2026 17:00**
2.	Clause 1.5 SN. 14 (Data Sheet)	Opening of Technical Proposal: **20th March 2026 13:00 hrs**	Opening of Technical Proposal: **7th April 2026 12 noon**

2. Rest of the terms and conditions mentioned in the RFP remain the same.

MIPR No.: 3096
Dated: 17-03-2026

Sd/- **Director**
Sports & Youth Affairs, Meghalaya, Shillong

संपादकीय जागरण

बुधवार, 18 मार्च, 2026 : चैत्र कृष्ण - 14 वि. 2082

अनुशासन के अभाव में जीवन दिशाहीन हो जाता है

राजनीतिक नौकरशाही

विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण अथवा उन्हें उनके वर्तमान पदों से हटाए जाने के चुनाव आयोग के फैसले से यही पता चलता है कि सरकारों और नौकरशाही में किस तरह मिलीभगत हो जाती है। चूंकि भाजपा शासित असम में भी अधिकारियों को हटाया गया है, इसलिए इस आरोप के लिए कोई स्थान नहीं बचता कि चुनाव आयोग एकतरफा कार्रवाई कर रहा है, पर ऐसे आरोप सामने आएंगे ही। बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बंगाल में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादलों को लेकर अपना गुस्सा संसद में निकाला। इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन तबादलों का भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन विपक्ष की चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने के आरोप लगाने की आदत हो गई है। वास्तव में इसी आदत के चलते तृणमूल कांग्रेस की अगुआई में विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की पहल की गई है। संकीर्ण राजनीति प्रेरित इस पहल से यह सच्चाई बदलने वाली नहीं है कि बंगाल उन राज्यों में अग्रणी है, जहां अनेक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते दिखते रहे हैं। इसके कई उदाहरण भी सामने आ चुके हैं। वास्तव में इसीलिए चुनाव आयोग को वहां के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी के साथ दर्जनों पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी हटाने पड़े हैं।

लोकसभा चुनाव के समय भी बंगाल में कई अधिकारियों को हटाया गया था। इनमें बंगाल के तत्कालीन डीजीपी भी थे। चुनाव बाद ममता बनर्जी ने उन्हें फिर से पुलिस प्रमुख बना दिया था। अभी हाल में उन्होंने उन्हें राज्यसभा भेजा। ऐसे मामले नए नहीं हैं। कई बार तो नौकरशाह इस्तीफा देकर या फिर वीआरएस लेकर सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। इस तरह के प्रसंग यही बताते हैं कि नौकरशाही का किस तरह राजनीतिकरण हो गया है। नौकरशाही के राजनीतिकरण के लिए किसी दल या सरकार विशेष को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इतना तो है ही कुछ राज्यों में यह हद से ज्यादा बढ़ गया है। नौकरशाही का राजनीतिकरण अथवा सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की ओर से नौकरशाहों के समक्ष अपने दल के सदस्य के तौर पर काम करने की परिस्थितियां पैदा करने से प्रशासनिक तंत्र का अवमूल्यन ही हो रहा है। यह ठीक नहीं कि जिन अधिकारियों से यह अपेक्षित होता है कि वे नियम-कानूनों के प्रति निष्ठावान रहें, वे जनता की सेवा करने के स्थान पर दल विशेष की सेवा करते दिखते हैं। जब ऐसा होता है तो शासन-प्रशासन की ओर से जनता के हितों की उपेक्षा ही होती है। नौकरशाही के राजनीतिकरण के लिए जितने जिम्मेदार नौकरशाह हैं, उतने ही राजनीतिक दल भी।

जानलेवा लापरवाही

उत्तरी दिल्ली के रूपनगर क्षेत्र में नजफगढ़ नाले पर बना पुल ढह जाने से महिला की मौत की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है, जब ये सामने आता है कि 33 वर्ष पहले बना ये पुल जर्जर हो चुका था और इसपर लोगों को आने-जाने से रोकने के लिए दोनों ओर बैरिकेड लगा दिए गए थे। इसके बावजूद, इस पुल से रोज बड़ी संख्या में लोग और स्कूली बच्चे गुजर रहे थे। ये गनीमत रही कि हादसे के समय पुल पर स्कूली बच्चे नहीं थे, अन्यथा और बड़ा हादसा हो सकता था।

> पुलों की जांच कराकर जो पुल जर्जर हो चुके हैं, उन्हें तत्काल पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए

दिल्ली सरकार ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर उसे इस हादसे की जांच सौंपी है और ऐसे अन्य पुलों के स्ट्रक्चरल आडिट के निर्देश दिए हैं, जो सर्वथा उचित है। लेकिन, प्रश्न ये भी उठते हैं कि नौ माह पूर्व जब इसे जर्जर घोषित किया गया था, तब इसे पूरी तरह बंद क्यों नहीं कर दिया गया? सिर्फ बैरिकेड लगाकर खानापूर्ति क्यों की गई? इसपर लोगों की आवाजाही क्यों जारी रही? इस तरह के हादसे रोकने के लिए पुलों की जांच कराकर जो पुल जर्जर हो चुके हैं, उन्हें तत्काल पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। दिल्लीवासियों को भी ये समझना चाहिए कि यदि किसी पुल को जर्जर घोषित कर दिया गया है तो उसका इस्तेमाल कतई न करें।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी का भाजपा प्रत्याशी बनना ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएगा?

आज का सवाल

क्या काबुल में अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक देशों के संगठन को पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए?

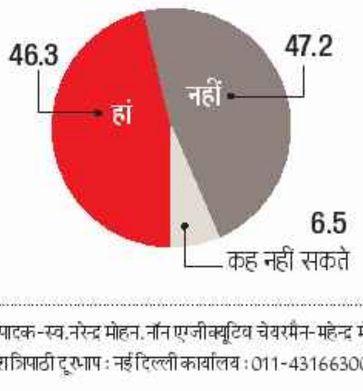

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अमेरिका को अराजक बनाते ट्रंप

निकोलस क्रिस्टोफ

ईरान पर हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन ही है, क्योंकि न तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी अनुमति दी और न ही आत्मरक्षा के लिए इसकी कोई आवश्यकता थी

कल्पना कीजिए कि ईरान अपने एजेंट मेक्सिको में उतार दे और वहां टेक्सास सीमा से वे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक मिसाइल दाग दें। भले ही उनकी ऐसी कोई मंशा न हो, लेकिन इस दौरान लापरवाही के चलते ऐसे हमले में कोई अमेरिकी स्कूल ध्वस्त हो जाए, जिसमें 175 जान गंवानी पड़ें। इसके बाद वे तेल डिपो को जलाने लग जाएं और लोगों को रासायनिक वर्षा का शिकार बनाएं। ऐसी स्थितियों में स्कूल, क्लिनिक और सामान्य जनजीवन ठप पड़ जाए और फिर भी ईरानी नेता धमकाएं कि अमेरिकी को इस हद तक तबाह कर देंगे कि वह कभी फिर से उठ खड़ा न हो पाए। निश्चित ही ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ हम सभी लोग निर्दोष नागरिकों पर हुए इस घृणित हमले को लेकर अपना आक्रोश प्रकट करेंगे और ऐसा करना बिल्कुल सही भी होगा।

युद्ध का परिदृश्य हमेशा त्रासद होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस त्रासदी ने और विकराल रूप ले लिया। तब अमेरिका ने अपनी मारक क्षमताएं दिखाईं कि महज कुछ ही घंटों के दौरान वह कैसे लाखों लोगों को काल के गाल में धकेल सकता है। युद्ध के बाद अपने दामन पर पड़े छींटों को साफ करने की मंशा से आत्ममंथन करते हुए अमेरिका ने ऐसे वैश्विक प्रयासों को लेकर पहल की, जिसमें युद्ध की विकरालता न बढ़े और खासतौर से आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। तब जिनेवा कन्वेंशन जैसे प्रोटोकाल के अतिरिक्त ऐसे अन्य अनेक उपाय किए गए कि युद्ध के दौरान पेयजल स्रोतों जैसे ढांचों को कतई निशाना न बनाया जाए, ताकि नागरिकों की परेशानी न बढ़े। हालांकि, सभ्यता-मानवता को पोषित करने वाली ऐसी परंपरा भी हाल के वर्षों में कई बार तार-तार हुई है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने नागरिकों के लिए बिजली की आपूर्ति तक काट दी। इससे हाड़ कंपाने वाली सर्दियां यूक्रेन के लोगों के लिए और बेरहम साबित होने लगी।

संयुक्त राष्ट्र आयोग के अनुसार इजरायल ने गाजा में फलस्तीन के लोगों को दाने-दाने के लिए तरसा दिया। उसने स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों तक पर भीषण बमबारी की और बच्चों को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया। संयुक्त अरब अमीरात ने सूडान में ऐसी मिलीशिया को शह दी, जिसने सामूहिक तुष्कर्मों और नरसंहार को अंजाम दिया। वहां पहले से ही मुश्किलें झेल रहे लोगों पर आफत की एक नई बारिश हो गई।

जहां तक गाजा की बात है तो वहां अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए जा रहे

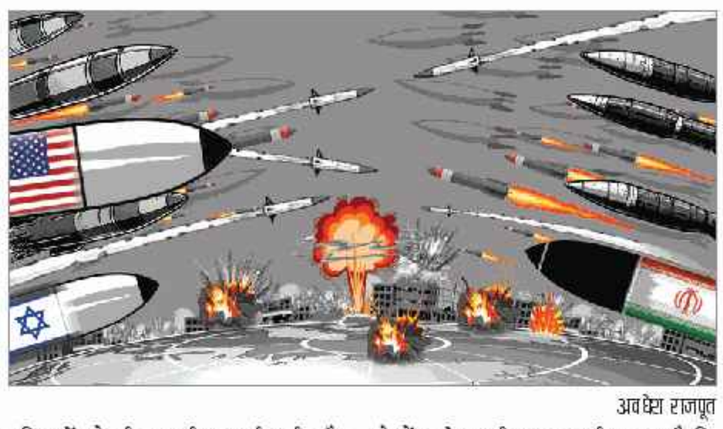

अवधेश राजपूत

हथियारों से ही तबाही मचाई गई और वाशिंगटन ने अपने सहयोगी की निंदा करने से भी परहेज ही किया। इसके बावजूद उसने आधे-अधूरे मन से ही सही, लेकिन वहां युद्ध के दौरान भी सामान्य तौर-तरीकों को कायम रखने की वकालत जारी रखी। जबकि ईरान के मामले में मुझे इस बात का डर है कि वह अपने इस रुख से भी पलट जाए तो कोई हैरत की बात नहीं। इस युद्ध में उन मूल्यों को ताक पर रखा जा सकता है, जिसके साथ सभी सभ्य देश खुद को बंधा हुआ देखते थे। वे मूल्य जो हमारी साझा मानवता को सहेजने के लिए बहुत जरूरी समझे गए हैं। ईरान पर हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ ही प्रतीत होता है, क्योंकि न तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी अनुमति दी है और न ही आत्मरक्षा के लिए इसकी कोई आवश्यकता थी। ईरान का आरोप है कि उसके उस संयंत्र को भी निशाना बनाया गया है, जिससे 30 गांवों को पेयजल की आपूर्ति होती थी। हालांकि अमेरिका और इजरायल ने इस आरोप को खारिज किया है। वहीं, ईरानी रेड क्रेसेंट सोसायटी का यह भी कहना है कि देश में 14 मेडिकल कालेज, 65 स्कूलों और 17,000 घर हमलों के शिकार बने हैं। वर्तमान परिदृश्य को लेकर यूनिसेफ का कहना है कि भिन्न-भिन्न देशों में छिड़ी लड़ाई के चलते अब तक 1,100 से अधिक बच्चे मारे गए हैं।

मैं इस बात को लेकर और अधिक चिंतित हूं कि अगर ट्रंप की हताशा बढ़ती गई और पहले से तय लक्ष्यों पर निशाने से उनके मंसूबे पूरे नहीं होते तो वे सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ग्रिड, हाईवे और पुलों जैसे नागरिक सुविधाओं से जुड़े ढांचों पर भी हमला कर सकते हैं ताकि ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इससे नागरिकों की मुश्किलें बढ़ेंगी और असंतोष भड़क सकता है। राष्ट्रपति और उनके आसपास जमा मंडली ने ऐसे इरादे जाहिर भी किए हैं। ट्रंप ने प्रेस से बाकायदा यह कहा है, 'अगर उन्होंने कोई दुस्साहस दिखाया तो उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उससे उबरने के लिए दुनिया में उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा।'

पूरी दुनिया यह देख रही है। जहां कुछ देशों ने ईरान पर हमले को सही बताया है तो उसका विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले को बेपरवाही से भरा और अवैध बताया है। स्विस रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिकी हमला अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री डोमिनिक डी विलेपिन ने अमेरिकी युद्ध को 'अवैध, अनैतिक, अप्रभावी एवं घातक' बताते हुए उस पर अंकुश की अपील की है। कुछ लोगों का तो यहां तक कि मानना है कि ट्रंप अमेरिका को दिशाहीन एवं अराजक देश बनाने पर तुले हैं।

ट्रंप के छेड़े इस युद्ध का विरोध करने के तमाम और भी व्यावहारिक कारण हैं। इससे ईरान की मुल्लाशाही का आधार दरकने के बजाय और मजबूत ही हुआ है। मोजतबा खामेनेई की ताजपोशी के रूप में हम एक ऐसे नेता को स्थापित करने का माध्यम बन गए जो अपने पिता की तुलना में कहीं अधिक कट्टर है। होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से तेल-गैस की कीमतों के चढ़ने के साथ ही उर्वरकों की आपूर्ति पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। जहां तक जानमाल की क्षति का सवाल है तो युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान दोनों जगह हालात और खराब होने की भरी-पूरी आशंका बढ़ गई है। इस युद्ध को बाद में इसके लिए भी याद किया जाएगा कि युद्ध की भयावहता और दुष्प्रभावों को घटाने के लिए एक समय जो प्रयास किए गए, वे कालांतर में कैसे मटियामेट हुए थे। ऐसा होता है तो मानवता ही उसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी होगी।

(लेखक 'द न्यूयार्क टाइम्स' के स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

राजनीति का दूसरा नाम अवसरवाद

राजीव सचान

राज्यसभा चुनावों ने फिर से यह दिखाया कि भारतीय राजनीति तेजी से विचारधारा विहीन होती जा रही है

क्रास वोटिंग करने वाली कांग्रेस विधायक सोफिया ● फाइल

राज्यसभा चुनावों में क्रास वोटिंग अब कोई नई-अनोखी बात नहीं। आम तौर पर हर बार राज्यसभा चुनावों में कहीं न कहीं क्रास वोटिंग देखने को मिलती है, अर्थात दल विशेष के विधायक किसी अन्य दल के प्रत्याशी को वोट देने का काम करते हैं। पहले क्रास वोटिंग के मामले यदा-कदा ही दिखते थे और वे प्रायः तब होते थे, जब विधायक अपने कार्यकाल के आखिरी चरण में होते थे, पर अब तो नए बने विधायक भी यह काम करने लगे हैं। क्रास वोटिंग करने का एक तरीका अपने दल या गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट ही न करना होता है। हाल में हुए राज्यसभा चुनावों में बिहार, ओडिशा और हरियाणा में क्रास वोटिंग देखने को मिली। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए पांच महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन यहां राजद के एक विधायक और कांग्रेस के तीन विधायकों ने महागठबंधन के स्थान पर राजग प्रत्याशी की राह आसान करना आवश्यक समझा। विडंबना यह रही कि महागठबंधन के बाहर के दलों बसपा और एआइएमआइएम के विधायकों ने तो उसके प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, पर उसके अपने ही लोग उसे गच्चा दे गए।

राजद इस पर कम दुखी हो सकता है कि उसके एक ही विधायक ने दगा किया, पर कांग्रेस क्या करे, जिसके छह में से तीन विधायकों ने वोटिंग करने की जरूरत नहीं समझी? मतलब आधी पार्टी परोक्ष रूप से दूसरे खेमे के साथ जाकर खड़ी हो गई। कांग्रेस इन विधायकों को निलंबित-निष्कासित कर सकती है, लेकिन उनकी विधायकी आसानी से नहीं जाने वाली। यदि वे विधायक बने रहते हैं तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजद के जिस विधायक ने वोटिंग न करके राजग प्रत्याशी को लाभ पहुंचाया, वे पहले जदयू में थे और उनके चुनाव परिणाम को भी चुनौती दी गई है। शायद उन्हें अदालती निर्णय के चलते अपनी विधायकी जाने का डर सता रहा हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह समझना कठिन होगा कि उसके आधे विधायकों ने दगा क्यों किया? आम तौर पर इसके दो ही कारण होते हैं-या तो पैसे का लालच या फिर अपनी पार्टी में अपना भविष्य न दिखना। कई बार दोनों ही कारण काम करते हैं। कांग्रेस को बिहार से ज्यादा बड़ा झटका ओडिशा में लगा। यहां उसके तीन विधायकों ने कांग्रेस और बीजद के साझा प्रत्याशी के स्थान पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया। इन विधायकों में सबसे अधिक चर्चा में रहीं-सोफिया फिरदौस। वह करीब दो वर्ष पहले हुए चुनाव में ओडिशा की पहली महिला मुस्लिम विधायक चुनी गई थीं। कांग्रेस ने सोफिया के साथ क्रास वोटिंग करने वाले रमेश जेना और दशरथ गोमांगो को निलंबित करते हुए कहा कि उनका भविष्य उज्ज्वल था, पर वे शायद ऐसा नहीं मान रहे थे। ओडिशा में कांग्रेस के साथ बीजद के भी आठ विधायकों ने क्रास वोटिंग की। यह बताता है कि नवीन पटनायक के सत्ता से बाहर होने के बाद बीजद अशक्त होती जा रही है।

क्रास वोटिंग हरियाणा में भी हुई, लेकिन यहां कांग्रेस झटका खाने के बाद भी लाज बचाने में सफल रही। यहां उसके पांच विधायकों ने क्रास वोटिंग की। उसके भाग्य से इसके बाद भी उसका प्रत्याशी जीत हासिल करने में सफल रहा। यहां कांग्रेस विधायकों के चार वोट अवैध भी पाए गए। यह जानना कठिन है कि इन चारों विधायकों को वोट देने का शऊर नहीं था या फिर वे अपने प्रत्याशी को वोट ही नहीं देना चाहते थे? जो भी हो, इस क्रास वोटिंग के बाद हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण उनकी विधायक पत्नी पर भी क्रास वोटिंग का आरोप बताया जा है।

हरियाणा में पहले भी राज्यसभा चुनावों में क्रास वोटिंग हो चुकी है और सही तरीके से वोट न देने के कारण वोट अमान्य भी किए जा चुके हैं। हरियाणा में ऐसा होना हैरानी की बात नहीं। यह वही राज्य है, जहां दलबदल को आयाराम-गयाराम की संज्ञा मिली थी। राज्यसभा चुनावों में पर्याप्त संख्याबल के बाद भी विरोधी दल या उसके समर्थित अथवा निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव जीतने का कारण राजनीतिक निष्ठा को ताक पर रखकर क्रास वोटिंग करना ही होता है। कई बार ऐसे प्रत्याशियों की जीत का सीधा कारण धनबल होता है। यह किसी से छिपा नहीं कि धन के सहारे वोट खरीदकर राज्यसभा चुनाव जीतने के मामले चर्चा में आते रहे हैं। ऐसी चर्चा की कभी पुष्टि नहीं हो पाती, लेकिन सब जानते हैं कि हर तरह के चुनावों और यहां तक कि सरकारों के विश्वासमत प्रस्ताव के समय भी धनबल की भूमिका देखने को मिलती रही है। यह भूमिका इसी कारण देखने को मिलती है, क्योंकि अब दलीय निष्ठा और राजनीतिक विचारधारा का कहीं कोई मूल्य नहीं रह गया है।

आम तौर पर हर नेता विचारधारा की दुहाई देते हुए ऐसे दावे करता है कि उसकी राजनीतिक लड़ाई वास्तव में विचारधारा का संघर्ष है, पर अब ऐसी बातें महज दिखावा हैं। इसी कारण हर तरह के चुनावों के समय पालाबदल होता है। विधानसभा या लोकसभा चुनाव करीब आते ही नेताओं में थोक में दलबदल करने की होड़ लग जाती है। हास्यास्पद यह है कि तब भी दलबदल करने वाले विचारधारा की दुहाई देते हैं। उनकी दलीय निष्ठा और विचारधारा रातोंरात बदल जाती है। चूंकि सभी दल पालाबदल यानी राजनीतिक अवसरवाद को प्रश्रय देते हैं, इसलिए भारतीय राजनीति धीरे-धीरे विचारधारा और राजनीतिक मूल्यों से विहीन होती जा रही है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वास्तविक सुख

मनुष्य सुख की तलाश में भटकता रहता है। कोई तीर्थों में सुख खोजता है, कोई संपत्ति और प्रतिष्ठा में तो कोई भौतिक विलासिता में। जब तक मनुष्य आत्मचेतना की ओर नहीं मुड़ता, तब तक उसकी यह खोज अधूरी ही रहती है। भारतीय आख्यानों में कस्तूरी मृग का उदाहरण प्रसिद्ध है। जंगल में रहने वाला मृग कस्तूरी की सुगंध से आकृष्ट होकर इधर-उधर दौड़ता है। वह नहीं जानता कि जिस सुगंध की तलाश में वह भटक रहा है, वह उसकी अपनी ही नाभि में स्थित है। मनुष्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वह सुख, शांति और आनंद को बाहर खोजता है, जबकि उसका वास्तविक स्रोत उसके अपने अंतर्मन में है।

संसार में असंख्य साधक ध्यान के माध्यम से परमात्मा की खोजते हैं। साधना आवश्यक है, पर यदि खोज केवल बाहरी रूपों तक सीमित रहे तो लक्ष्य तक पहुंचना कठिन हो जाता है। परम सत्य कहीं दूर नहीं, वह हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित है। जबकि मनुष्य भौतिक भोगों में ही सुख खोजता है। निश्चय ही उनमें क्षणिक आनंद का आभास मिलता है, पर स्थायी सुख वहां संभव नहीं। वास्तविक सुख का उद्गम संयम, संतुलन और त्याग में है। संयम जीवन को अनुशासित करता है और मन को शांति प्रदान करता है। विडंबना यही है कि मनुष्य इस सत्य को जानते हुए भी उसे व्यवहार में नहीं उतारता। वह संयम की प्रशंसा तो करता है, पर जीवन में असंयम को ही स्थान देता है। परिणामस्वरूप वह असंतोष और दुख के चक्र में उलझा रहता है।

आज दुनिया में बाहरी उपलब्धियों की चमक बढ़ी है, परंतु भीतर की शांति घटती जा रही है। सुख की तलाश जितनी तेज हुई है, उतनी ही बेचैनी भी बढ़ी है। यह स्थिति हमें उसी पड़ाव की ओर ले जाती है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। उसे पाने का मार्ग आत्मचिंतन, संयम और संतुलित जीवन से होकर गुजरता है। यही जीवन की सच्ची ऊर्जा है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

ट्रंप के रवैये पर उठते सवाल

'मुश्किल में ट्रंप' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में समकालीन परिस्थितियों को उचित ही रेखांकित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कठिन स्थिति बन गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनके फैसलों को अपेक्षित अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप द्वारा मित्र देशों से सहयोग की अपेक्षा की गई थी, लेकिन जापान, आस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की सीमित या सशर्त प्रतिक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि अब अमेरिका के सहयोगी देश भी बिना सोचे-समझे उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। खासकर जर्मनी द्वारा नाटो को इस संघर्ष से दूर रखने की बात ने यह संकेत दिया है कि वैश्विक मंच पर ट्रंप का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। ट्रंप की विदेश नीति अक्सर आक्रामक और एकतरफा मानी जाती रही है। ईरान के साथ तनाव बढ़ाने, वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप करने और अंतरराष्ट्रीय समझौतों से हटने जैसे कदमों ने अमेरिका की छवि को प्रभावित किया है। होर्मुज जलमार्ग में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। किसी भी वैश्विक शक्ति के लिए केवल सैन्य बल या दबाव की राजनीति पर्याप्त नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विश्वास और संतुलित कूटनीति ही स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

himanshushekhar.mca@gmail.com

सरकारी स्कूलों में पढ़ें सभी

शिक्षा के क्षेत्र मे केंद्र सरकार ने पीएमश्री स्कूल खोलने के बाद हरियाणा सरकार ने गरीबों के बच्चों के लिए सीएमश्री स्कूल खोलने की घोषणा की है, जो एक सराहनीय व गरीबों के लिए एक आशा की किरण है। सरकारी नौकरी के लिए निम्न आय से लेकर मध्यम आय वाले प्रत्येक परिवार अपनी खून-पसीने की कमाई से अपने बच्चों को निजी स्कूल मे पढ़ाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, परंतु वर्तमान मे प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों से प्रत्येक परिवार का विश्वास क्यों उठा हुआ है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए सभी को सरकारी कालेज ही चाहिए। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने मे इलाहाबाद उच्च न्यायलय के आदेश को अमल में लाया जाए तो किसी भी सरकार को न तो अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी और न किसी भी सरकारी स्कूल को कोई विशेष दर्जा देने की आवश्यकता होगी। उच्च न्यायलय ने अपने एक आदेश मे कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों अर्थात सबसे छोटे सरकारी कर्मचारी से लेकर सर्वोच्च सरकारी अधिकारी व ग्राम प्रधान से लेकर सभी संसद सदस्यों के बच्चे सरकारी स्कूल मे पढ़ेंगे तो पुरे देश के सभी सरकार स्कूलों की रातोंरात काया पलट जाएगी। इस तरह का नियम बन जाने से किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि देश के स्कूलों की एक यूनिफार्म हो और एक ही पाठ्यक्रम हो, यह सब स्वतः ही हो जायेगा।

प्रेमपाल सिंह, मोहन नगर पलवल

आपदा में अवसर

इस समय विश्व में अनेकों स्थान पर युद्ध चल रहा है। लगभग सभी देशों में पेट्रोल-डीजल के दामों में असाधारण वृद्धि हुई है। भारत शायद एक मात्र देश है, जहां न इन वस्तुओं की कोई किल्लत है न ही दाम बढ़े हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता का प्रतीक है। निवेशक सदैव ऐसे स्थान का ही चयन करते हैं। फिर यहां लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, उत्तम कानून व्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। सस्ते श्रम एवं उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता है। स्थिर राजनीतिक स्थिति है। सामान्यतः 12 लाख रुपए तक और नौकरीपेशा के मामले में 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कर न लगने के कारण कुल क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। जीएसटी में बड़ी कटौती से काफी वस्तुए सस्ती हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के शासन काल में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जिनकी वजह से बाजार को और विस्तार मिला है। एक नवीनतम रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हुआ है कि 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्ष से अधिक खरीदारी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसाफ्ट के सीईओ ने घोषणा की है कि वह 17.5 अरब डालर यानी लगभग 1,45,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश भारत में करने जा रहे हैं। यह राशि लगभग उस राशि के बराबर है, जितनी राशि एक माह में भारत में जीएसटी के रूप में एकत्र होती है। मोदी देशहित में हर संभव अवसर तलाशने वाले हैं।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

पोस्ट

इतिहास और भूगोल इसके साक्षी हैं कि छिटपुट लड़ाइयां जीतने के बाद भी बड़े युद्ध में हार संभव है।

वेलिना@vtchakarova

पाकिस्तान इन दिनों अफगानिस्तान में जो कर रहा है, वह नरसंहार से कम नहीं। हिना यूसुफजई@xhinax

वैसे तो पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के मानक पहले से ही बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन काबुल में अस्पताल पर हमला उन मानकों से भी गया-गुजरा है।

नितिन पई@acorn

हम एक ऐसे त्रासद दौर में जी रहे हैं, जहां स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी करना सामान्य बात बन गई है। मानवता का इससे अधिक और पतन नहीं हो सकता।

निधि राजदान@Nidhi

रमजान के महीने में पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश अफगानिस्तान में मुसलमानों को ही मार रहा है। उम्मा इस पर आंखें मूंदे हुए है। इस्लामिक देशों के संगठन से लेकर उलमा तक सभी खामोश हैं। ऐसा पाखंड क्यों?

जहक तनवीर@ZahackTanvir

जनपथ

सीढ़ी पर वे बैठकर खाते बिस्कुट चाय,
संसद में हुड़दंग हित खोजें नया उपाय।
खोजें नया उपाय करें जिससे हंगामा,
बैठ सदन में आप सिर्फ करते हैं ड्रामा।
क्या सीखेगी दोस्त देखकर यह नवपीढ़ी,
नौटंकी का मंच बनी संसद की सीढ़ी!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 242

मोजतबा खामेनेई ने ठुकराया युद्धविराम का प्रस्ताव, कहा- अमेरिका और इजरायल पहले हार मानें

तेहरान, रायटर: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने की कूटनीतिक कोशिशें फिलहाल बेअसर होती दिख रही हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ तनाव घटाने या युद्धविराम से जुड़े प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के अनुसार ये प्रस्ताव दो मध्यस्थ देशों के जरिए तेहरान पहुंचाए गए थे, लेकिन खामेनेई ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर नहीं लाया जाता, तब तक शांति पर बातचीत का समय नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम लीडर के रूप में चयन के बाद विदेश नीति पर हुई अपनी पहली उच्चस्तरीय बैठक में मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बहुत कठोर और गंभीर प्रतिशोध का रुख अपनाया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वह बैठक में स्वयं मौजूद थे या दूरस्थ माध्यम से जुड़े थे।

मोजतबा खामेनेई ● फाइल फोटो

ट्रंप प्रशासन ने भी ठुकराई थी मध्यस्थता: सूत्रों के अनुसार 14 मार्च को पश्चिम एशियाई सहयोगी देशों ने युद्ध समाप्त कराने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संवाद शुरू कराने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे स्वीकार नहीं किया।

ऊर्जा संकट गहराया, सहयोगी देशों ने दूरी बनाई: होर्मुज जलडमरूमध्य अब भी लगभग बंद स्थिति में है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से समुद्री मार्ग खुलवाने में मदद मांगी थी, लेकिन कई यूरोपीय देशों ने प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी से इन्कार कर दिया है।

'ईरान से नहीं था खतरा', कहकर ट्रंप के शीर्ष अधिकारी ने दिया इस्तीफा

वाशिंगटन, रायटर: ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले से नाखुश शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने मंगलवार को ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और ताकतवर अमेरिकी युद्ध लाबी के हाथों की 'कठपुतली' बने हुए हैं। केंट ने ट्रंप को भेजे अपने इस्तीफे में साफ कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था और वह इस युद्ध का नैतिक रूप से समर्थन नहीं कर सकते। केंट के इस्तीफे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि वह बहुत कमजोर अधिकारी थे और उन्होंने इस्तीफा देकर बहुत अच्छा किया है।

केंट ने ट्रंप को संबोधित अपने पत्र और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखे संदेश में आरोप लगाया कि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल और उससे जुड़े प्रभावशाली अमेरिकी लाबी के दबाव में उतरा। उन्होंने लिखा कि ''यह स्पष्ट है कि हमने यह युद्ध दबाव में शुरू किया और मेरी अंतरात्मा अब इसका समर्थन करने की अनुमति नहीं देती।''

व्हाइट हाउस और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की ओर से देर शाम तक इस इस्तीफे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। केंट को गबार्ड का करीबी माना जाता रहा है व जुलाई 2025 में सीनेट की मंजूरी के बाद उन्हें एनसीटीसी प्रमुख बनाया गया था।

जोसेफ केंट ● फाइल/एपी

- अमेरिका के नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट ईरान युद्ध को लेकर जताई नाराजगी
- केंट बोले, नहीं कर सकते युद्ध का नैतिक समर्थन, इजरायल और ताकतवर लाबी ने ट्रंप को उलझाया

इस्तीफे में केंट ने कहा कि ट्रंप ने 2016, 2020 और 2024 के चुनाव अभियानों में ''अमेरिका फर्स्ट'' विदेश नीति का समर्थन किया था, जिसमें पश्चिम एशिया के लंबे युद्धों से दूरी बनाए रखने की बात कही गई थी। उन्होंने लिखा कि जून 2025 तक ट्रंप स्वयं पश्चिम एशिया के युद्धों को ऐसा जाल बताते थे, जिसने अमेरिका की संपदा और सैनिकों की जान दोनों को नुकसान पहुंचाया। केंट ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन के भीतर कुछ उच्चस्तरीय इजरायली संपर्कों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली वर्ग ने ऐसा माहौल बनाया, जिससे युद्ध-पूर्व मानसिकता तैयार हुई। उनके अनुसार राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाया गया कि सैन्य कार्रवाई त्वरित और आसान सफलता देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी कानून और युद्ध संबंधी संवैधानिक परंपरा के अनुसार किसी बड़े सैन्य अभियान के लिए ''इमिनेंट थ्रेट'' यानी तात्कालिक खतरे का स्पष्ट आधार महत्वपूर्ण माना जाता है।

युद्ध के 18वें दिन ईरान को फिर तगड़ा झटका, इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से मचा हड़कंप

सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत का दावा

ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी (बाएं) व बसीज फोर्स के कमांडर जनरल गुलामरेजा सुलेमानी (दाएं) की मौत का दावा करती इजरायल डिफेंस फोर्सेज की एक्स पोस्ट ● इंटरनेट मीडिया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के 18वें दिन ईरान को तगड़ा झटका लगा। इजरायल ने दावा किया कि सोमवार रातभर चली कार्रवाई में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और अर्धसैनिक बसीज फोर्स के कमांडर जनरल गुलामरेजा सुलेमानी मारे गए।

ईरान की तरफ से दोनों के ही न तो मारे जाने की पुष्टि की गई है और न ही दावे का खंडन किया गया है। लारीजानी को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद ईरान का सबसे ताकतवर नेता माना जाता था। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से लेकर युद्ध की रणनीति तक पर्दे के पीछे से सबकुछ लाराजानी ही तय कर रहे थे। यहां तक कि वह राष्ट्रपति से भी मजबूत हो गए थे।

प्रेट्र के अनुसार, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लारीजानी के मारे जाने का दावा करते हुए कहा कि इजरायल ईरान के नेतृत्व को कमजोर कर रहा है ताकि लोग इस अवसर का फायदा उठाएं और सरकार को उखाड़ फेंकें। ये काम एक बार में नहीं होगा और आसानी से भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम लगातार जुटे रहे तो हम ईरानी जनता को अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने का मौका प्रदान करेंगे।

रायटर के अनुसार, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि हम अब भी ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाने की रणनीति पर कायम हैं। इजरायली सेना ने भी अलग बयान में कहा कि हमले में सुलेमानी समेत 300 बसीज कार्यकर्ता मारे गए। रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े बसीज फोर्ज पर ईरान में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कठोर बल प्रयोग, व्यापक गिरफ्तारियां और नागरिकों पर हिंसा का आरोप है। आइडीएफ ने बताया कि बसीज फोर्स ने तंबू में अपना अस्थायी मुख्यालय बना रखा था।

इजरायली हवाई हमले के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगर में उठता धुएं का गुबार ● एपी

राष्ट्रपति पेजेशकियान से भी ज्यादा प्रभावशाली थे लारीजानी

न्यूयार्क टाइम्स से

न्यूयार्क: अली लारीजानी पिछले कुछ सप्ताह से ईरान की सत्ता के सबसे प्रभावशाली चेहरों में उभरकर सामने आए थे। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की अमेरिकी-इजरायली हमलों में मौत के बाद लारीजानी ने व्यवहारिक रूप से देश की रणनीतिक कमान संभाल ली थी। वे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख होने के साथ युद्ध, आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति के प्रमुख निर्णयों के केंद्र में थे। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की रूपरेखा तैयार करने और संभावित युद्धकालीन प्रशासनिक ढांचे पर भी उनकी सीधी पकड़ थी।

खामेनेई के करीबी विश्वस्त माने जाने वाले 67 वर्षीय लारीजानी ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आक्रामक रुख अपनाया और लगातार इंटरनेट मीडिया पर कड़े संदेश जारी किए। खामेनेई के उत्तराधिकारी बनने की अटकलों के बावजूद वे सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते थे, क्योंकि वे वरिष्ठ शिया धर्मगुरु नहीं थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की तुलना में लारीजानी को अधिक प्रभावशाली माना जाने लगा था। इंटरनेट प्रतिबंधों जैसे फैसलों में भी अंतिम सहमति उन्हीं से लेनी पड़ रही थी। इससे स्पष्ट हुआ कि युद्धकाल में वास्तविक शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति भवन नहीं, बल्कि सुरक्षा परिषद बन चुकी थी। वे प्रसिद्ध लारीजानी परिवार से आते थे, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक अमेरिका के केनेडी परिवार जैसी राजनीतिक हैसियत वाला मानते हैं। उनके भाई सादिक लारीजानी न्यायपालिका के प्रमुख रह चुके हैं, जबकि मोहम्मद जवाद लारीजानी विदेश नीति मामलों में सुप्रीम नेतृत्व के करीबी सलाहकार रहे।

ईरान ने इजरायल और यूएई पर बढ़ाए हमले, लेबनान में भीषण हुई लड़ाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के 18वें दिन ईरान ने इजरायल को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई खेप लांच की, तो इजरायल ने भी ईरान और लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भीषण हमले किए। ईरान ने खाड़ी के पड़ोसी देशों के ऊर्जा ढांचों पर हमला किया।

रायटर के अनुसार, यूएई के फुजैराह तेल ठिकाने समेत अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरानी हमले जारी रहे। चार दिनों में तीसरी बार फुजैराह तेल ढांचे पर हमले हुए। इंटरसेप्ट की गई ईरानी मिसाइल का मलबा अबू धाबी के बानी यास क्षेत्र में गिरा, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति (पाकिस्तानी) की मौत हो गई। यूएई में मरने वालों की संख्या आठ पहुंच गई है। ड्रोन हमले में अबू धाबी के शाह गैस फील्ड में आग लग गई। ईरानी संसद प्रमुख मोहम्मद बघेर कलीबाफ ने कहा कि हमले करना मजबूरी है क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

सऊदी अरब ने भी देश के पूर्वी प्रांत में दर्जनों ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। इस प्रांत में तेल के बड़े ढांचे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरानी मिसाइल हमले को विफल किया गया। एक राकेट को भी मार गिराया गया, जिसके मलबे से औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई। कुवैत में मिसाइल का मलबा एक एंबुलेंस पर गिरा, जिसमें दो चिकित्साकर्मी घायल हुए।

- यूएई के फुजैराह तेल ढांचे पर चार दिन में तीसरी बार हमला
- इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के हथियार भंडार पर किया हमला

बगदाद में हमले को अमेरिकी दूतावास की वायुरक्षा प्रणाली द्वारा नष्ट किए जाने के बाद मलबे से उठता धुआं ● रायटर

इराक में ईरान समर्थित विद्रोही गुट ने बगदाद के अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला किया, जिसे इंटरसेप्ट किया गया। इसका मलबा दूतावास पर गिरा।

एएनआइ के अनुसार, इजरायली सेना ने तेहरान के साथ-साथ गाजा और दक्षिणी लेबनान में हमले किए। गाजा पट्टी में दो फलस्तीनी मारे गए। दक्षिणी लेबनान के कफरा क्षेत्र में हिजबुल्ला के बड़े भूमिगत हथियार भंडार पर इजरायली सेना ने हमला किया। इजरायल का दावा है कि वहां क्रूज मिसाइलें व सैकड़ों राकेट जमा थे।

ईरान ने चहारशनबे सूरी त्योहार से पूर्व बड़ा अभियान चलाते हुए जासूसी के शक में 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कुल 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, सैकड़ों की संख्या में स्टारलिंक कंपनी के इंटरनेट सिस्टम भी जब्त किए गए हैं।

जल्द खत्म करेंगे ईरान युद्ध, नाटो के रवैये से नाखुशी : ट्रंप

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, ईरान पर अब तक 15 हजार से ज्यादा हमले करने का दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा करना मेरी जिम्मेदारी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने ईरान युद्ध को जरूरी बताया। होर्मुज जलमार्ग में तेल टैंकरों को सुरक्षा देने के लिए अपने युद्धपोत भेजने के मुद्दे पर नाटो देशों के पीछे हटने पर ट्रंप ने कहा कि वे बहुत मूर्खतापूर्ण गलती कर रहे हैं। हम इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए झटके से कम नहीं है। ट्रंप ने कहा कि कुछ देश मदद के लिए आ रहे हैं। हम अपने नाटो सहयोगियों की पूरी मदद करते हैं। हमारे 45 हजार सैनिक जापान में हैं, 45 हजार दक्षिण कोरिया में हैं। 40 से 50 हजार सैनिक जर्मनी में हैं। हम इन सभी देशों की रक्षा करते हैं।

मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से की बात, होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर दिया जोर

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित व निर्बाध आवाजाही के महत्व पर सहमति जताई। मोदी ने इस टेलीफोन वार्ता के दौरान खाड़ी देशों पर हुए सभी हमलों की कड़ी निंदा की और यूएई के नेता के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए कार्य करने पर सहमति जताई। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मैंने यूएई के राष्ट्रपति नाह्यान से बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। हमने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की।' मोदी ने नाह्यान के साथ बातचीत में दोहराया कि भारत यूएई पर हुए सभी हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनमें लोगों की जान गई और आम लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा- 'हम इस बात पर सहमत हुए कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। हमने यह भी तय किया कि पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति, सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने के लिए वे मिलकर काम करते रहेंगे।' अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से यह दूसरी बार है जब मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत की है।

यूएई के राष्ट्रपति व पीएम मोदी ●

अमेरिका को चेताया, ईरान को 'घायल' छोड़ देना होगी बड़ी भूल

दुबई, रायटर: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच खाड़ी देशों का रुख तेजी से बदलता दिख रहा है। खाड़ी क्षेत्र के कई प्रभावशाली देशों ने अमेरिका से साफ कहा है कि यदि सैन्य अभियान शुरू किया गया है तो उसे बीच में रोकना रणनीतिक भूल होगी। ट्रंप भी बार-बार कह रहे हैं कि वह जल्दी युद्ध खत्म करेंगे। इससे खाड़ी के अमेरिकी सहयोगियों में आशंका गहराने लगी है। सूत्रों के अनुसार, खाड़ी देशों ने सीधे युद्ध की मांग नहीं की थी, अब उनका मानना है कि ईरान को इतना कमजोर किया जाए कि वह दोबारा क्षेत्रीय ऊर्जा ढांचे को निशाना न बना सके।

ईरान युद्ध पर मेरे और ट्रंप के बीच मतभेद नहीं : वेंस

वाशिंगटन, एएनआइ: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान युद्ध को लेकर किसी भी तरह के मतभेद से साफ इन्कार किया है। वह पश्चिम एशिया के संदर्भ में अपनी पिछली टिप्पणियों को लेकर मीडिया के सवाल पर बिफर गए और कहा कि आप मेरे और राष्ट्रपति के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ट्रंप प्रशासन विदेश नीति मामले में एकमत है।

जेडी वेंस

वेंस सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति से पश्चिम एशिया को लेकर उनके पिछले बयानों के बारे में पूछा गया। वह इन सवालों को टालते हुए कहा, 'आप प्रशासन के सदस्यों के बीच, मेरे और राष्ट्रपति के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति 2015 से कहते आ रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और मैं उनसे सहमत हूं।' सीएनएन के अनुसार, वेंस ने कहा, 'हमारे पूर्व के राष्ट्रपतियों की अपेक्षा ट्रंप काफी स्मार्ट राष्ट्रपति हैं। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा है'

पूर्व में ऐसा रहा रुख: सीएनएन के अनुसार, ट्रंप प्रशासन से जुड़ने से पहले वेंस ने कहा था कि अमेरिका को विदेशी संघर्षों में शामिल नहीं होना चाहिए।

ट्रंप का दावा, ईरान पर हमला नहीं करने के लिए एक पूर्व राष्ट्रपति ने खुद जताया खेद

न्यूयार्क टाइम्स से

वाशिंगटन: राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक पूर्व राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला नहीं करने को लेकर खेद जताया है। एक पूर्व राष्ट्रपति ने निजी तौर पर कहा, 'काश मैंने भी वही किया होता जो आपने किया।' यह बात ईरान पर हमले और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने के संदर्भ में कही। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह चार जीवित पूर्व राष्ट्रपतियों में से किसका जिक्र कर रहे हैं। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति का नाम यह कहकर उजागर नहीं किया कि वह उनको किसी परेशानी में डालना नहीं चाहते। जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वह पूर्व राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश हैं, जो रिपब्लिकन हैं। इस पर ट्रंप ने नहीं में जवाब दिया। चार जीवित पूर्व राष्ट्रपतियों में बुश के अलावा बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और जो बाइडन हैं।

सभी को हेल्थ इंश्योरेंस में लाना सरकार की प्राथमिकता : निर्मला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वर्ष 2033 तक देश के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता है। यह काम ग्रामीण इलाके को कवर किए बगैर संभव नहीं हो सकता। इसलिए, सरकार ने 25,000 ग्राम पंचायतों तक हेल्थ इंश्योरेंस को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाना चाहती है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने 2024 में अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत इंश्योरेंस कवरेज के लिए ग्राम पंचायत को आधारभूत यूनिट माना जाएगा। ग्रामीण इलाके और गरीबों से जुड़े हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को सस्ता बनाने पर भी सरकार ध्यान दे रही है। सीतारमण ने कहा कि हमारे देश में सभी प्रकार के इंश्योरेंस का दायरा बढ़ तो रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर से हमारा इंश्योरेंस एरिया काफी पीछे हैं।

निर्मला सीतारमण

'किसी भी चुनौतियों से निपटने में भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना का ही नतीजा है कि आज देश किसी भी अनिश्चित चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर को लेकर मंगलवार को संसद में उठाए गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू स्तर पर इस संकट से देश को कोई गंभीर खतरा नहीं है। सरकार ने अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत खर्च के लिए 12.20 लाख करोड़ का प्रविधान किया है, जिससे विकास गति कायम रखने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा संकट को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। वर्ष 2014 के मुकाबले देश में बिजली का उत्पादन दोगुना हो चुका है। एलपीजी का उत्पादन भी घरेलू स्तर पर बढ़ाया जा रहा है।

सरकार ने सार्थक वार्ता के लिए बढ़ाया हाथ : सोनम वांगचुक

नई दिल्ली, प्रेट्र : जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद लद्दाख के प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार के कदम को 'दोनों पक्षों की जीत' बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन पर से रासुका हटाना विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनके अनुसार, सरकार ने लद्दाख के लोगों के साथ सार्थक और रचनात्मक बातचीत शुरू करने के लिए हाथ बढ़ाया है।

सार्थक संवाद की पहल: वांगचुक ने स्पष्ट किया कि लद्दाख में हो रहे सभी आंदोलनों का एकमात्र उद्देश्य सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करना था। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आमतौर पर लोग हथियार उठाते हैं और सरकार बातचीत की अपील करती है, लेकिन यहां जनता सरकार से संवाद के लिए आग्रह कर रही है।

अपनी अगली रणनीति पर चर्चा करते हुए वांगचुक ने बताया कि वे जल्द ही लद्दाख जाकर लेह एपेक्स बाडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के नेताओं से परामर्श करेंगे। उन्होंने फिर से अनशन पर बैठने की इच्छा से इन्कार किया।

एके-47 से लैस आतंकियों से संपर्क, ड्रोन आपरेशन का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआइए अदालत ने म्यांमार में सक्रिय उग्रवादी समूहों से संपर्क, हथियार सप्लाई और ड्रोन आपरेशन में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार सात विदेशी नागरिकों को 11 दिन की एनआइए हिरासत में भेज दिया है। इनमें छह यूक्रेन के नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने पारित किया। एनआइए ने 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने 27 मार्च तक 11 दिन की हिरासत मंजूर की। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और ये सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को प्रभावित करते हैं। कोर्ट ने माना कि मामला सामान्य नहीं है और प्रथम दृष्टया यूएपीए की धारा 18 लागू होती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अब तक पर्याप्त प्रगति हुई है। केस डायरी के आधार पर अदालत ने माना कि आगे की कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एफआइआर दर्ज करने या जांच प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है और प्रारंभिक पूछताछ में सीमा पार साजिश के संकेत मिले हैं।

- म्यांमार साजिश मामला : अमेरिकी नागरिक समेत सात विदेशी एनआइए हिरासत में
- मिजोरम के रास्ते म्यांमार पहुंच उग्रवादियों को दी ट्रेनिंग, अंतरराष्ट्रीय साजिश की जांच

ये हैं आरोपित: गिरफ्तार आरोपितों में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरान वैन डाइक और यूक्रेन के नागरिक हुरबा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफानकिव मारियन, होन्चारुक मक्सिम और कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं।

एनआइए के अनुसार, आरोपित सीधे तौर पर एके-47 राइफल से लैस आतंकियों के संपर्क में थे व गतिविधियों में सहयोग कर रहे थे। एजेंसी का आरोप है कि आरोपित म्यांमार में सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन संचालन, हथियारों के इस्तेमाल और सैन्य प्रशिक्षण दे रहे थे। ये समूह भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी संगठनों से जुड़े हैं।

गुजरात में विवाह, तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए समान कानूनी ढांचे की सिफारिश

गांधीनगर, प्रेट्र : गुजरात सरकार द्वारा राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के संबंध में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से अब बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यूसीसी पर ड्राफ्ट बिल पेश किए जाने की संभावना है।

समिति अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई ने सीएम को रिपोर्ट सौंपते समय प्रस्तुति दी। समिति अध्यक्ष ने कहा- रिपोर्ट में विवाह, तलाक, विरासत व गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों व समुदायों के लिए एक सामान्य कानूनी ढांचे का सुझाव दिया गया है। खासकर महिलाओं के समान अधिकार व सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार 25 मार्च को यूसीसी पर ड्राफ्ट बिल विधानसभा में पेश कर सकती है। सरकार ने पिछले वर्ष फरवरी में पैनल गठित किया था।

- यूसीसी पर पैनल ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, विधानसभा में जल्द पेश होगा ड्राफ्ट बिल
- महिलाओं के समान अधिकार और सुरक्षा को दी गई है रिपोर्ट में प्राथमिकता

महाराष्ट्र में अब धोखाधड़ी करके नहीं कराया जा सकेगा मतांतरण

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र विधान परिषद ने मंगलवार को फ्रीडम आफ रिलीजन बिल-2026 पारित कर दिया। विधानसभा ने सोमवार को ही इसे स्वीकृति दे दी थी। इसमें जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के जरिये मतांतरण पर रोक लगाने के कड़े प्रविधान हैं। अब यह विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस व सपा ने विरोध किया।

विधेयक के अनुसार, शादी का झांसा देकर गैरकानूनी तरीके से मतांतरण कराने वालों को सात वर्ष की जेल व एक लाख जुर्माना देना होगा। यह विधेयक लालच, गलत जानकारी, बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या धोखाधड़ी वाले तरीके से किए गए मतांतरण पर रोक लगाता है। इसमें प्रविधान है कि मतांतरण के इरादे की जानकारी देते हुए सक्षम अथारिटी को पहले से नोटिस देना होगा। मतांतरण करने वाले व मतांतरण कराने वाली संस्था को मतांतरण के बाद सक्षम अथारिटी के समक्ष घोषणा करना अनिवार्य होगा। गैरकानूनी मतांतरण की जांच सब-इंस्पेक्टर या ऊपर के पुलिस अधिकारी से कराने का प्रविधान है। इसमें गैरकानूनी मतांतरण के शिकार लोगों को राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास में मदद व बच्चों के गुजारे भत्ते व कस्टडी का भी प्रविधान है।

चिंतन

पहले अपने घर को दुरुस्त करे कांग्रेस

तकनीक
प्रमोद भार्गव

राज्यसभा चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि संगठन, अनुशासन और नेतृत्व की असली परीक्षा भी होती है। इस बार के चुनावों में जो तस्वीर उभरकर सामने आई है, उसने कांग्रेस की आंतरिक कमजोरियों को न सिर्फ उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि पार्टी अभी उस मजबूती से काफी दूर है, जो कभी इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा के दौर में देखने को मिलती थी। हरियाणा, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में जो घटनाक्रम सामने आया, वह केवल चुनावी हार-जीत की कहानी नहीं है, बल्कि संगठनात्मक बिखराव की गंभीर चेतावनी है। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा अपेक्षाकृत कम चर्चित उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध को मैदान में उतारना ही असंतोष की जड़ बन गया। नतीजा यह रहा कि पार्टी के पास 37 विधायक होने के बावजूद केवल 28 वोट ही उम्मीदवार के पक्ष में पड़े। हालात इतने बिगड़े कि विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें दूसरे राज्य में शिफ्ट करने जैसी रणनीति अपनानी पड़ी। यह स्थिति बताती है कि पार्टी के भीतर विश्वास और संवाद का अभाव गहराता जा रहा है। बिहार में स्थिति और भी चिंताजनक रही। यहां कांग्रेस और राजद के विधायकों द्वारा मतदान से दूरी बनाना महज लापरवाही नहीं, बल्कि नेतृत्व के प्रति असहमति का संकेत है। जब विधायक खुले तौर पर यह कहें कि उन्हें स्पष्ट निर्देश ही नहीं मिले तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पार्टी का कमांड और कंट्रोल सिस्टम आखिर कितना प्रभावी है। परिणामस्वरूप एनडीए ने सभी सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को करारा झटका दिया। ओडिशा में तो मामला अनुशासनहीनता की हद तक पहुंच गया। कांग्रेस के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करना और फिर पार्टी द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना इस बात का प्रमाण है कि अंदरूनी असंतोष अब नियंत्रण से बाहर हो रहा है। यह केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रवृत्ति का संकेत है, जहां व्यक्तिगत निर्णय पार्टी लाइन पर भारी पड़ रहे हैं। इन घटनाओं का सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह सब उस समय हो रहा है, जब कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्यसभा जैसे अहम चुनावों में इस तरह की चूक यह दर्शाती है कि पार्टी का जमीनी ढांचा अभी भी कमजोर है। नेतृत्व की ओर से उम्मीदवार चयन में स्थानीय समीकरणों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करना महंगा साबित हो रहा है। इसके विपरीत, सत्तारूढ़ गठबंधन ने इन कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। बेहतर रणनीति, स्पष्ट निर्देश और मजबूत संगठनात्मक पकड़ के चलते उन्होंने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की। यह अंतर साफ बताता है कि आज की राजनीति में केवल विचारधारा नहीं, बल्कि प्रबंधन और अनुशासन भी उतने ही जरूरी हैं। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आत्ममंथन की है। क्या पार्टी अपने भीतर के असंतोष को समय रहते दूर कर पाएगी? क्या नेतृत्व राज्यों में मजबूत और स्वीकार्य चेहरों को आगे लाने में सफल होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा कायम कर पाएगी? यह चुनाव कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है कि सिर्फ विपक्ष में होना पर्याप्त नहीं, एक प्रभावी और संगठित विपक्ष बनना जरूरी है। वरना, रास के इस चुनाव में जो दरारें दिखी हैं, वे आने वाले समय में और भी गहरी हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस भाजपा से लड़ाई के बजाय अपने घर को दुरूस्त करे।

यूएस उतारेगा ईरान के विरुद्ध रोबोट सेना

सैन्य प्रौद्योगिकी की दुनिया में दिखाई जाने वाली फिल्मी कहानियां अब मानव जीवन की ठोस सच्चाई में बदलती दिख रही हैं। अमेरिकी टेक कंपनी 'फाउंडेशन' ने दुनिया का पहला आदमी जैसा ह्यूमनोइड कृत्रिम बुद्धि से संचालित रोबोट सैनिक 'फैंटम एमके-1' तैयार कर लिया है। स्टील से बना यह सैनिक रोबोट एम-16 राइफल, रिवॉल्वर और शॉटगन जैसे हथियार चलाने में दक्ष है। इस सैनिक की दक्षता की परख फिलहाल कारखानों और बंदरगाहों पर की जा रही है। अमेरिका ही नहीं रूस,चीन और भारत भी ऐसे सैनिक बनाने में जुटे हैं। भारत का डीआरडीओ ये रोबोट बना रहा है। हालांकि सैनिक के रूप में अभी उनका युद्ध के मैदान में परीक्षण होना शेष है।

मनुष्य की सोच असीम संभावनाओं से जुड़ी है। कल्पना से शुरू होने वाले विचार सच्चाई के धरातल पर आकार लेते हैं, तो आंखें हैरान रह जाती हैं। सैन्य प्रौद्योगिकी की दुनिया में दिखाई जाने वाली फिल्मी कहानियां अब मानव जीवन की ठोस सच्चाई में बदलती दिख रही हैं। अमेरिकी टेक कंपनी 'फाउंडेशन' ने दुनिया का पहला आदमी जैसा ह्यूमनोइड कृत्रिम बुद्धि से संचालित रोबोट सैनिक 'फैंटम एमके-1' तैयार कर लिया है। स्टील से बना यह सैनिक रोबोट एम-16 राइफल, रिवॉल्वर और शॉटगन जैसे हथियार चलाने में दक्ष है। इस सैनिक की दक्षता की परख फिलहाल कारखानों और बंदरगाहों पर की जा रही है। अमेरिका ही नहीं रूस,चीन और भारत भी ऐसे सैनिक बनाने में जुटे हैं। भारत का डीआरडीओ ये रोबोट बना रहा है। इजराइल ऐसे सैनिक बना चुका है। हालांकि सैनिक के रूप में अभी उनका युद्ध के मैदान में परीक्षण होना शेष है। यह एक नए शीत युद्ध और नई तकनीक की होड़ की शुरुआत है,जो दुनिया को ऐसे स्व-नियंत्रित रोबोट सैनिकों को सौंपने जा रही है, जो कृत्रिम बुद्धि से विस्फोटक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

इजराइल पहले ही एक ऐसी 'रोक रोबोट' सेना तैयार कर चुका है, जो न केवल युद्ध लड़ेगी, बल्कि सीमा पर इंसानी सैनिकों की जगह भी ले लेगी। इजराइल की विख्यात रक्षा कंपनी इल्बिट रोबो टीम ने इस सेना को तैयार किया है। रोबो टीम के सीईओ इलाजलेवी के मुताबिक अब तक आकाश में ड्रोन और हवाई रोबोट के जरिए होने वाले सभी काम धरती पर भी हो सकेंगे। मानव रहित रोक रोबोट के अंदर स्वयं ही खतरों को भांपकर फैसला लेने की क्षमता विकसित कर दी गई है। कृत्रिम बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण ये रोबोट जंग के मैदान में खराब होने पर इसके पुर्जे साथ चलने वाले रोबोट सैनिक बदल देंगे। इसकी इस विशेषता से रोबोट सैनिक एकाएक निष्कर्ष नहीं होंगे। 200 किलोग्राम वजन वाले इस रोक रोबोट की दौड़ने की क्षमता 30 किलोमीटर प्रतिघंटा है। यह 1200 किलोमीटर मारक क्षमता वाले हथियार लेकर चलने में सक्षम हैं। इसकी कीमत डेढ़ लाख डॉलर से लेकर तीन लाख डॉलर तक है। मसलन भविष्य के युद्ध रोबोट थल सेना लड़ेगी।ये सैनिक डर और थकान से मुक्त होंगे। कृत्रिम बौद्धिकता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले एक दशक से अपनी हैरतअंगेज उपलब्धियों व भविष्य की संभावनाओं के चलते दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। एलन मस्क, बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग ने इसकी अतिरिक्त बुद्धि एवं शक्ति से आशंकित होकर कई बार चेताया भी है। बावजूद अनेक ऐसे पूंजी-निवेशक और वैज्ञानिक हैं, जो एआई को एक बेहतर भविष्य के सपने के रूप में देखते रहे हैं। आज रोबोट कारखानों में मजदूरी के काम से लेकर शिक्षक, टीवी एंकर, नर्स और अब सैनिक की भूमिका में अवतरित होने जा रहा है।

सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भविष्य में यह मशीनी रोबोट मनुष्य पर ही भारी न पड़ जाए। मानव और मशीन के बीच पैदा होने वाले ये द्वंद्व हकीकत में किस सच्चाई के रूप में सामने आएंगे, यह तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जब-जब कोई नया आविष्कार हुआ है तो वह शंका का कारण तो बना ही है। भारत सरकार इस कोशिश में है कि तीनों सेनाओं में कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिशियल

इनटेलीजेंसी) से निर्मित रोबोटिक हथियारों की संख्या बढ़ा दी जाए। इस नाते एक महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य मानव रहित टैंक, जलपोत, स्वचालित राइफल और रोबो आर्मी तक खड़ी की जाने की तैयारी है। हवाईयानों को भी रोबोटिक हथियारों से सक्षम बनाया जाएगा। यह परियोजना जब क्रियान्वित हो जाएगी, तब भारत की थल, जल और वायु सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए नई तकनीक से सक्षम हो जाएंगी। टाटा संस के प्रमुख एन चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाला एक उच्च स्तरीय समूह इस परियोजना को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भी सहयोग कर रहा है।

दरअसल, भविष्य के युद्धों में रोबोट और मानव रहित हथियार ही ज्यादा उपयोग में लाए जाएंगे। इससे युद्ध में मानव सैनिकों के प्राण बचेंगे। परंतु रक्षा विशेषज्ञों की चिंता है कि यदि युद्ध के दौरान एआई में तकनीकी व्यवधान और हैकिंग के बड़े संकट हैं। अतएव इंसानी नियंत्रण से मुक्त इन मशीनी सैनिकों को फैसले लेने की छूट मिल जाती है तो ये युद्ध को पलों में तांडव में बदल सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश को सेना को बदलती परिस्थितियों की जरूरतों के अनुसार ढालना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की सीमा पर दृश्य दुश्मनों से कहीं ज्यादा अदृश्य शत्रुओं की चुनौती कहीं अधिक है। साफ है, इनसे निपटना आसान नहीं है। ये सामने तो दिखाई नहीं देते हैं, मगर इनका धोखे से किया गया हमला बड़ा खतरनाक होता है। साफ है, इन धोखेबाज ताकतों से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़े उपकरणों से ही निपटना बेहतर है। इस कड़ी में अब भारतीय रोबो सेना जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए उतारने की तैयारी की जा रही है। ये रोबोट आतंकियों के गुप्त ठिकानों में दृश्य व अदृश्य शक्ति के रूप में उतरकर उनकी मौजूदगी की सटीक जानकारी तो देंगे ही, अलबत्ता उन्हें पलों में तबाह भी कर देंगे। ये रोबोट घाटी एवं नियंत्रण रेखा पर जो आतंक प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें सेना की आतंकरोधी इकाई और सुरक्षा बलों के लिए सुरक्षा के लौह कवच सिद्ध होंगे। इनकी सीमा पर उपलब्धता के साथ ही सेना को पूरी तरह हाईटेक बना दिया जाएगा। यही नहीं, दुश्मन की घुसपैठ को नाकाम बनाने और पाकिस्तानी सेना के हमलों से मुकाबले में भी यह रोबोट सेना फलदायी सिद्ध होगी। कृत्रिम बुद्धि (एआई) वाले ये रोबोट सेना के रूप में सीमा पर शक्ति का पर्याय बनके दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगे। इसी मंशा के अनुरूप रक्षा मंत्रालय पहले चरण में 550 रोबोटिक्स सर्वेलांस यूनिट खरीद रहा है। इनकी खेप मिलते ही इन्हें सेना के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये आर्मी-रोबो किसी भी आतंकरोधी अभियान के दौरान आतंकियों पर हमला करने में सहायक की भूमिका निभाएंगे। सुरक्षा बलों के लिए आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही में सबसे बड़ी चुनौती उनकी सही संख्या और उनके पास उपलब्ध हथियारों की पूरी जानकारी लेने की होती है। ये रोबोट वीडियोग्राफी के जरिए इनके ठिकानों के निश्चित स्थल से चित्र सहित अवगत करा देंगे। ये रोबोट सैनिक इसलिए इतने बौद्धिक रूप से सक्षम व चपल होंगे, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर की संरचना में इतनी बुद्धि डाल दी जाएगी कि भविष्य में ये मनुष्य के जैविक दिमाग से कहीं ज्यादा तेज गति से काम करने लग जाएंगे। इस मिली-जुली बुद्धिमत्ता के लिए एक नया शब्द 'सिंगुलैरिटी' अस्तित्व में आ गया है। यानी मशीनी दिमाग का आधिपत्य हो जाए तो इसे सिंगुलैरिटी शब्द से पुकारा जाएगा। बहरहाल तेज दिमाग और तात्कालिक चपलता से जुड़ी रोबो-आर्मी युद्धों में ऐसा वरदान साबित होगी, जो हमारे मानव सैनिकों के जीवन को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करेगी।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मुद्दा
अखिलेश आर्येन्दु

भारत के सामने क्यों है युद्ध रुकवाना चुनौतीपूर्ण

ब्रिक्स के गठन के बाद कुछ देशों में युद्ध के हालात बने लेकिन वे वैश्विक तेल और आर्थिक संकट की वजह नहीं बनें। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के संयुक्त युद्ध के हालात दुनिया में कई तरह की समस्याएं और संकट पैदा कर रहे हैं। अमेरिका के मित्र देशों पर ईरान के हमले के बाद हालात कुछ ज्यादा ही जटिल हो गए हैं। कई देशों में उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधे असर पड़ा है। दुनिया भर में यह आशंका होने लगी है कि कहीं यह युद्ध विश्व-युद्ध का रूप न ले ले। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् जल्द से जल्द युद्ध खत्म कराने की कोशिश में है। दूसरी तरफ भारत की कोशिश है कि जल्द से जल्द आपसी संवाद के जरिए युद्ध रोका जाए और तेल संकट जो दुनिया के लिए आर्थिक संकट के रूप में उभर आया है, उस पर आपसी सहमतियां बनें। ब्रिक्स के जरिए भी यह कोशिश हो रही है कि युद्धरत देशों में आपसी संवाद का रास्ता आगे बढ़े और युद्ध विराम हो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मसूद ने कहा था कि यदि भारत ईरान का मित्र है तो ब्रिक्स को चाहिए कि बढ़ते संघर्ष से निपटने में मजबूत और रचनात्मक भूमिका निभाए। भारत ब्रिक्स का वर्तमान में अध्यक्ष है। अध्यक्ष होने की वजह से ईरान चाहता है कि भारत ब्रिक्स के जरिए अमेरिका-इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों की निंदा करने के लिए सदस्य देशों में सहमति बैठाने की कोशिश करे।

भारत का दृष्टिकोण इस मामले में बेहद संतुलित है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि इस मामले में सीधे किसी देश के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए युद्धरत देशों में आपसी संवाद ही सबसे मुफीद रास्ता है। इस मुद्दे पर ब्रिक्स के भीतर सहमति बनाना बेहद कठिन हो गया है क्योंकि समूह के कुछ सदस्य देश मौजूदा संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ भारत लगातार संपर्क बनाए हुए है और एक संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि शेरपा ब्रिक्स के सदस्य देशों का एक माध्यम है। इसके जरिए सदस्य देशों की आधिकरिक कूटनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है।

इसके जरिए किसी शिखर सम्मेलन से पहले सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि आपसी संवाद को आगे बढ़ाते हैं और मुद्दों पर एक सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। ब्रिक्स देशों के जो प्रतिनिधि उस देश के जरिए नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें शेरपा कहा जाता है। ये शेरपा उन देशों के नेताओं के बैठक के पहले बैठक का एजेंडा, बयान और समझौतों के मसौदे तैयार करने में अहम रोल निभाते हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारी को 'शेरपा' कहा जाता है और उन अधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत को शेरपा चैनल कहा जाता है। 'ब्रिक्स' की स्थापना के वक्त इसमें भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन शामिल थे। ये वे देश हैं जिन पर ईरान के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है या इजराइल-अमेरिका के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा युद्ध के हालात में ब्रिक्स देशों में युद्ध रुकवाने या अमेरिका-इजराइल के ईरान पर आक्रमण को लेकर निंदा का सर्वसम्मति सहमति न बन पाने की वजह सबके अपने स्वार्थ और एक दूसरे से संबंध हैं। वर्तमान में विश्व के हालात पिछले वर्षों में युद्धरत देशों से अलग तरह के हैं। गौरतलब है 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स ने जून 2025 में ईरान पर इजराइल के हमलों को लेकर दो बयान जारी किए थे। इस साल भारत सहित ब्रिक्स देशों की स्थिति अलग तरह की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात सहित गल्फ कोऑपरेशन कांउसिल (जीसीसी) के देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की है। वहीं पर ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों को लेकर भारत ने कोई बयान जारी नहीं किया है। सवाल यह है कि क्या कोई संयुक्त बयान जारी न करवा पाने की वजह से ब्रिक्स की प्रेसीडेंसी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है? क्या बयान जारी न करवा पाना मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता मानी जाएगी? दरअसल, पिछले साल के विश्व हालात और वर्तमान के हालात में अंतर है। ईरान ने अमेरिकी मित्र देशों पर हमला करके स्थिति को काफी जटिल बना दी है। इनमें से ज्यादातर देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। इसलिए ईरान के प्रति हमदर्दी दिखाना धर्मसंकट जैसी स्थिति बन गई है। भारत फिर भी इस नीति पर चल रहा है कि युद्ध जल्द खत्म हो और युद्धरत देशों में संवाद की स्थिति बन बने। तेल और आर्थिक संकट से दुनिया के देश बाहर आएं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हृदय का करें अनुसरण

संकलित
दर्शन

कोई भी धर्मग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता। चाहे हम दुनिया के सारे धर्मग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता। हम सारी उम्र धर्म या ईश्वर संबंधी बातें करते रहें, पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। दुनिया के विद्वानों ने भले ही हमारी बुद्धि प्रखर कर दी हो, पर हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सके। पाश्चात्य संस्कृति का दोष यह है कि हम बुद्धि का संस्कार करते समय हृदय के संस्कार की ओर ध्यान ही नहीं देते। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य दस गुना स्वार्थी हो जाता है। यदि हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो, तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि केवल एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है, वह उसके परे जा ही नहीं सकती, पर वह केवल हृदय ही है, जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरूढ़ करता है। वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय, बुद्धि का अतिक्रमण कर अंतःस्फूर्ति को पा लेती है। बुद्धि से कभी अंतःस्फूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अंतःस्फूर्ति का कारण केवल ज्ञानोदय बासित हृदय ही है। बुद्धिप्रधान, किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान नहीं बन सकता। प्रेममय पुरुष की समस्त क्रियाएं उसके हृदय से अनुप्राणित होती हैं। एक ऐसा उच्चतर साधन, जिसे बुद्धि कभी नहीं दे सकती, अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने ही, और वह साधन है अंतःस्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय अंतःस्फूर्ति का। शुरुआत में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता, जितनी कि बुद्धि।

हे श्री कृष्ण! तुम सर्वज्ञ हो

संकलित
प्रेरणा

एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है, उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते है। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार-बार आग्रह करने पर दुकानदार खीज कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, जिसकी कोई कीमत हो, तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हे दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है। क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह, एक मुड़ा-तुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिख कर तराजू पर रख देती है। दुकानदार ये देख कर हंसने लगता है। फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। आश्चर्य..!!! कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो और सब्जी रखता जाता है पर कागज वाला पलड़ा नीचे नहीं होता। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठा कर पढता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था, हे श्री कृष्ण! तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है, कि दोस्त, आश्चर्य मत करो। केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं की प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। चाहे वो एक घंटे की हो या एक मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाये, तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं।

लकड़ियां दूर करेगी गैस की कमी

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मंगलवार को कुकिंग गैस की कमी दूर करने लकडहारे सड़क किनारे लकड़ियों को ईंधन के लिए काटते हुए।

आज की पाती

राजनीति पर लगाम कसने मतदान जरूर करे

देश के चार राज्यों तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मतदान की अहम भूमिका होती है। हर चुनाव में हर मतदाता को जरूर मतदान करना चाहिए। वैसे तो हर उम्र के मतदाताओं को मतदान में रुचि दिखानी चाहिए, लेकिन युवाओं का दायित्व बनता है कि वो देश की राजनीति की धूमिल होती छवि और अवसरवाद की ओर बढ़ती राजनीति पर लगाम कसने के लिए हर चुनाव में मतदान जरूर करे। महापुरुषों ने युवा वर्ग के लिए कहा था कि युवा देश, समाज में एक अच्छा और सच्चा बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए या निभा सकता है। मतदान समझदारी से करना होगा। – विकास यादव, रायपुर

ट्रेंड

महिलाओं की भागीदारी

भारत में स्टॉक एक्सचेंज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बढ़ती भागीदारी न केवल आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि देश की विकास यात्रा में महिलाओं की सशक्त और महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाती है।
-अन्नपूर्णा देवी, महिला विकास मंत्री

किसानों की समृद्धि

प्रदेश के किसानों और उद्योगों की समृद्धि हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। वर्ष 2027 तक हर अन्नदाता को दिन में निर्बाध बिजली देने के संकल्प के साथ राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। अब हमारा किसान 'अन्नदाता' के साथ 'ऊर्जादाता' बनकर विकास को नई रोशनी दे रहा है।
-भजनलाल, सीएम, राजस्थान

पानी तक उपलब्ध नहीं

युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति थोड़ी बाधित हुई है। लेकिन झारखंड में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तो दूर की बात है, कांग्रेस-झामुमो की सरकार जनता को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
-बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम, झारखंड

सम्मान की उम्मीद

जब कूटनीति से लेकर व्यापार और धर्म तक हर चीज को हथियार बना लिया जाता है, तो युद्ध से "कानूनों" या "नैतिकता" का सम्मान करने की उम्मीद करना एक कोरी कल्पना मात्र है।
-कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार विजेता

करंट अफेयर

अहमदिया के दमन को लेकर पाकिस्तान की आलोचना

भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी पड़ोसी देशों में 'इस्लामोफोबिया' (इस्लाम के प्रति घृणा) की 'काल्पनिक कहानियां गढ़ने' की आदत है और सवाल उठाया कि इस्लामाबाद के अपने ही देश में अहमदिया समुदाय के क्रूर दमन या रमजान के दौरान अफगानिस्तान पर हवाई बमबारी को कैसे देखा जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, 'भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश अपने आसपास इस्लामोफोबिया की कल्पनिक कहानियां गढ़ने का उत्कृष्ट उदाहरण है।' उन्होंने कहा, 'यह सोचने वाली बात है कि इस देश में अहमदियाओं का क्रूर दमन, बेबस अफगानों की बड़े पैमाने पर जबरन वापसी या रमजान के पवित्र माह में हवाई बमबारी को क्या कहा जाएगा?' हरीश सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया से निपटने के अंतरराष्ट्रीय दिवस को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि 'इस्लामिक सहयोग संगठन' ने बार-बार भारत के खिलाफ झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस संगठन को 'हमारे पश्चिमी पड़ोसी ने भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की व्यवस्थित तरीके से कोशिश की है।'

ऑफ बीट

कार्डियो वजन उठाने से पहले करना चाहिए या बाद में ?

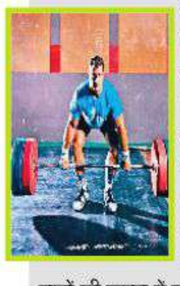

फिटनेस के प्रति जुनूनी लोग दशकों से इस प्रश्न पर बहस करते रहे हैं कि 'कार्डियो' करना वजन उठाने से पहले बेहतर होता है या बाद में? हाल तक, इसका उत्तर काफी हद तक पसंद पर निर्भर करता था - कुछ लोग वजन उठाने से पहले जॉगिंग करते थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि पहले वजन उठाना वसा को खत्म करने के लिए बेहतर है। लेकिन एक नए शोध ने अंततः इस लंबे समय से विवादित प्रश्न का उत्तर दे दिया है। शोध के अनुसार, आपके व्यायाम का क्रम इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि आप कितनी चर्बी कम करते हैं। जिन प्रतिभागियों ने वजन उठाने के बाद कार्डियो किया, उनमें कार्डियो करने के बाद वजन उठाने वालों की तुलना में काफी अधिक चर्बी कम हुई और वे पूरे दिन शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहे। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को 12 सप्ताह के लिए तीन समूहों में विभाजित किया। दोनों व्यायाम समूहों ने एक जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाए, केवल व्यायाम क्रम में अंतर था। प्रतिभागियों ने बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, बाइसेप कर्ल और स्क्वाट जैसे व्यायाम किए। कार्डियो सत्र में 30 मिनट तक 'साइकिलिंग' शामिल थी। दोनों समूहों के प्रतिभागियों ने अपनी हृदय संबंधी फिटनेस, मांसपेशियों की ताकत और शारीरिक बनावट में सुधार का अनुभव किया।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस जीत से हुड्डा कैंप हुआ मजबूत दीपेंद्र ने कहा, खरीद फरोख्त और दबाव की राजनीति हुई नाकाम

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

कांग्रेस ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार करमवीर बौद्ध की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि भाजपा ने खरीद-फरोख्त और चुनाव आयोग से मिलीभगत कर लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हरियाणा के सुबाई सियासत में एकबार फिर हुड्डा कैंप का दबदबा बढ़ा। शीर्ष नेतृत्व ने पिछले राज्यसभा चुनाव से सीख लेकर इस बार पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को जिताने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी थी। तमाम प्रयासों को विफल कर जीत का तमगा लेने के बाद दिल्ली में जब हुड्डा पत्रकारों से मुखातिब हुए तो आत्मविश्वास से लबरेज थे।

कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए हुड्डा और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने करमवीर बौद्ध की जीत के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और इसे लोकतंत्र एवं संविधान की जीत बताया। हुड्डा ने भाजपा पर चुनाव के दौरान अनैतिक हथकंडे अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने रात के अंधेरे में लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने की कोशिश की। गुजरात के उपमुख्यमंत्री को ऑब्जर्वर बनाकर भेजने का हवाला देते हुए हुड्डा ने कहा कि भाजपा हाईकमान हर हाल में यह सीट हासिल करना चाहता था। इसके लिए भाजपा ने क्रॉस वोटिंग के साथ कई तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने करमवीर बौद्ध को जीत दिलाकर लोकतंत्र बचाने का काम किया।

इनेलो (इंडियन नेशनल लोकदल) को भाजपा की बी टीम करार देते हुए हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जब खरीद-फरोख्त से संख्या हासिल करने की भाजपा की योजना फेल हो गई तो उसे समझ आ गया कि कांग्रेस उम्मीदवार जीतने जा रहा है। इनेलो ने चुनाव के दिन तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। शाम चार बजे तक मतदान था और इनेलो ने साढ़े तीन बजे घोषणा की कि वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। जब कांग्रेस के पक्ष में 30 से ज्यादा वोट पड़ गए और यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस जीत रही है तो इनेलो मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई।

उन्होंनेकहा कि इस सबके बाद भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर अगला हथकंडा अपनाया। रिटर्निंग अधिकारी ने पक्षपात किया और कांग्रेस के 4 वैध वोटों को गलत तरीके से अमान्य घोषित किया गया। ये सब तब किया गया, जब एक अन्य चुनाव अधिकारी ने यही वोट वैलिड ट्रे में डाले थे। उन्होंने कहा कि जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पार्षदों के वोट चोरी करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने विधायकों के वोट चोरी करने का प्रयास किया। राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट किया कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जनता इन विधायकों को माफ नहीं करेगी और बदला लेगी। उन्होंने उन विधायकों की सराहना की जो तमाम प्रलोभन और दबाव के बावजूद मजबूती एवं ईमानदारी से पार्टी के साथ खड़े रहे। गौतम ने सच्चे अंबेडकरवादी करमवीर बौद्ध को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल धनवानों को मजबूत मानती है, इसलिए वह करमवीर बौद्ध को कमजोर उम्मीदवार बता रही थी। लेकिन कांग्रेस ने दिखा दिया कि वह एक आम कार्यकर्ता को भी राज्यसभा भेज सकती है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जांच एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ सक्रिय रहती हैं, लेकिन विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं करतीं। भाजपा बाबासाहेब अंबेडकर, दलितों और संविधान से नफरत करती है।

संसद में एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने की मांग विपक्ष ने उठाई

राज्यसभा में दिखे शुक्ला के तेवर, दोनों सदनों में उठे सवाल, सरकार नई तकनीकों पर ध्यान दे

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए रक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक योजनाओं को लेकर आलोचना की। रक्षा मामलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हालिया 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे उदाहरणों से स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध अब आसमान में लड़े जा रहे हैं, जहां मिसाइल और ड्रोन की भूमिका अहम है। ऐसे में सरकार को अपनी रणनीति बदलते हुए रिसर्च और नई तकनीकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एंटी-ड्रोन तकनीक के विकास की भी जरूरत बताई और कहा कि पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की घटनाएं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। एलपीजी संकट को लेकर उन्होंने सरकार के बयानों में विरोधाभास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने संकट से इनकार किया, लेकिन बाद में इसे स्वीकार किया गया।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब कीमतें बढ़ती थीं तो भाजपा नेता स्मृति ईरानी खुद सड़क पर सिलेंडर लेकर विरोध करती थीं। विदेश नीति पर भी राजीव शुक्ला ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले भारत सभी देशों के साथ संतुलित संबंध रखता था, लेकिन अब देश एक खास गुट के साथ जुड़ा नजर आ रहा है, जिससे कूटनीतिक संतुलन प्रभावित हुआ है। उन्होंने वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की रसोई बंद होने का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि एलपीजी संकट नहीं है, तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन पर्याप्त नहीं है और आयुष्मान योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट मुनाफा 22.3 फीसदी बढ़ा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा। देश की संपत्ति और आय का बड़ा हिस्सा केवल शीर्ष 10 फीसदी लोगों के पास केंद्रित है, जिससे असमानता बढ़ रही है। इसके अलावा, उन्होंने फसल बीमा योजना को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि यह योजना अब एक तरह का "स्कैंडल" बन चुकी है, जहां निजी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, जबकि किसान नुकसान में हैं। उन्होंने रुपये की डॉलर के मुकाबले गिरती स्थिति पर भी चिंता जताई। शुक्ला ने सरकार से इन सभी मुद्दों पर जवाब देने और ठोस कदम उठाने की मांग की।

लोकसभा में ज्योत्सना महंत ने उठाया कोरबा में रेल सुविधाओं की कमी का मामला

लोकसभा में ज्योत्सना महंत ने छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में रेल सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार और रेलवे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कोरबा का कोयला पूरे देश को रोशन करता है और रेलवे की आय में बड़ा योगदान देता है, लेकिन बदले में क्षेत्र को पर्याप्त यात्री सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरबा में रेलवे की प्राथमिकता केवल मालगाड़ियों को दी जा रही है, जबकि यात्री गाड़ियां घंटों आउटर पर खड़ी रहती हैं। इससे आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।ज्योत्सना महंत ने बताया कि सरकार ने बजट में कोरबा और बैकुंठपुर में नए रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव रखा था और भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जबकि इसे वर्ष 2021 तक ही तैयार हो जाना था। उन्होंने कोरबा से कटनी मार्ग पर एक भी सीधी ट्रेन नहीं होने पर भी उन्होंने चिंता जताई। महंत ने यह भी कहा कि कई ट्रेनें नागपुर तक आकर रुक जाती हैं, उन्हें कोरबा तक विस्तारित क्यों नहीं किया जा रहा, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।

असहमति को राष्ट्रद्रोह से न जोड़े सरकार आंदोलनों को कुचलना उचित नहीं

राज्यसभा में रजनी पाटिल ने देश में बढ़ती विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई और सरकार के रवैये को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाना उचित नहीं है और शांतिपूर्ण विरोध को सम्मान मिलना चाहिए। पाटिल ने कहा कि पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न वर्गों, युवा, किसान, महिला खिलाड़ी, आदिवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों पर युवाओं ने विरोध किया, वहीं देश की महिला पहलवानों ने एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने आगे कहा कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया, जबकि आदिवासी समुदाय ने जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी आम जनता ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किए।

पाटिल ने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ युवाओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन उन्हें देश विरोधी करार देकर जेल में डाल दिया गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि असहमति को देशद्रोह से जोड़ना उचित नहीं है। सरकार से अपील करते हुए रजनी पाटिल ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के प्रति उदार और संवेदनशील नीति अपनाई जानी चाहिए, ताकि नागरिक बिना भय के अपनी बात रख सकें। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि पुलिस बल का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए और पहले संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सभी पक्षों—प्रदर्शनकारियों, संगठनों और संबंधित संस्थाओं—के साथ संस्थागत संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

कर्नाटक को रेलवे बजट में कम आवंटन पर राज्यसभा में उठे सवाल

राज्यसभा में नासिर हुसैन ने कर्नाटक को रेलवे बजट 2025–26 में मिले अपेक्षाकृत कम आवंटन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर्नाटक के साथ रेलवे निवेश के मामले में न्याय नहीं हो रहा है। हुसैन ने सदन में बताया कि वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कर्नाटक का संशोधित राज्य सकल घरेलू उत्पाद लगभग 30.7 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जिससे यह देश के सबसे बड़े राज्यीय आर्थिक केंद्रों में से एक बनता है। इसके बावजूद, रेलवे बजट में राज्य को केवल 7,564 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे राज्य, जिनकी अर्थव्यवस्था कर्नाटक से काफी छोटी है और जिनका कर योगदान भी कम है, उन्हें इससे कहीं अधिक रेलवे बजट मिला है। यह असमानता केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के निष्पक्ष वितरण पर सवाल खड़े करती है। कर्नाटक में रेलवे नेटवर्क की स्थिति पर चिंता जताते हुए हुसैन ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई लगभग 3,089 किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक विस्तार और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के बिना उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के कई रेलवे प्रोजेक्ट्स लंबे समय से फंड की कमी और मंजूरी में देरी के कारण अटके हुए हैं। इससे राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हुसैन ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह कर्नाटक के साथ न्याय करते हुए रेलवे बजट में उचित बढ़ोतरी करे और लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दे।

आयुष कार्ड को लेकर अस्पतालों की मनमानी पर राज्यसभा में उठे सवाल

राज्यसभा में प्रमोद तिवारी ने आयुष कार्ड धारकों के साथ अस्पतालों में हो रही कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना होने के बावजूद मरीजों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तिवारी ने सदन में कहा कि अक्सर यह देखा जा रहा है कि जब मरीज आयुष कार्ड लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, तो उनसे पहले नकद राशि जमा करवाई जाती है। जबकि योजना का उद्देश्य ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना आर्थिक बोझ के इलाज उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जब इस बारे में अस्पताल प्रशासन से पूछा जाता है, तो उनका जवाब होता है कि सरकार से भुगतान मिलने में कई साल लग जाते हैं, जिसके कारण उन्हें मरीजों से पहले ही पैसे लेने पड़ते हैं। इस स्थिति ने योजना की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर प्रमोद तिवारी ने सरकार से दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला, क्या उन अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी जो आयुष कार्ड को स्वीकार नहीं करते या उसके बावजूद मरीजों से नकद वसूली करते हैं? दूसरा, क्या नर्सिंग होम और अस्पतालों को सरकार द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे?उन्होंने कहा कि यदि अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं मिलेगा, तो वे योजना के प्रति उदासीन रहेंगे और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि मरीजों को बिना किसी परेशानी के इलाज मिल सके।

उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व पर राज्यसभा में उठे सवाल

नई दिल्ली। राज्यसभा में नीरज डांगी ने देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज भी कई शीर्ष संस्थानों में फैकल्टी स्तर पर इन वर्गों की भागीदारी बेहद कम है, जो सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांतों के विपरीत है। सदन में अपने वक्तव्य के दौरान डांगी ने इस विषय पर तीन महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि सार्वजनिक संस्थान ही भारत की सामाजिक विविधता को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? दूसरा, यदि प्रतिष्ठित संस्थानों में आरक्षण नीति का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, तो इससे वंचित वर्गों को क्या संदेश जाएगा? तीसरा, जब शैक्षणिक नेतृत्व में समावेशिता की कमी है, तो समावेशी विकास की बात कैसे की जा सकती है? नीरज डांगी ने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि सभी केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों में फैकल्टी प्रतिनिधित्व का देशव्यापी ऑडिट कराया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

मुद्रा योजना के 'तरुण प्लस' के तहत नहीं मिल रहे लोन

राज्यसभा में शक्तिसिंह गोहिल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 'तरुण प्लस' श्रेणी में कम लोन वितरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी में 10 से 20 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पहले लिया गया लोन सफलतापूर्वक चुका दिया हो। गोहिल ने बताया कि इसके बावजूद 'तरुण प्लस' कैटेगरी में बहुत कम लोगों को ऋण मिल रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण हैं और इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे, ताकि योग्य लाभार्थियों को समय पर ऋण मिल सके।

एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष से मिली हरसिमरत, मान की शिकायत की

मान के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस वाली टिप्पणी पर कार्रवाई हो

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

शिरोमणी अकाली दल की वरिष्ठ नेता और बठिंडा सांसद बीबा हरसिमरत कौर बादल ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर से मुलाकात कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि लुधियाना में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में महिलाओं के खिलाफ गलत बयान, अपमानजनक और यौन रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस संबंध में कड़ा संदेश देना जरूरी बताया

हरसिमरत कौर बादल ने आयोग की अध्यक्ष से कहा कि यह बेहद जरूरी है ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि महिलाओं को इस तरह वस्तु की तरह न देखा जा सकता। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सांसद बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के सामने एक लड़की के साथ रिश्ते का झूठा दावा किया था। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री ने उस लड़की को उसके कपड़ों के आधार पर उसका अपमान भी किया।

बठिंडा सांसद ने एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष से कहा कि जब किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सार्वजनिक रूप से संवेदनशील लोगों की सभा में महिलाओं के बारे इस तरह की बात करना कितना आपत्तिजनक है- और इसने एक खतरनाक संदेश दिया कि सार्वजनिक मनोरंजन और सस्ते रोमांच के लिए महिलाओं की गरिमा को कम किया जा सकता है और उनकी पहचान को केवल उनकी उपस्थिति तक सीमित कर दिया जा सकता है।

कांग्रेस के आरोप निराधार, बजट में एसवाईएल के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधानः सैनी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2026-27 के प्रस्तावों में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इसलिए विपक्ष का यह आरोप कि बजट में एस.वाई.एल. नहर का कहीं जिक्र नहीं है, पूरी तरह से निराधार है। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट अनुमान 2026-27 पर चर्चा के उपरांत जवाब दे रहे थे।

सैनी ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के साथियों ने यह कहा कि वे तीन दिन से बजट भाषण पढ़ रहे हैं और उसमें एसवाईएल नहर का कहीं जिक्र नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के गठन के लगभग 60 वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई बजट नहीं रहा, जिसमें एस.वाई.एल. का उल्लेख न किया गया हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट 2026-27 के दस्तावेज खंड-III,

जो कि पूंजीगत व्ययों का ब्यौरेवार अनुमान प्रस्तुत करता है, उसके पृष्ठ संख्या 204 पर स्पष्ट रूप से एस.वाई.एल. नहर का निर्माण के सब-हेड में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वर्ष 2005 से 2014 तक के दस वर्षों के कार्यकाल के बजट भाषणों के रिकॉर्ड के अनुसार केवल दो वर्षों 2005-06 और 2006-07 के बजट भाषण में ही एस.वाई.एल. नहर का उल्लेख किया था। बाकी 8 बजट भाषणों में एस.वाई.एल. शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, 10 में से केवल 2 वर्षों अर्थात 2013-14 और 2014-15 के बजट में एसवाईएल के निर्माण के लिए मात्र 10 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया था। बाकी आठ वर्षों में एक रुपए का भी प्रावधान इस सब- हेड के लिए नहीं किया था। सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने तो वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक हर साल 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। राज्यपाल द्वारा 20 फरवरी, 2026 को दिए गए अभिभाषण के पैरा नंबर-36 में भी एसवाईएल के बारे में कहा गया है कि मेरी सरकार के लिए हरियाणा के जल के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। हम सतलुज-यमुना लिंक नहर बनाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध हैं।

किसानों की आय और सुरक्षा दोनों की गारंटी, लोक सभा में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान

छोटी जोत पर बड़ा मुनाफा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल तैयार

कहा, तंबाकू की जगह नकदी फसलें प्रोत्साहित कर रही केंद्र सरकार

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने तंबाकू जैसी हानिकारक फसल के स्थान पर लाभदायी वैकल्पिक फसलें उपलब्ध कराने से लेकर एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीदी, फसल बीमा योजना में क्रांतिकारी सुधार और सख्त निगरानी व्यवस्था के जरिए किसानों की आय और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

चौहान ने मंगलवार को लोक सभा में सांसदों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताया कि मोदी सरकार ने केवल किसानों से तंबाकू की उपज छोड़ने की अपील नहीं की, बल्कि जिन क्षेत्रों में ये उगाई जाती है, वहां हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास,

आलू, चिया, फीड बीन, लोबिया, रागी, रेड ग्राम, गन्ना, सोयाबीन, ज्वार और मूंगफली जैसी लाभकारी फसलों को मजबूत विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया है ताकि किसानों की नकदी आमदनी सुरक्षित रहे।

उन्होंने कहा कि देश में अधिकांश किसानों के पास छोटी जोत है, ऐसे में छोटे किसानों के लिए केवल एक फसल पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, इसलिए सरकार ने एकीकृत खेती (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) के कई मॉडल तैयार कर विभिन्न राज्यों में उनका डेमो शुरू किया है। इन मॉडलों के तहत किसान अनाज (गेहूं, धान), सब्जियाँ, फल, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन और कृषि वानिकी जैसी गतिविधियां एक साथ अपनाकर साल भर स्थिर और बेहतर आमदनी अर्जित कर सकते हैं।

चौहान ने कहा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं, धान, दलहन और तिलहन सहित सभी प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और वर्तमान सीजन में एमएसपी पर फसलों की ऐतिहासिक खरीदी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मोदी सरकार ही है जिसने तुअर, मसूर और उड़द जैसी दलहन फसलों के लिए यह व्यवस्था की है कि किसान पंजीयन कराकर जितना भी बेचने के लिए लाएंगे, सरकार पूरी खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दाल उत्पादक किसानों को बड़ा सहारा मिला है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई-कई महीनों तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता था, लेकिन मोदी सरकार ने नियमों में व्यापक संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि एक अकेले किसान की फसल को भी नुकसान होगा तो बीमा कंपनी को उसका मुआवजा देना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब उपज के आंकड़े आने के बाद 21 दिनों के भीतर यदि बीमा दावा राशि किसान के खाते में नहीं पहुंचती, तो बीमा कंपनियों और राज्यों – दोनों को 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा ताकि किसी भी किसान को देरी की दोहरी मार न झेलनी पड़े।

पश्चिम बंगाल में मनरेगा फंड रोकने के आरोपों पर शिवराज ने दिया जवाब

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में मनरेगा फंड रोकने पर 'भेदभाव' के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि यह राजनीतिक नहीं, वैधानिक कार्रवाई थी। उन्होंने बताया कि विभिन्न टीमों और सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में मजदूरों की जगह मशीनों से काम, ठेकेदार–केन्द्रित काम, एक काम के कई टुकड़े कर ठेके बाँटना, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मास्टररोल और 80–20 की बंदरबांट, 80 साल की 'मजदूर' दादियां, तीन-तीन महीने बाद गांव जाकर मनरेगा के पैसे निकालने वाली कामवाली बाई जैसे गंभीर आरोप सामने आए। वहां सोशल ऑडिट और शिकायतों के जरिए लगभग 11 लाख गड़बड़ियों की रिपोर्ट आई। केंद्र की टीमों ने राज्य सरकार से गड़बड़ियां रोकने को कहा, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ और हाईकोर्ट की शर्तों को भी 'फाड़कर फेंक दिया गया', तब मनरेगा फंड पर रोक लगानी पड़ी।

चौहान ने साफ किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, पीएम आवास और कृषि योजनाओं के पैसे बंगाल को मिलते रहे, क्योंकि हमारा मकसद जनता को सज़ा देना नहीं, व्यवस्था की गड़बड़ियों को ठीक करना है, केवल खाने के लिए पैसा नहीं दिया गया, जवाबदेही भी ज़रूरी है। पंजाब का जिक्र कर शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के दौर में यूपीए सरकार ने पंजाब को सिर्फ 858 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने उसी पंजाब को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि मनरेगा के लिए दी, फिर भी आज वही लोग केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं।

अमर उजाला
प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा
नई दिल्ली ■ बुधवार, 18 मार्च 2026

इंटरनेट को नियंत्रित करना सत्तावादी शासनों के लिए एक शक्तिशाली साधन है। -रोजर स्पिट्ज

होर्मुज मार्ग को सुरक्षित बनाने में सहयोग की अमेरिकी अपील पर सहयोगी देशों ने जैसी ठंडी प्रतिक्रिया दी है, उस पर ट्रंप की निराशा वर्तमान वैश्विक कूटनीतिक यथार्थ का महत्वपूर्ण संकेतक है। होर्मुज को खोलने के लिए सैन्य बल से ज्यादा जरूरी यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय संवाद-उन्मुख हो।

ट्रंप की अपील

दरसे देशों से युद्धपोत और नौसैनिक बलों को भेजकर होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग को सुरक्षित बनाने में सहयोग करने की अमेरिकी अपील पर मिली ठंडी प्रतिक्रिया के बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा व्यक्त की गई निराशा आज के वैश्विक शक्ति संतुलन और कूटनीतिक यथार्थ का महत्वपूर्ण संकेतक है। उल्लेखनीय है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले इस संकरे समुद्री मार्ग से वैश्विक तेल कारोबार का करीब 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के लिए इस मार्ग की अहमियत इससे ही समझी जा सकती है कि वर्तमान पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत में इस मार्ग में अड़चन आने की आशंका पैदा होने के साथ ही वैश्विक तेल बाजार में तेल की कीमत सौ डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। हालांकि, ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के लिए होर्मुज का प्रश्न उतना अहम नहीं है, क्योंकि उसके पास तेल तक अपनी पहुंच है। इसके बावजूद, ट्रंप की सहयोग की अपील को, चीन और जापान के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस व दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने खारिज किया, तो इसकी वजह समझी जा सकती है। असल में, ट्रंप की एक खास किस्म की अनिश्चितता उन देशों को भी उनसे दूर कर रही है, जो अब तक भले ही अनिच्छापूर्वक, लेकिन उनके साथ खड़े थे। जहां तक यूरोपीय देशों की बात है, उनमें से ज्यादातर अपनी घरेलू राजनीतिक बाध्यताओं से जूझ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से इन देशों के संसाधनों पर जो दबाव पड़ा है, उससे यहां युद्ध विरोधी भावनाएं और सैन्य हस्तक्षेप के प्रति संदेह बढ़ा है, और इसीलिए वे किसी नए सैन्य अभियान में शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व के अन्य देशों में अमेरिकी विदेश नीति को लेकर संशय तो बढ़ा ही है, कोई भी देश पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होकर अपनी सुरक्षा व आर्थिक हितों को जोखिम में नहीं डालना चाहता। वैश्विक व्यवस्था के लिहाज से यह स्थिति जटिलता बढ़ाने वाली ही है कि खुद अमेरिका अपने सहयोगियों को ऐसी लड़ाई में खींचने की कोशिश कर रहा है, जिससे वे बचना चाहते हैं। अब ट्रंप यह कहने को मजबूर हुए हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन यह पूरा प्रकरण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सबक है। यह स्थिति अमेरिका की एकध्रुवीय शक्ति के युग के कमजोर होने का भी संकेत है, जब सहयोगी बिना सवाल उठाए अमेरिकी आदेशों का पालन नहीं कर रहे। यह समय है, जब सभी पक्ष कूटनीति की ओर लौटें। युद्ध विनाश और तबाही ही फैलाते हैं। होर्मुज को खोलने के लिए सैन्य बल से ज्यादा जरूरी यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय संवाद-उन्मुख हो।

धमाके जो कभी हुए ही नहीं

पश्चिम एशिया के संघर्ष में एआई युद्ध का टूल बन गया है, जिससे तैयार फर्जी वीडियो व तस्वीरें ईरान की रणनीति का अहम हिस्सा बन गई हैं। इनके जरिये डर व सहानुभूति पैदा करने के साथ यह संदेश भी दिया जा रहा है कि युद्ध अमेरिका व उसके साथियों के लिए कहीं ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ है।

ईरान में चल रहे युद्ध के शुरुआती हफ्तों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार किए गए तमाम फर्जी वीडियो और तस्वीरों ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इन वीडियो में ऐसे भयावह और चौंकाने वाले दृश्य दिखाए जा रहे हैं- जैसे विशाल धमाके, जो कभी हुए ही नहीं; तबाह पड़ी शहरों की सड़कें, जिन पर हमला नहीं हुआ; या युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करते सैनिक, जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं है। इन दृश्यों ने युद्ध को और भी अधिक अराजक, भ्रामक और उलझन भरा बना दिया है। ये फर्जी सामग्रियां युद्ध के हर पहलू को दिखाने की कोशिश करती हैं-कहीं तेल अवीव में धमाकों के बीच सहमे और चीखते इस्राइली नागरिकों के झूठे दृश्य दिखाए गए हैं, तो कहीं ईरान में अपने मृतकों पर शोक जताते लोगों की काल्पनिक तस्वीरें पेश की गई हैं। यहां तक कि अमेरिकी सैन्य जहाजों पर मिसाइल और टॉरपीडो से हमले के गढ़े हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं।

स्टुअर्ट ए थॉम्पसन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

झूठ और भ्रामक जानकारी के इस मायाजाल को एक्स (पहले ट्विटर), टिकटॉक और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों बार देखा गया, और निजी मैसेजिंग एप्स के जरिये यह गलत जानकारी दुनिया भर के लोगों तक तेजी से पहुंची। आज के दौर में आधुनिक एआई उपकरणों ने इस तरह के फर्जी कंटेंट बनाना बेहद आसान कर दिया है। कोई भी व्यक्ति असली लगने वाले ऐसे वीडियो बना सकता है, जो आम लोगों को आसानी से भ्रमित कर सकते हैं।

हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इस तरह की चीजें सामने आई थीं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के बाद से युद्ध आधारित फर्जी कंटेंट की बाढ़ आ गई है। कतर की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मीडिया एनालिटिक्स के प्रोफेसर मार्क ओवेन जोंस के मुताबिक, 'यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की तुलना में आज स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। हम शायद आज इतिहास में सबसे अधिक एआई-जनित कंटेंट का सामना कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया।' एआई से तैयार यह कंटेंट अब तेहरान के लिए एक मजबूत सूचनात्मक हथियार बन गया है। इसके जरिये युद्ध की डरावनी और तबाही भरी तस्वीरें दिखाकर लोगों के मन में युद्ध को लेकर डर, बेचैनी और सहानुभूति पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। सोशल मीडिया एनालिसिस कंपनी सायब्रा की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे ज्यादातर एआई वीडियो ईरान के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं और उसकी सैन्य ताकत और तकनीक को हकीकत से ज्यादा बड़ा दिखाते हैं। जोंस का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र की एआई से बनी ऐसी तस्वीरें, जिनमें शहरों को जलता या टूटता हुआ दिखाया जाता है, ईरान की रणनीति का अहम हिस्सा बन गई हैं। उनका कहना है कि इन तस्वीरों के जरिये यह संदेश देने की कोशिश होती है कि यह युद्ध अमेरिका के सहयोगियों के लिए हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक और नुकसानदायक साबित हुआ है।

ऑनलाइन वायरल हुए सबसे ज्यादा शेयर किए गए नकली वीडियो में से एक में तेल अवीव के एक अपार्टमेंट की बालकनी से लिया गया हिलता-डुलता दृश्य दिखाया गया है। इसमें शहर के आसमान में मिसाइल हमले होते नजर आते हैं और सामने इस्राइली झंडा भी दिखाई देता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इन वीडियो में दिखाई देने वाला गलत इस्राइली झंडा ही उनके फर्जी और एआई से बना होने का सबसे बड़ा सुराग है। दूसरी तरफ, असली युद्ध के वीडियो भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, जिन्हें लोग अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिये तुरंत साझा कर रहे हैं। ये असली वीडियो, एआई से बनाए गए वीडियो के मुकाबले ज्यादा शांत और सामान्य लगते हैं। असली वीडियो में मिसाइल हमले अक्सर रात के वक्त और काफी दूरी से रिकॉर्ड किए जाते हैं, जहां मिसाइलें आसमान में केवल रोशनी के चमकते बिंदुओं जैसी दिखती हैं। इसके उलट, कई एआई वीडियो और तस्वीरों में युद्ध को एक फिल्मी अंदाज में दिखाया गया है, मानो कोई हॉलीवुड एक्शन फिल्म चल रही हो। इनमें बड़े-बड़े धमाके, मशरूम जैसे उठते बादल, शहरों को हिला देने वाली 'सोनिक बूम' की लहरें और आसमान में चमचमाती हाइपरसोनिक मिसाइलें दिखाई जाती हैं। कुछ मामलों में असली वीडियो को भी एआई की मदद से और ज्यादा नाटकीय बना दिया जाता है, ताकि धमाके ज्यादा बड़े और खतरनाक लगें। इससे असली और नकली के बीच फर्क करना और मुश्किल हो जाता है।

दर्जनों अन्य एआई तस्वीरों और वीडियो ने तो यह छिपाने की कोशिश भी नहीं की कि वे नकली हैं, बल्कि वे एक तरह के डिजिटल प्रचार (प्रोपेगेंडा) की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिनका मकसद सरकारों या उनके समर्थकों के विचारों को मजबूत तरीके से दिखाना था। इनमें विश्व नेताओं को शक्तिशाली पुरुषों के रूप में महिमामंडित करने वाले चित्रण, या विपक्षी नेताओं को अमानवीय रूप में दिखाने वाले चित्रण भी शामिल थे। इसी तरह, एक पूरी तरह काल्पनिक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल का दृश्य दिखाया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी को अमेरिका द्वारा एक कथित तौर पर गलती से दागी गई मिसाइल इस स्कूल पर गिर गई थी। ईरानी अधिकारियों का दावा था कि इस हमले में कम से कम 175 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। एआई से बनाए गए इन वीडियो को छोटी फिल्मों की तरह पेश किया गया, जिनमें पहले स्कूल की बच्चियों को खेलते हुए दिखाया जाता है, और फिर अचानक एक अमेरिकी लड़ाकू विमान आकर मिसाइल दाग देता है।

इस सबके बावजूद, सोशल मीडिया कंपनियां अब तक एआई से बने फर्जी वीडियो की समस्या को रोकने के लिए ज्यादा ठोस कदम नहीं उठा पाई हैं। हालांकि, अब एक्स ने ऐलान किया है कि जो खाते सशस्त्र संघर्ष जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ा एआई कंटेंट बिना यह बताए पोस्ट करेंगे कि वह नकली है, उन्हें 90 दिनों तक कमाई करने से रोका जाएगा। इसका मकसद उपयोगकर्ताओं को गलत जानकारी से फायदा उठाने से रोकना है। सायब्रा की जांच में सामने आया कि ईरान से जुड़े कई खातों का मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की फेलो और विदेश नीति व एआई पर काम करने वाली वैलेरी विर्टशाफ्टर के अनुसार, एआई भी एक तरह का युद्ध का हथियार बन चुका है।

- साथ में अलेक्जेंडर कार्डिया *©The New York Times 2026*

जीवन धारा

सेनेका

हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए जी रहा है, पर स्वयं के लिए नहीं। हम दूसरों से समय व ध्यान की अपेक्षा करते हैं, पर स्वयं को समय देना भूल जाते हैं। यदि हम अपने भीतर झांकना सीख लें, तो जीवन का अर्थ प्रकट हो जाएगा।

खुद के लिए भी जीना सीखें

हम प्रकृति की शिकायत क्यों करते हैं? उसने तो हमें जीवन का उदार और पर्याप्त विस्तार दिया है। वास्तव में जीवन लंबा है, यदि हम उसे समझदारी और सजगता से जीना सीख लें। लेकिन मनुष्य स्वयं ही अपनी मूर्खताओं और दुर्बलताओं के कारण इसे छोटा बना लेता है। कोई असीम लालच में उलझा रहता है, तो कोई उन कार्यों में अपना समय नष्ट करता है, जिनका कोई महत्व नहीं होता। कोई मदिरा और भोग-विलास में डूबकर अपनी चेतना खो देता है, तो कोई आलस्य के कारण अपनी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। कुछ लोग महत्वाकांक्षा के ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जो दूसरों की स्वीकृति और निर्णयों पर निर्भर करता है। वे स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की दृष्टि में महान बनने के लिए जीते हैं। कुछ लोग व्यापार तथा लाभ की लालसा में दूर-दूर तक भटकते हैं, समुद्रों और देशों की यात्राएं करते हैं, लेकिन उनके भीतर शांति का अभाव बना रहता है। कुछ लोग युद्ध के जुनून से पीड़ित हैं और हमेशा या तो दूसरों को खतरे में डालने की फिराक में रहते हैं, या फिर अपने ही खतरे की चिंता में डूबे रहते हैं।

कुछ ऐसे भी हैं, जो बड़े और शक्तिशाली लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जहां उन्हें न तो सम्मान मिलता है और न ही संतोष। कई लोग दूसरों की सफलता के पीछे भागते हैं, जबकि कुछ अपनी असफलताओं का विलाप करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं बनाते। वे चंचल, अस्थिर और असंतुष्ट रहते हैं, और हर समय नई-नई योजनाओं में उलझे रहते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन को वास्तव में जीते नहीं, बल्कि केवल समय बिताते हैं। जैसा कि एक महान कवि ने कहा है, 'जीवन का वही अंश सच्चा है, जिसे हम जागरूकता और अर्थ के साथ जीते हैं; शेष सब केवल समय का प्रवाह है।' हमारे दोष, वासनाएं और इच्छाएं हमें चारों ओर से जकड़ लेती हैं। वे हमें ऊपर उठने और सत्य को देखने नहीं देतीं, बल्कि हमें अपने बंधनों में बांधकर रखती हैं। यह केवल उन लोगों की बात नहीं है, जो दुखी हैं। उन लोगों को भी देखिए, जिनकी सफलता और समृद्धि की लोग प्रशंसा करते हैं। वे भी अपने ही वैभव के बोझ तले दबे रहते हैं। धन, प्रसिद्धि और निरंतर प्रदर्शन की चाह उन्हें थका देती है। कुछ लोग निरंतर सुखों के पीछे भागते-भागते भीतर से रिक्त हो जाते हैं।

हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए जी रहा है, पर स्वयं के लिए नहीं। कोई भी अपने जीवन का स्वामी नहीं रह गया है। लोग दूसरों से समय और ध्यान की अपेक्षा करते हैं, पर स्वयं को समय देना भूल जाते हैं। सच्चाई यह है कि हम दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से दूर हो चुके हैं। यदि हम अपने भीतर झांकना सीख लें, स्वयं को सुनना और समझना शुरू कर दें, तो जीवन का वास्तविक अर्थ हमारे सामने अपने आप प्रकट हो जाएगा। *-ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ के अनूदित अंश*

जीवन को व्यर्थ न गंवाएं

सूत्र

प्रकृति ने जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाया है, पर मनुष्य अपनी इच्छाओं, लालच और अस्थिरता में उसे व्यर्थ कर देता है। जो स्वयं को समझना सीख लेता है, वही जीवन को सच में जीता है, क्योंकि सच्चा जीवन वही है, जिसमें हम अपने भीतर झांककर शांति, उद्देश्य और आत्मबोध को प्राप्त करते हैं।

दूसरा पहलू

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 11 से 15 वर्ष के करीब 10 से 13 फीसदी किशोरों में समस्या-जनक सोशल मीडिया उपयोग के लक्षण पाए गए हैं।

सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना क्यों जरूरी है

हाल ही में, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत सहित अन्य देशों से अपील की कि वे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु-आधारित प्रतिबंध लागू करने पर गंभीरता से विचार करें। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की न्यूनतम आयु-सीमा तय करने की दिशा में ठोस पहल की है, जबकि फ्रांस में भी 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन मंचों से दूर रखने के उपायों पर चर्चा चल रही है।

सुभाष चंद्र कुशवाहा

प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले किशोरों में अवसाद के लक्षणों की संभावना करीब 60 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

यूनिसेफ के अनुसार, विश्व स्तर पर प्रत्येक तीन में से एक बच्चा साइबर उत्पीड़न का अनुभव कर चुका है। भारत में फर्जी प्रोफाइल, ऑनलाइन धमकी और यौन शोषण की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, 11 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10 से 13 प्रतिशत किशोरों में समस्या-जनक सोशल मीडिया उपयोग के लक्षण पाए गए, जो अवसाद, चिंता और नींद की कमी से जुड़े हैं। पिउ रिसर्च सेंटर के 2022 के सर्वेक्षण में 59 प्रतिशत अमेरिकी किशोरों ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। *जर्नल ऑफ अडोलेसेंट हेल्थ* में 2019 से 2023 के बीच प्रकाशित अध्ययनों में यह निष्कर्ष सामने आया कि प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले किशोरों में अवसाद के लक्षणों की संभावना लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इस तरह बनाए जाते हैं कि वे 'डोपामिन चक्र' उत्पन्न करते हैं। लाइक, टिप्पणी और सूचनाएं बच्चों को बार-बार स्क्रीन की ओर आकर्षित करती हैं। यह निरंतर उत्तेजना मस्तिष्क के विकासशील भागों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और किशोरों को वास्तविक जीवन से दूर कर सकती है।

यूनिसेफ के अनुसार, विश्व स्तर पर प्रत्येक तीन में से एक बच्चा साइबर उत्पीड़न का अनुभव कर चुका है। भारत में चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) तथा अन्य संगठनों की रिपोर्टें बताती हैं कि फर्जी प्रोफाइल, ऑनलाइन धमकी और यौन शोषण की घटनाओं में वृद्धि हुई है। भारत के संदर्भ में यह बहस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में किशोर तेजी से डिजिटल जगत से जुड़ रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्मार्टफोन की उपलब्धता बढ़ी है, परंतु डिजिटल साक्षरता का स्तर समान रूप से विकसित नहीं हुआ। ऐसे में, नीति-निर्माताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश, आयु सत्यापन की प्रभावी व्यवस्था और बच्चों के लिए सुरक्षित तथा शैक्षणिक मंचों को प्रोत्साहन देना होगा। प्रतिबंध का उद्देश्य बच्चों को तकनीक से दूर करना नहीं, बल्कि उनके परिपक्व आयु तक पहुंचने से पूर्व अनियंत्रित और संभावित रूप से हानिकारक माहौल में पड़ने से बचाना होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राज्य और समाज का भी सामूहिक उत्तरदायित्व है।

आंकड़े

नींद है जरूरी

71 फीसदी भारतीय कर्मचारी मानते हैं कि कम नींद उत्पादकता को प्रभावित करती है। तनाव व चिंता नींद न आने के सबसे बड़ा कारण बनकर उभरे हैं।

तनाव	39
कॅरिअर की चिंता	39
काम का बोझ	37
चिड़चिड़ापन	35
घरेलू जिम्मेदारियां	31

आंकड़े नींद न आने के विभिन्न कारणों के, प्रतिशत में | स्रोत : रेस्मेड ग्लोबल स्लीप सर्वे 2026

राजा सगर के पुत्र शाप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रही थीं। मां गंगा के पवित्र स्पर्श से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ।

मां गंगा ने दिलाया मोक्ष

पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा सगर के वंश में कई प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुए, परंतु उनके वंश पर एक गंभीर संकट आ पड़ा। राजा सगर के साठ हजार पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रही थीं। इस दुखद स्थिति से मुक्ति का एक ही उपाय था कि स्वर्ग से मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनके अस्थि-अवशेषों को स्पर्श करें।

इस महान उद्देश्य को लेकर राजा सगर के पौत्र दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुईं, पर उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रचंड वेग धरती सहन नहीं कर पाएगी और सब कुछ विनष्ट हो जाएगा।

अंतर्यात्रा
संकलित

तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब माता गंगा धरती पर अवतरित हुईं, तो भोलेनाथ ने उनके वेग को अपनी जटाओं में समाहित कर उसे नियंत्रित किया और फिर धीरे-धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया।

भगीरथ गंगा के प्रवाह के साथ आगे बढ़ते हुए उस स्थान तक पहुंचे, जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। मां गंगा के पवित्र जल के स्पर्श मात्र से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। अतः मनुष्य अपनी भक्ति से असंभव को भी संभव बना सकता है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 18 मार्च, 1959

नहरी पानी विवाद के लिए एक और योजना

नहरी पानी विवाद के लिये एक और योजना

विश्व बैंक के चेयरमैन यूजीन रॉबर्ट ब्लैक ने बताया कि विश्व बैंक नहरी पानी विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहा है। मई तक भारत व पाकिस्तान के सामने एक और योजना रखी जाएगी, जिस पर इंजीनियरों व आर्थिक सलाहकार, दोनों ने विचार कर लिया है।

पश्चिमी मोर्चे पर घिरा पाकिस्तान

ईरान व अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान को ऐसे भू-राजनीतिक संकट में ला दिया है, जिसे न वह अनदेखा कर सकता है, न संभाल सकता है।

केएस तोमर — मुद्दा

आज पाकिस्तान अपने हालिया इतिहास के सबसे जटिल रणनीतिक क्षणों में से एक से गुजर रहा है। उसके पश्चिम पड़ोस में हो रहे घटनाक्रमों, विशेष रूप से ईरान के आसपास की उथल-पुथल और अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ तेजी से बिगड़ते संबंध, ने ऐसा भू-राजनीतिक दबाव पैदा कर दिया है, जिसे वह न तो अनदेखा कर सकता है और न ही आसानी से संभाल सकता है। पाकिस्तान खुद को अनिश्चितता, आतंकी प्रतिक्रिया और भू-राजनीतिक जोखिमों से घिरा हुआ पाता है, जो आने वाले वर्षों में उसके सुरक्षा परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकते हैं।

पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा शायद ही कभी शांत रही हो, लेकिन मौजूदा हालात असामान्य रूप से पेचीदा हैं। ईरान महज एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि एक अहम भू-राजनीतिक और आर्थिक साझेदार भी है। दोनों देशों की सीमा बलूचिस्तान के दुर्गम इलाके से गुजरती है, जो लंबे समय से अस्थिर रहा है। ईरान में उथल-पुथल से सीमा पार सक्रिय अलगाववादी नेटवर्क के मजबूत होने और अशांत प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षा हालात के और पेचीदा होने का खतरा है। इसके अलावा, पाकिस्तान लंबे समय से ऊर्जा की कमी से भी जूझ रहा है, इसलिए ईरानी गैस उसके लिए आकर्षक विकल्प रही है। ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रतिबंधों और राजनीतिक दबावों के कारण रुकी हुई है। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है, तो इस परियोजना में और अधिक देरी हो सकती है या यह पूरी तरह रुक सकती है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरियां और बढ़ जाएंगी।

इसके अलावा, ईरान के बाहर, शिया आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में ही रहता है। ईरान से जुड़ा कोई भी संघर्ष पाकिस्तान के भीतर सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है। इसलिए, ईरान में होने वाली उथल-पुथल का असर पाकिस्तान में बहुत जल्द महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव भी एक अन्य समस्या है। पाकिस्तान का मानना था कि काबुल में एक दोस्ताना शासन होने से अफगानी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा और वहां भारत का प्रभाव सीमित रहेगा। पर 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद दोनों के रिश्ते धीरे-धीरे खराब होते चले गए।

सबसे बड़ा विवाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की मौजूदगी को लेकर है, जिसने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है। यह तनाव समय-समय पर खुलकर टकराव में बदलता रहा है। अफगान सीमा के पार कथित उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी हवाई हमलों और तालिबान नेताओं की जवाबी कार्रवाई ने दोनों के रिश्तों को खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। डूरंड रेखा विवाद इस स्थिति को और जटिल बना देता है। इसके बावजूद, इस्लामाबाद के कुछ रणनीतिकारों को क्षेत्रीय उथल-पुथल से कुछ सीमित अवसर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यदि ईरान बाहरी दबावों में उलझ जाता है, तो हो सकता है कि बलूच सीमा पर पाकिस्तान को ईरान की तरफ से कम निगरानी का सामना करना पड़े। इसी तरह, अफगानिस्तान का गहरा आर्थिक संकट अंततः तालिबान नेतृत्व को इस्लामाबाद के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर वार्ता के लिए मजबूर कर सकता है, खासकर तब, जब उन्हें व्यापारिक पहुंच या वित्तीय सहयोग की आवश्यकता हो। लेकिन ये केवल अनुमान हैं। असल में, जोखिम अवसरों पर भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर चल रही मुश्किलें उसके सैन्य व खुफिया संसाधनों पर दबाव डालती हैं, जिससे उसकी पूर्वी सीमा पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर भी, भारत यह मानकर नहीं चल सकता कि पाकिस्तान के पड़ोस में अस्थिरता उसके लिए रणनीतिक लाभ बन जाएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती अस्थिरता से उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां पूरे क्षेत्र में फैल सकती हैं। कट्टरपंथी नेटवर्क मजबूत हो सकते हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति और जटिल हो सकती है। इसलिए, भारत इन घटनाक्रमों को सावधानी से देखता है। इस बदलती हुई स्थिति में एक और अहम खिलाड़ी चीन है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर जारी अस्थिरता वहां चीन के निवेश और क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं के लिए भी खतरा पैदा करती है। इसके अलावा, अफगानिस्तान में सक्रिय उग्रवादी नेटवर्क उसके शिनजियांग क्षेत्र में मौजूद चरमपंथी समूहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, बीजिंग ने इस्लामाबाद और काबुल के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया है।

ईरान व अफगानिस्तान की तनावपूर्ण स्थितियों ने पाकिस्तान को एक अहम मोड़ पर ला खड़ा किया है। अगर उसकी पश्चिमी सीमा पर अस्थिरता बढ़ती है, तो इस्लामाबाद को लंबे समय तक चलने वाले सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक सुधार व घरेलू प्रशासन पर ध्यान देना कठिन हो जाएगा। उसे क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक एकीकरण और उग्रवादी समूहों पर निर्भरता से दूरी बनाने को प्राथमिकता देनी होगी। पर यह आसान नहीं होगा। edit@amarujala.com

एजुकेशन & कॅरिअर

यदि व्यक्ति कुछ सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है।

Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

कॉन्स्टेबल के पदों पर करें आवेदन

827 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 20 अप्रैल, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 23, 25 व 27 वर्ष
यहां आवेदन करें : ssb.gov.in

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिक्तियां ■ 195 पद

प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-I रिक्रूटमेंट एग्जाम-2026
आवेदन की अंतिम तिथि
01 अप्रैल, 2026
वेतनमान
रुपये 56,100 से लेकर रुपये 1,77, 500 तक निर्धारित
यहां आवेदन करें
allahabadhighcourt.in

एनएचपीसी लिमिटेड में संभावनाएं ■ 72 पद

ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि
06 अप्रैल, 2026
योग्यताएं
बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
nhpcindia.com

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ■ 373 पद

कंपाउंडर, टेक्नीशियन व अन्य पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 30 मार्च, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : esb.mp.gov.in

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ■ 59 पद

जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर व अन्य पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
05 अप्रैल, 2026
पात्रताएं
इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
nbccindia.in

सचिवालय सुरक्षा बल में रिक्तियां ■ 10 पद

कॉन्स्टेबल के पदों पर योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि
28 अप्रैल, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
mha.gov.in

यहां भी रोजगार के अवसर...

- मुंबई पत्तन प्राधिकरण : अग्निशमन अधिकारी का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 27 मार्च, 2026
- mumbaiport.gov.in
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश : डिजाइनर, फैकल्टी आदि के पदों पर रिक्तियां।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 30 अप्रैल, 2026
- nidmp.ac.in/careers/

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

प्रभावी प्रोफाइल से मिलेंगे नौकरी के मौके

प्रभावशाली और पेशेवर ऑनलाइन प्रोफाइल नियोक्ताओं पर अच्छा असर डालती हैं और आपको बेहतर नौकरी के अवसर दिला सकती हैं

रेबेका नाइट
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

आज के समय में नौकरी पाना केवल रिज्यूमे भेजना या आवेदन भेजने तक सीमित नहीं रह गया है। डिजिटल दुनिया में आपकी ऑनलाइन मौजूदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल, पोस्ट और गतिविधियां यह दिखाती हैं कि आप पेशेवर रूप से कितने गंभीर, सक्रिय और सक्षम हैं। अब कंपनियां केवल उम्मीदवारों के आवेदन का इंतजार नहीं करतीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये खुद भी योग्य प्रतिभाओं को खोजती हैं। ऐसे में, यदि आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल प्रभावशाली और पेशेवर है, तो यह नियोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और नौकरी के बेहतर अवसर दिलाने में मदद करती है।

Harvard Business Review

■ अनावश्यक जानकारी हटा दें

नौकरी खोजने से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिजिटल सफाई कर लें। सार्वजनिक प्रोफाइल से अनावश्यक या संवेदनशील जानकारी हटा दें और निजी अकाउंट्स को प्राइवेट कर दें। साथ ही कोई भी जानकारी पोस्ट करने से पहले सोच-समझकर फैसला लें, क्योंकि आज कंपनियां एआई और डाटा एनालिटिक्स की मदद से उम्मीदवारों की ऑनलाइन जानकारी आसानी से देख सकती हैं।

■ जरूरी कीवर्ड शामिल करें

सोशल मीडिया पर मजबूत नेटवर्क बनाना जरूरी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों और अवसरों से जुड़ सकें। इसके लिए लिंक्डइन और ग्लासडोर जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल आकर्षक और पूरी जानकारी के साथ बनाएं। अपनी प्रोफाइल में अपने अनुभव, काम और उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से लिखें। जिन कंपनियों में आप काम करना चाहते हैं, उनके जॉब पोस्ट देखकर उसी तरह के जरूरी कीवर्ड भी अपनी प्रोफाइल में शामिल करें। कॅरिअर की शुरुआत में अपने काम और जिम्मेदारियों के बारे में बताना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे अपनी उपलब्धियों और कौशलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

■ नकारात्मक बातों का जिक्र न करें

अगर आपने हाल ही में स्नातक किया है, तो अपनी प्रोफाइल में डिग्री, कौशल और उपलब्धियां स्पष्ट रूप से

लिखें और यह भी बताएं कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर नौकरी चली भी गई है, तो उसे नकारात्मक तरीके से पेश करने के बजाय अपने अनुभव और कौशल को सकारात्मक रूप में दिखाएं। वहीं, अगर आप वर्तमान नौकरी में रहते हुए नई नौकरी खोज रहे हैं, तो इसे सार्वजनिक करने के बजाय लिंक्डइन की मदद से केवल रिक्रूटर्स को संकेत दें कि आप नए अवसरों के लिए तैयार हैं।

■ नई जानकारी साझा करते रहें

सोशल मीडिया पर केवल एक पोस्ट करना काफी नहीं है। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने काम, उपलब्धियों या नई सीख से जुड़ी पोस्ट साझा करें और दूसरों की पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दें। साथ ही, शिकायत या नकारात्मक बातें लिखने से बचें, क्योंकि भर्ती करने वाले अक्सर सोशल मीडिया देखते हैं और ऐसी बातें आपके अवसरों को प्रभावित कर सकती हैं।

आवेदन आमंत्रित

एनवाईयू स्टर्न फेलोशिप-2026

एनवाईयू स्टर्न फेलोशिप-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह पूरी तरह से वित्त पोषित फेलोशिप है, जो 17 से 18 सितंबर, 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह फेलोशिप दुनिया भर के पत्रकारों-जैसे रिपोर्टर, संपादक और फ्रीलांसर के लिए खुली है। इसका उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों को आमंत्रित करना है, जो जलवायु परिवर्तन, वित्तीय बाजारों और व्यापक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर्संबंधों का अध्ययन करने में रुचि रखते हों।

इस कार्यक्रम के लिए अर्थशास्त्र में पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, फेलो को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सेंट्रल पार्क और टाइम्स स्क्वायर जैसे न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित स्थलों का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। फेलोशिप के तहत यात्रा, आवास और अन्य सभी खर्च कार्यक्रम द्वारा वहन किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक tinyurl.com/3hewx2nj पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से इस फेलोशिप प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं।

इंटर्नशिप अलर्ट

डब्ल्यूआईपीओ इंटर्नशिप रोस्टर-2026

डब्ल्यूआईपीओ इंटर्नशिप रोस्टर-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह एक पूर्णतः वित्त-पोषित इंटर्नशिप है। यह इंटर्नशिप बौद्धिक संपदा, नवाचार और रचनात्मकता के क्षेत्र में कार्य करती है, इसलिए प्रतिभागियों को वैश्विक स्तर पर अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस इंटर्नशिप की अवधि 12 सप्ताह से एक साल तक होती है। विश्वविद्यालय में पढ़ रहे या हाल ही में डिग्री पूरी कर चुके छात्र आवेदन कर सकते हैं। स्नातक छात्रों के लिए तीसरे या चौथे वर्ष में होना आवश्यक है। साथ ही वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामों का ज्ञान होना जरूरी है। स्नातक छात्रों को आवास, भोजन और स्थानीय परिवहन के लिए 1,645 स्विस फ्रैंक का मासिक वजीफा दिया जाएगा, जबकि स्नातकोत्तर छात्रों को 2,170 स्विस फ्रैंक प्रतिमाह मिलेंगे। आवेदक आधिकारिक लिंक tinyurl.com/ejm62k7n पर जाकर 04 जुलाई, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट हफ्ते की परीक्षाएं

एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा

- परीक्षा की तिथि : 22 मार्च, 2026
- इस परीक्षा के खंड-अ में सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न, जबकि खंड-ब में इंजीनियरिंग विषय से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक निर्धारित हैं और परीक्षा की कुल अवधि तीन घंटे है।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें
  mppsc.mp.gov.in/Admitcard

राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर मुख्य परीक्षा

- परीक्षा की तिथि : 22 मार्च, 2026
- इस परीक्षा में पेपर-I में हिंदी तथा पेपर-II में इंजीनियरिंग विषय से 100-100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि पेपर-III और पेपर-IV में वैकल्पिक विषय से 200-200 अंकों के प्रश्न शामिल होंगे।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें
  sso.rajasthan.gov.in

खुद को परखें

1. हाल ही में खबरों में आई एम्ब्लीसेप्स वायवी किस प्रजाति से संबंधित है?
   (a) कैटफिश
   (b) मकड़ी
   (c) मेंढक
   (d) चींटी

2. गजपति साम्राज्य एक मध्यकालीन हिंदू राजवंश था, जिसकी उत्पत्ति वर्तमान में भारत के किस राज्य से हुई थी?
   (a) ओडिशा (b) बिहार
   (c) केरल (d) महाराष्ट्र

3. हाल ही में खबरों में आई वैलेस मेरिनेरिस किस ग्रह पर स्थित एक विशाल घाटी प्रणाली है?
   (a) शुक्र (b) चंद्रमा
   (c) बृहस्पति (d) मंगल

उत्तर : 1.a, 2.a, 3.d

सामान्य ज्ञान

परमाणु घड़ी

■ क्या है

परमाणु घड़ी बहुत सटीक समय बताने वाली घड़ी होती है, जो परमाणुओं के कंपन से काम करती है।

■ चर्चा में क्यों

हाल ही में इसरो ने बताया कि आईआरएनएसएस-1एफ उपग्रह में लगी परमाणु घड़ी खराब हो गई है। इसके कारण नेविक प्रणाली में सही तरीके से काम करने वाले उपग्रहों की संख्या कम हो गई है।

■ यह कैसे काम करती है?

परमाणु घड़ी तरंगों के आधार पर बेहद सटीक समय मापती है। उपग्रह समय के साथ सिग्नल भेजते हैं, जिनसे दूरी निकाली जाती है और चार या अधिक उपग्रहों की मदद से किसी स्थान की सटीक स्थिति पता चलती है।

■ उच्च सटीकता

यह बहुत सटीक होती है और बहुत लंबे समय तक भी कम गलती करती है। उपग्रहों में कई घड़ियां होती हैं, ताकि एक खराब हो जाए, तो दूसरी काम करे। अब नई एनवीएस शृंखला में भारत में बनी घड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं।

टेक-टॉक

Gadgets Ai Technology

अंगूर से बैटरी रीसाइकिलिंग

वैज्ञानिकों ने बैटरी रीसाइकिलिंग के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी तकनीक विकसित की है। इसके जरिये अंगूर में पाए जाने वाले टारटरिक अम्ल का उपयोग कर धातुओं को अलग किया जा सकता है।

आधुनिक तकनीकों जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और जेट इंजन के तेजी से बढ़ते उपयोग ने उच्च-प्रदर्शन सामग्रियों और बैटरियों की मांग को काफी बढ़ा दिया है। इन तकनीकों में कोबाल्ट और निकेल जैसी धातुएं मुख्य भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनकी बढ़ती खपत के साथ एक गंभीर चुनौती भी सामने आई है-पुरानी बैटरियों और औद्योगिक कचरे से इन धातुओं का प्रभावी पुनर्चक्रण। दरअसल, कोबाल्ट और निकेल रासायनिक रूप से समान होते हैं, जिससे इन्हें अलग करना जटिल और महंगा बन जाता है।

अब वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक पर्यावरण-अनुकूल तरीका खोजा है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध में पाया गया कि अंगूर में पाया जाने वाला प्राकृतिक टारटरिक अम्ल धातुओं के पृथक्करण को सरल बना सकता है। यह खोज बैटरी रीसाइकिलिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

■ जटिल प्रक्रिया : वर्तमान में कोबाल्ट और निकेल का उपयोग लिथियम-आयन बैटरियों, सुपरएलॉय और औद्योगिक उत्प्रेरकों में बड़े पैमाने पर होता है। बढ़ती मांग के चलते भविष्य में इनकी कमी और कीमतों में वृद्धि की आशंका है। ऐसे में इन धातुओं का पुनर्चक्रण बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि मौजूदा तकनीकें महंगी हैं, कठोर रसायनों पर निर्भर हैं और कई जटिल चरणों से गुजरती हैं।

■ इलेक्ट्रोविनिंग तकनीक : नए शोध में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोविनिंग तकनीक का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में बिजली की मदद से तरल घोल से धातुओं को अलग कर किसी सतह पर जमा किया जाता है। यह प्रक्रिया धातु चढ़ाने (इलेक्ट्रोप्लेटिंग) के जैसी होती है, लेकिन समस्या यह थी कि कोबाल्ट और निकेल दोनों ही बिजली के प्रति लगभग समान व्यवहार करते हैं, जिससे वे एक साथ जमा हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें अलग करना कठिन हो जाता है।

■ टारटरिक अम्ल कारगर : इस समस्या के समाधान के लिए शोधकर्ताओं ने विभिन्न जैविक अम्लों का परीक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन-सा अम्ल धातु आयनों के साथ अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कुल 13 अम्लों के परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि टारटरिक अम्ल निकेल आयनों के साथ अधिक मजबूत बंधन बनाता है। परिणामस्वरूप, निकेल घोल में ही बना रहता है, जबकि कोबाल्ट पहले अलग होकर सतह पर जमा हो जाता है। इस क्रमिक प्रक्रिया से दोनों धातुओं को प्रभावी ढंग से अलग किया जा सकता है। शोध की पुष्टि के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन भी किए गए, जिनसे यह साबित हुआ कि टारटरिक अम्ल वास्तव में निकेल के साथ अधिक स्थिर संयोजन बनाता है। प्रारंभिक छोटे पैमाने के परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने 99.1 प्रतिशत कोबाल्ट सफलतापूर्वक निकाल लिया। बाद में जब इस तकनीक को बड़े और निरंतर प्रवाह वाले सिस्टम में लागू किया गया, तब भी परिणाम प्रभावशाली रहे।

■ पर्यावरण अनुकूल : वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विधि बैटरी रिसाइकिलिंग को सस्ता, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बना सकती है। साथ ही, यह तकनीक अन्य महत्वपूर्ण धातुओं को अलग करने में भी उपयोगी हो सकती है। अभी इस पर शोध जारी है। यदि यह औद्योगिक स्तर पर सफल होती है, तो यह वैश्विक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बिना इंटरनेट भी चला सकेंगे व्हाट्सएप

आपके मोबाइल में नेट नहीं है या रीचार्ज नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब बिना इंटरनेट के भी आपका व्हाट्सएप चलेगा। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन्स में एक नया फीचर दिया है, जिससे सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स पर बिना इंटरनेट के भी कई एप्स चलेंगे। ये एप्स सेटेलाइट रेडी एप्स हैं, जो बिना मोबाइल इंटरनेट के भी चलते हैं।

कंपनी ने इसके लिए मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ भागीदारी की है। एप्पल जहां सेटेलाइट इंटरनेट कंपनियों पर निर्भर करती है, वहीं सैमसंग लोकल नेटवर्क ऑपरेटर्स पर निर्भर करती है। कुछ देशों में सेटेलाइट कनेक्टिविटी केवल इमरजेंसी सर्विस मुहैया करवाती है, वहीं सैमसंग के गैलेक्सी फोन कई एप्स भी चलाने की सहूलियत देते हैं।

कॉपी-पेस्ट करने वालों की होगी शिकायत

फेसबुक पर कॉपी-पेस्ट वाले कंटेंट की भरमार रहती है। इन्हें रोकने के लिए मेटा ने कदम उठाए हैं। कंपनी ने क्रिएटर्स के ओरिजिनल कंटेंट की सुरक्षा के लिए नए टूल और अपडेटेड कंटेंट गाइडलाइंस पेश किए हैं। मेटा के अनुसार, इन नए फीचर्स का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे कॉपी कंटेंट और स्पैम को कम करना है। इसके तहत क्रिएटर्स को एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड दिया जाएगा, जहां से वे आसानी से अपने कंटेंट की कॉपी या दुरुपयोग की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलने के बाद मेटा की टीम ऐसे कंटेंट की जांच करेगी और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर पोस्ट हटाने, रीच कम करने या अकाउंट पर कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

आने वाली है

जल्द ही सड़कों पर दौड़ेगी टाटा सिएरा ईवी

अब बहुत जल्द बाजार में टाटा सिएरा का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन देखने को मिलेगा। टाटा सिएरा ईवी का इंटीरियर बेहद प्रीमियम और स्पेसियस है। ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड के साथ फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डुअल-टोन मैटेरियल्स, एंबिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। टाटा सिएरा ईवी में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360 डिग्री कैमरा, व्हीकल-टू-लोड और व्हीकल-टू-व्हीकल चार्जिंग, ओवर-द-एयर अपडेट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले और मल्टीपल ड्राइव मोड्स शामिल हैं। पावर टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग और कनेक्टेड टेक इसे हैरियर ईवी जैसा प्रीमियम बनाते हैं।

न्यू लॉन्च

ऑडी खरीदने के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली

अगर आप ऑडी की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अगले महीने से इस जर्मन कंपनी के कारों की कीमत बढ़ने वाली है। कंपनी का कहना है कि कल-पुर्जे की बढ़ती कीमत और विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। कंपनी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि वे विदेशी मुद्रा में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण गाड़ी की कीमत में 2 प्रतिशत का इजाफा कर रहे हैं। कीमतें बढ़ाने का फैसला तब लिया गया है, जब ऑडी अपनी नई कार SQ8 को भारत में उतारने की तैयारी कर रही है। ऑडी एसक्यू 8 भारत में कल ही लॉन्च हुई है।

18 मार्च, 1902 आज का दिन

इटालियन ओपेरा गायक एनरिको कारुसो ने पहली बार अपनी आवाज ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड की थी। 20वीं सदी में ऐसा करने वाले वे पहले संगीतकारों में से एक थे।

- 1925 : अमेरिका में 'त्रि-राज्य बवंडर' आया था।
- 1964 : अमेरिकी एथलीट स्नोड स्केटर बोनी ब्लेयर का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था।
- 2000 : चेन शुई-बियान को ताइवान का राष्ट्रपति चुना गया था।
- 2017 : अमेरिकी गायक-गीतकार और गिटारवादक चक बेरी का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी/अमावस्या। **कल :** नवरात्र प्रारंभ, कलश स्थापना, वसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले। **राहुकाल :** दिन में 13.30 से 15.00 तक।

कल का पंचांग

सूर्योदय : 06.30
सूर्यास्त : 18.27
(भारतीय मानक समयानुसार)

विक्रमी संवत 2082, 28 फाल्गुन मास शक 1947, चैत्र मास 06 प्रविष्टे, 29 रमजान हिजरी 1447, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या 06.25 तक उपरांत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 28.52 तक उपरांत द्वितीया, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र 28.04 तक उपरांत रेवती नक्षत्र, शुक्ल योग 25.16 तक उपरांत ब्रह्म योग, नाग करण 06.25 तक उपरांत किन्स्तुघ्न करण, चंद्रमा मीन राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : विकास की नई योजना बन सकती है। अटका धन मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति और लाभ में सुधार होगा।

वृष : नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बीमा आदि से अर्थ प्राप्ति संभव है।

मिथुन : मानसिक तनाव बना रहेगा। नौकरी संबंधी चिंता रहेगी। विरोधी पक्ष से सचेत रहें। संतान से निराशा होगी।

कर्क : दिनमान प्रतिकूल रहेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश से हानि होगी। कीमती वस्तु संभालकर रखें।

सिंह : भविष्य की योजना में व्यस्त रहेंगे। रोजगार प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं। कार्य विशेष में सफलता मिलेगी।

कन्या : आरोग्य सुख उत्तम रहेगा। अटके कार्य बनेंगे। सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे।

तुला : आत्मबल बनाए रखें। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। यात्रा में परेशानी होगी। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

वृश्चिक : दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी। स्वजनों से मनमुटाव रहेगा। नौकरी में श्रम की अधिकता रहेगी।

धनु : अटकी योजना में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

मकर : मन खिन्न रहेगा। अनैतिक कार्य से बचें। आर्थिक स्थिति प्रतिकूल रहेगी। नौकरी में धैर्य बनाएं रखें।

कुंभ : नई योजना में सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव हो सकता है। व्यवसाय में यथेष्ट धन लाभ होगा।

मीन : विरोधी कुचेष्टारत रहेंगे। नौकरी में सावधानी बरतें। आर्थिक दबाव बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

जन्मदिन

अलीशा चिनॉय, गायिका

इस वर्ष मध्य तक विकास कार्यों में अवरोध आएंगे। समाज में आपके प्रति भ्रामक धारणा बन सकती है। विश्वासपात्र से सावधानी बरतें। परेशानियों में कमी आएगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यावसायिक विस्तार एवं लाभ की दृष्टि से वर्ष की अंतिम तिमाही लाभकारी रहेगी। आरोग्य सुख सामान्य रहेगा।

सुडोकू

8	7		9	3	4		5	
		6					8	
		3		2	6			
6				9				3
	3		1		8		9	
5				7				4
			7	8		9		
	2					4		
	9		6	4	1		7	5

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

8	7	2	9	3	4	1	5	6
9	4	6	5	1	7	3	8	2
1	5	3	8	2	6	7	4	9
6	1	7	4	9	5	8	2	3
2	3	4	1	6	8	5	9	7
5	8	9	2	7	3	6	1	4
4	6	5	7	8	2	9	3	1
7	2	1	3	5	9	4	6	8
3	9	8	6	4	1	2	7	5

डेली हेल्थ कैप्सूल

प्रोटीन और कैल्शियम का संगम बेसन दूध

बेसन वाला दूध बेहतर पाचन, हड्डियों, ब्लड शुगर, त्वचा और बालों के लिए एक बेहतरीन पौष्टिक उपाय है।

बेसन का दूध बदलते मौसम में आपको बीमारियों से बचाकर स्वस्थ बनाए रखता है। बेसन में फाइबर होता है, जो पेट को साफ रखने और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। दूध को जब बेसन में मौजूद प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है, तो हड्डियों के लिए अधिक

लाभकारी हो जाता है। बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह सुरक्षित और हेल्दी विकल्प माना जाता है। बेसन में मौजूद प्रोटीन और फाइबर से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। रात में बेसन वाले दूध का सेवन करने से वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। बेसन वाले दूध में विटामिन बी, प्रोटीन और आयरन होता है, जो त्वचा को नमी देता है और बालों को मजबूत बनाता है। बेसन का दूध बनाने के लिए कड़ाही में एक चम्मच घी डालकर बेसन को हल्का भून लें। अब धीरे-धीरे दूध डालें और अच्छे से मिलाएं। इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उबालें। स्वाद के लिए इसमें शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

जिन लोगों को डायबिटीज, लैक्टोज इनटॉलरेंस (दूध पचने में समस्या) है या जिन्हें बेसन से एलर्जी होती है, उन्हें बेसन वाले दूध का सेवन करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

-नेहा पठानिया, आहार विशेषज्ञ

देश में 1.1 करोड़ स्नातक बेरोजगार, 40% को नहीं मिल रही नौकरी

रिपोर्ट...रोजगार से जुड़ीं चुनौतियां बरकरार
स्नातकों में उच्च बनी हुई है बेरोजदारी की दर

नई दिल्ली। देश में 20 से 29 साल के 6.3 करोड़ स्नातकों में से 1.1 करोड़ बेरोजगार हैं। चिंता की बात यह है कि बेरोजगार के रूप में पंजीकरण कराने के एक वर्ष के भीतर सिर्फ सात फीसदी स्नातकों को स्थायी वेतन वाली नौकरी मिल पाती है। हाल के वर्षों में स्नातकों की बढ़ती संख्या के कारण यह समस्या और बढ़ गई है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट 'भारत में कामकाज की स्थिति-2026' के मुताबिक, देश में युवाओं (15-29 वर्ष) की उच्च शिक्षा तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, रोजगार से जुड़ी चुनौतियां अब भी कायम हैं। स्नातकों में बेरोजगारी दर उच्च बनी हुई है। 15 से 25 वर्ष के स्नातकों में बेरोजगारी दर करीब 40 फीसदी और 25 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में 20 फीसदी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्नातक युवाओं को आय के मामले में लाभ मिलता है और उनकी शुरुआती कमाई गैर-स्नातकों के मुकाबले लगभग दोगुनी होती है। इसके बावजूद 2011 के बाद युवा पुरुष स्नातकों के वेतन में वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी है। रिपोर्ट की मुख्य लेखिका प्रोफेसर रोजा अब्राहम ने कहा, यह अध्ययन शिक्षा से रोजगार तक युवाओं की यात्रा और उसमें आए बदलावों को दर्शाता है।

पुरुषों की नामांकन दर में गिरावट

*पिछले चार दशक में उच्च शिक्षा में नामांकन दर 28 फीसदी तक पहुंच गई है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी खासतौर पर बढ़ी है। हालांकि, पुरुषों के नामांकन में गिरावट आई है। यह 2017 के 38 फीसदी से घटकर 2024 के अंत तक 34 फीसदी रह गई है। **इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि पुरुष परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कमाने के मौके तलाशने लगते हैं।***

■ *उच्च शिक्षण संस्थानों का दायरा भी बढ़ा है। प्रति लाख युवाओं पर कॉलेज की संख्या 2010 के 29 से बढ़कर 2021 में 45 पहुंच गई, जिसमें निजी संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है।*

गरीब परिवारों की उच्च शिक्षा में बढ़ी भागीदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च शिक्षा में गरीब परिवारों की भागीदारी बढ़ी है, जो 2007 के आठ फीसदी से बढ़कर 2017 में 15 फीसदी हो गई है। लेकिन, आर्थिक बाधाएं अब भी बनी हुई हैं। महंगे पेशेवर पाठ्यक्रमों मसलन इंजीनियरिंग और मेडिकल में अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग के छात्र-छात्राओं की भागीदारी अधिक है। **युवा तेजी से कृषि से हटकर सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं।**

■ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2010 के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की संख्या में करीब 300 फीसदी की वृद्धि हुई है। साथ ही, निजी संस्थानों में गुणवत्ता को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं।

24 से 48 घंटे में गारंटी के साथ होगी पार्सल की डिलीवरी, देरी पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

नई दिल्ली। इंडिया पोस्ट के जरिये अब आप अपने जरूरी दस्तावेज या पार्सल को गारंटी के साथ 24 से 48 घंटे के अंदर कहीं भी भेज सकेंगे।

डाक विभाग ने शुरू कीं तीन प्रीमियम सेवाएं

इसके लिए डाक विभाग ने मंगलवार को 24 घंटे और 48 घंटे में डिलीवरी की गारंटी वाली तीन प्रीमियम सेवाएं शुरू कीं। खास बात है कि अगर तय समय में पार्सल की डिलीवरी नहीं हुई, तो मनी-बैक गारंटी के तहत आपको पूरे पैसा वापस मिलेंगे।

दरअसल, डाक विभाग उन कूरियर सेवाओं के बढ़ते बाजार के मुकाबले खुद को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ ही घंटों में डिलिवरी का वादा करती हैं। इसके तहत, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट की शुरुआत की। एजेंसी

■ ***शुरुआती चरण में छह शहरों में मिलेगी सेवा :*** *शुरुआती चरण में तीनों प्रीमियम सेवाएं छह शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू और हैदराबाद में शुरू की गई हैं। तय समय में डिलीवरी के लिए विभाग हवाई परिवहन का भी इस्तेमाल करेगा।*

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह पहल इंडिया पोस्ट के लिए नए दौर की शुरुआत है और इसमें विस्तार की व्यापक संभावनाएं निहित हैं।

ओटीपी सत्यापन और टैकिंग की भी सुविधा

नई सेवाओं में ओटीपी आधारित सत्यापन के साथ डिलीवरी, ट्रैकिंग सुविधा और वास्तविक समय में एसएमएस अलर्ट शामिल होंगे। इससे ग्राहकों को पार्सल की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी।

■ **बाद में भुगतान की भी सुविधा :** व्यवसायों के लिए 'अभी बुक करें, बाद में भुगतान करें' सुविधा, केंद्रीकृत बिलिंग व एपीआई एकीकरण के विकल्प भी उपलब्ध होंगे। थोक शिपमेंट के लिए मुफ्त पिकअप और तय समय में डिलीवरी नहीं होने पर पैसे वापसी की गारंटी भी मिलेगी।

न्यूज डायरी

पीएफसी देगी 3.25 रुपये का चौथा अंतरिम लाभांश

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 3.25 रुपये के चौथे अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है। पीएफसी ने बताया, 23 मार्च को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर शेयरधारकों की पात्रता तय की जाएगी। अंतरिम लाभांश का भुगतान 16 अप्रैल, 2026 तक या उससे पहले होगा। एजेंसी

सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़ा खुदरा निवेशकों का हिस्सा

मुंबई। सरकारी बॉन्ड बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है और द्वितीयक बाजार की गतिविधियों में तेज वृद्धि देखी जा रही है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मंच पर द्वितीयक बाजार खंड में कारोबार की मात्रा एक वर्ष में 3.7 गुना बढ़ गई है। यह सरकारी प्रतिभूतियों में व्यक्तिगत निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। रिटेल डायरेक्ट मंच के जरिये आसान पहुंच और बेहतर नकदी से इसे समर्थन मिल रहा है। एजेंसी

आरबीआई ने 48,014 करोड़ की नकदी डाली

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को बैंकिंग प्रणाली में सात दिन की वैरिएबल रेट रेपो (वीआरआर) नीलामी के जरिये 48,014 करोड़ रुपये की अस्थायी नकदी डाली। केंद्रीय बैंक ने एक बयान कहा, यह धनराशि 5.26 फीसदी की कट-ऑफ और भारित औसत दर पर उपलब्ध कराई गई। हालांकि, यह राशि 1.50 लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि की तुलना में काफी कम रही। एजेंसी

जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को दिवालिया प्रक्रिया के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. के अधिग्रहण के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज लि. की 14,535 करोड़ की बोली को मंजूरी दे दी। जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. ने बताया, एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने 17 मार्च, 2026 को अदाणी एंटरप्राइजेज की समाधान योजना को मंजूरी दी। एजेंसी

450.85 करोड़ रुपये का एनपीए बेचेगा पीएनबी

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने मंगलवार को रोल्टा प्राइवेट लि. की 450.85 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। नोटिस के अनुसार, इन एनपीए में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित करीब 7,800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जमीन और इमारत शामिल है। इस संपत्ति का आरक्षित मूल्य 250 करोड़ रुपये तय किया गया है। एजेंसी

कच्चे तेल और तैयार ईंधन की कीमतों में अंतर कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचा

90 फीसदी पेट्रोल पंपों के लिए बढ़ा संकट अब एडवांस भुगतान मांग रहीं तेल कंपनियां

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति और उत्पादन में व्यवधान के बीच देश की तीनों सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल पंपों से एडवांस भुगतान की मांग कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि इन कंपनियों को पेट्रोल-डीजल की खुदरा बिक्री से राजस्व के मोर्चे पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। देशभर में कुल 1,01,470 पेट्रोल पंप स्टेशन हैं, जिनमें से 90 फीसदी को यही तीनों कंपनियां ईंधन (पेट्रोल एवं डीजल) की आपूर्ति करती हैं।

बाजार सूत्रों ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को रुपये में लगातार गिरावट के कारण पहले से ही काफी नुकसान हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से अब इनके खुदरा बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी गिरावट आ रही है। दोनों तरह के नुकसान को झेलने और तरलता की स्थिति बनाए रखने के लिए ये कंपनियां ईंधन की आपूर्ति के लिए पेट्रोल पंपों से एडवांस भुगतान की मांग कर रही हैं।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज मार्ग से आपूर्ति में रुकावट के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इससे क्रूड और तैयार ईंधन की कीमतों में अंतर कई वर्षों के अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद भी तीनों सरकारी कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।

उधर, संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों ने आपूर्ति को लेकर चिंता फिर बढ़ा दी है। इससे मंगलवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब चार फीसदी बढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं, जबकि सोमवार को दाम घटे थे।

■ ***पहले मिलता था पांच दिन का क्रेडिट***

*देशभर के 92,000 पेट्रोल पंप स्टेशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा, सरकारी रिफाइनरी कंपनियां पहले गैसोलीन और गैसऑयल की बिक्री के लिए डीलरों को पांच दिन का क्रेडिट देती थीं। अब वे पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति से पहले ही भुगतान मांग रही हैं। **मौजूदा संकट के बीच सरकारी तेल कंपनियों के इस फैसले से कारोबार करना मुश्किल हो रहा है।***

एलपीजी खपत : 15 दिन में 17.3 फीसदी की आई गिरावट

11.47 लाख टन रह गई रसोई गैस की मांग

आपूर्ति बाधित होने से देश में रसोई गैस (एलपीजी) की खपत मार्च के पहले पखवाड़े में 17.3 फीसदी घटकर 11.47 लाख टन रह गई। एक साल पहले की समान अवधि में खपत 13.87 लाख टन रही थी। फरवरी के पहले पखवाड़े के 15.57 लाख टन के मुकाबले भी एलपीजी की मांग में 26.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

■ तीनों सरकारी तेल कंपनियों के प्रारंभिक बिक्री आंकड़ों के मुताबिक, एक से 15 मार्च के दौरान एलपीजी खपत 2024 और 2023 की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 16 फीसदी एवं 10.6 फीसदी कम रही।

■ लकड़ी एवं अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों के स्थान पर स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की वजह से एलपीजी खपत में पिछले कुछ वर्षों में सालाना आधार पर 3 से 4% की स्थिर वृद्धि देखी गई है।

विमान ईंधन की खपत भी घटी : खाड़ी देशों में हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों के निलंबन से विमान ईंधन की खपत भी चार फीसदी घटकर 3,27,900 टन रह गई। मासिक आधार पर भी इसमें 12.3 फीसदी की गिरावट रही।

पेट्रोल-डीजल की मांग में अच्छी वृद्धि : पेट्रोल की बिक्री 13.2 फीसदी बढ़कर 15 लाख टन और डीजल खपत 8.2 फीसदी बढ़कर 33.84 लाख टन रही। मासिक आधार पर पेट्रोल-डीजल की खपत 11.2% तक बढ़ी है।

यूएई पर हमले के बाद क्रूड उछलकर 101 डॉलर के पार

पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के बाद मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में 1.33 फीसदी की तेजी देखने को मिली। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों के बाद आपूर्ति संबंधी चिंताएं फिर से बढ़ने के कारण अंतरराष्ट्रीय मानक तेल ब्रेंट क्रूड 1.33 डॉलर या 1.3 फीसदी उछलकर 101.53 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया।

■ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.21 डॉलर या 1.3 फीसदी बढ़कर 94.71 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। कारोबार के दौरान क्रूड के दाम 3.3 फीसदी तक बढ़कर 103.48 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। पिछले सत्र में कच्चे तेल की कीमतों में 5.3 फीसदी तक गिरावट रही थी।

40%
तक बढ़े हैं तेल के दाम युद्ध के बाद से

अभी तेल बाजारों की नजर इस बात पर टिकी है कि यह संघर्ष कितने समय तक चलेगा। होर्मुज में तेल आपूर्ति कब तक रुकी रहेगी और आखिरकार इस उथल-पुथल से खाड़ी क्षेत्र के क्रूड बुनियादी ढांचे को कितना नुकसान पहुंचेगा।

-प्रियंका सचदेवा, विश्लेषक, फिलिप नोवा

पश्चिम एशियाई तेल सर्वाधिक महंगे, ब्रेंट क्रूड को भी पीछे छोड़ा

पश्चिम एशियाई क्रूड के बेंचमार्क रिकॉर्ड ऊंचाई को छूते हुए दुनिया के सबसे महंगे तेल हो गए हैं। कीमतों के मामले में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानक तेल ब्रेंट क्रूड को भी पीछे छोड़ दिया है। एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स के मुताबिक, मंगलवार को मई में लोड होने वाले कार्गो के लिए कैश दुबई की कीमत बढ़कर 157.66 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह 2008 में ब्रेंट क्रूड के 147.50 डॉलर प्रति बैरल के वायदा भाव के अब तक के उच्चतम स्तर को भी पार कर गया।

157.66
डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई कैश दुबई की कीमत

■ रॉयटर्स के आंकड़ों के मुताबिक, ओमान कच्चे तेल का वायदा भी 152.58 डॉलर प्रति बैरल के नए शिखर पर पहुंच गया। दुबई स्वैप पर इसका प्रीमियम 55.74 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो फरवरी में औसतन सिर्फ 75 सेंट था।

■ पश्चिम एशिया से एशियाई देशों को होने वाले कच्चे तेल का निर्यात मार्च में गिरकर 1.16 करोड़ बैरल प्रतिदिन रह गया, जो फरवरी में करीब 1.9 करोड़ बैरल प्रतिदिन रहा था। यह मार्च, 2025 के के मुकाबले करीब 32 फीसदी की गिरावट है।

ईरान युद्ध के बावजूद वैश्विक व्यापार में आगे बढ़ रहा भारत

■ पीयूष गोयल बोले, निर्यात की गति बनाए रखेगा देश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत का वैश्विक व्यापार बीते तीन वर्षों से अधिक समय में काफी मजबूत हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद भारत वैश्विक व्यापार में तरक्की कर रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि फरवरी में कम नहीं हुई और वैश्विक तनावों के बावजूद मार्च के दूसरे सप्ताह में भी सकारात्मक तेजी रही। देश महीने के अंत तक अपने निर्यात को बनाए रखेगा।

गोयल ने लोकसभा में कहा, विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बीच कोई भी सोच सकता है कि होर्मुज मार्ग से जहाज नहीं गुजर सकते। माल ढुलाई तीन गुना बढ़ गई है और बीमा भी नहीं है। इसके बावजूद, फरवरी में वस्तु व्यापार स्थिर रहा, जबकि सेवाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। मार्च में भी पहले सप्ताह में थोड़ी कमजोरी के बावजूद दूसरे हफ्ते में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

मंत्री ने कहा, भारत ने तीन-चार वर्षों में सेवा क्षेत्र में असाधारण वृद्धि दर्ज की है। वस्तु और सेवा क्षेत्र को मिला दें, तो व्यापार घाटा जीडीपी का 1-1.25 फीसदी रहा है। वास्तव में, चार साल पहले हम अधिशेष में थे। इसलिए, हमें किसी एक आंकड़े को देखने के बजाय समग्र निर्यात वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए।

भारत ने तीन-चार वर्षों में सेवा क्षेत्र में दर्ज की है असाधारण वृद्धि

व्यापार घाटा जीडीपी का सिर्फ 1-1.25 फीसदी

भारत के निर्यात को सिर्फ वस्तु व्यापार की दृष्टि से नहीं देखें

गोयल ने कहा, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नए युग की शुरुआत हो रही है। नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो विश्व में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा।

■ मंत्री ने कहा, भारत की निर्यात की कहानी को सिर्फ वस्तु व्यापार की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। सेवा निर्यात में हमारी वृद्धि वैश्विक व्यापार में उठापटक के बीच देश को स्थिरता प्रदान करती है।

निर्यातकों के लिए खुले 38 विकसित बाजारों के अवसर

गोयल ने कहा, भारत के अन्य देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से 38 विकसित देशों के बाजार निर्यातकों के लिए खुले हैं। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है। इन देशों में निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी, क्योंकि ये लागत के मोर्चे पर भारत से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।

सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर 76,000 के पार, 2.73 लाख करोड़ बढ़ी पूंजी

वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख और धातु एवं वाहन शेयरों में खरीदारी के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर 76,000 के पार पहुंच गया। निवेशकों की पूंजी 2.73 लाख करोड़ बढ़कर 433.3 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। ब्यूरो

76,070.84
पर बंद हुआ सेंसेक्स

801.41 अंक तक उछल गया था दिन में

172.35 अंक चढ़कर निफ्टी 23,581.15 पर बंद

मेटल इंडेक्स सर्वाधिक बढ़त में

0.86% तक बढ़त में रहे मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक

2.81% उछल गया मेटल इंडेक्स

2.05% की तेजी रही ऑटो इंडेक्स में

08% गिरकर 20 के नीचे आ गया बाजार में उतार-चढ़ाव को मापने वाला इंडिया विक्स सूचकांक सकारात्मक संकेत।

ये शेयर सर्वाधिक चढ़े

इटरनल	5.70%
टाटा स्टील	4.41%
एमएंडएम	3.21%
बीईएल	2.39%
एलएंडटी	2.29%

21 कंपनियों के शेयर बढ़त में रहे 09 शेयरों में 1.37 फीसदी तक गिरावट

बिकवाली का दौर

4,741.22 करोड़ के शेयर बेचे विदेशी संस्थागत निवेशकों ने

5,225.32 करोड़ की खरीदारी की घरेलू संस्थागत निवेशकों ने

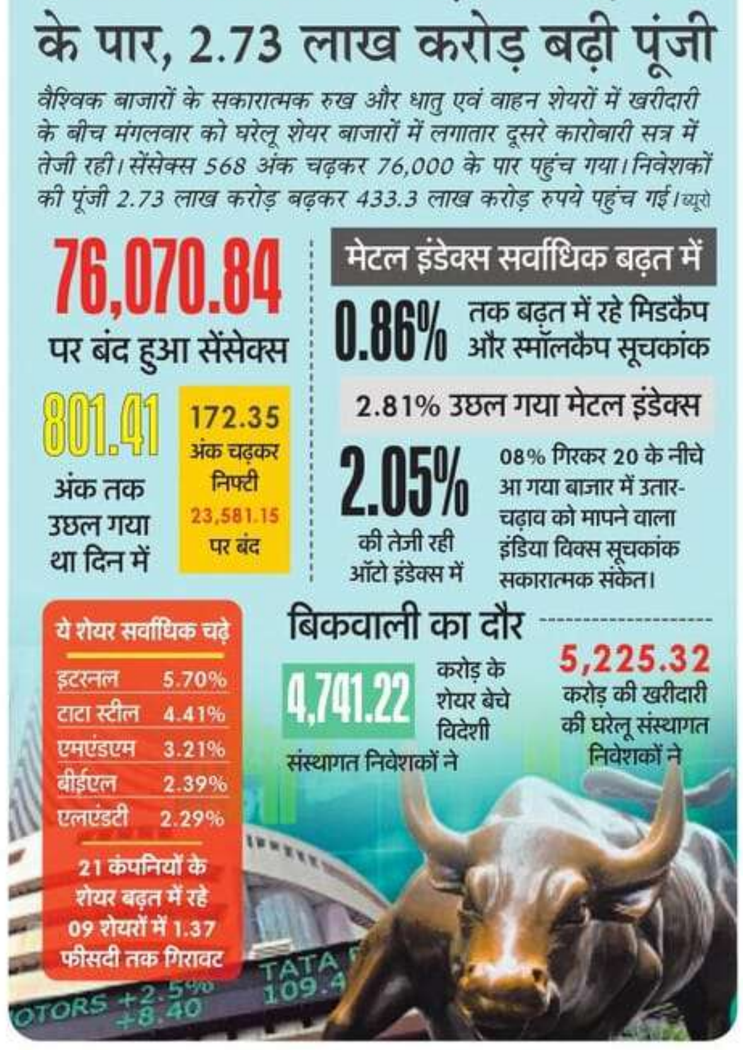

मारुति सुजुकी को मिला 5,786 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया को आयकर विभाग से 5,786.4 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर (टैक्स डिमांड नोटिस) मिला है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि इस नोटिस का उसके कारोबार, कामकाज या वित्तीय स्थिति पर सीधा असर नहीं पड़ेगा।

मारुति सुजुकी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में बताया, उसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला है। इसमें घोषित आय के संबंध में 5,786.4 करोड़ रुपये के कुछ अतिरिक्त/अस्वीकरण प्रस्तावित किए गए हैं। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (कॉरपोरेट अफेयर्स) राहुल भारती ने कहा, यह एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे ऑर्डर समय समय पर आते रहते हैं। ज्यादातर इनकी वजह नियमों की व्याख्या से जुड़े मुद्दे होते हैं। कंपनी इस ड्राफ्ट ऑर्डर के खिलाफ विवाद समाधान पैनल के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगी। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत कंपनियां आयकर विभाग से मिलने वाले ऐसे डिमांड नोटिस को चुनौती दे सकती हैं। एजेंसी

चीनी का उत्पादन 10 फीसदी बढ़कर 2.62 करोड़ टन, गन्ने के बकाया भुगतान में वृद्धि

नई दिल्ली। देश का चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष 2025-26 में 15 मार्च तक 10.5 फीसदी बढ़कर 2.62 करोड़ टन पहुंच गया। मिलों ने एक साल पहले की समान अवधि में 2.37 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया था।

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) के मुताबिक, गन्ना पेराई चालू है। 15 मार्च तक 157 मिलें चालू थीं और 379 बंद रहीं। उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक, देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में 15 मार्च तक उत्पादन बढ़कर 98.4 लाख टन पहुंच गया। दूसरे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन 81.3 लाख टन और कर्नाटक में 46 लाख टन रहा। दक्षिण कर्नाटक की कुछ मिलों के जून/जुलाई से सितंबर, 2026 तक चलने वाले विशेष सत्र के दौरान फिर से काम शुरू करने की उम्मीद है। इस्मा ने आगे कहा, उत्पादन की लागत बढ़ने और मिल से होने वाली कमाई पिछड़ने से गन्ने का बकाया भुगतान बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 28 फरवरी तक बकाया 4,898 करोड़ था, जो पिछले वर्ष इसी तारीख के 2,849 करोड़ से ज्यादा है। मौजूदा लागत ढांचे के हिसाब से न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) समय पर बढ़ाना मिलों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए जरूरी है। एजेंसी

सुरक्षित निवेश की मांग से चांदी की कीमत 6,000 रुपये बढ़ी, सोना एक फीसदी उछला

नई दिल्ली। सुरक्षित निवेश मांग के दम पर दिल्ली सराफा बाजार में चांदी और सोने की कीमतों में मंगलवार को दो फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी 6,000 रुपये या 2.34 फीसदी महंगी होकर 2,62,500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पहुंच गई। सोने में लगातार तीन कारोबारी सत्रों की गिरावट का सिलसिला टूट गया और इसकी कीमत 1,050 रुपये या एक फीसदी बढ़कर 1,61,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, घरेलू बाजारों में रुपये के नरम पड़ने से हाजिर सोने की कीमतों को वैश्विक कमजोरी से अलग होने में मदद मिली है। हालांकि, जब तक फेडरल रिजर्व कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं देता, तब तक कीमतों में एक विस्तृत दायरे के भीतर उतार-चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है। वैश्विक बाजार में हाजिर सोना मामूली गिरावट के साथ 5,003.68 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। एजेंसी

रुपया 12 पैसे टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर

डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 12 पैसे टूटकर अपने सबसे निचले स्तर 92.40 पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया संकट के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी के कारण रुपये में यह गिरावट आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान भी रुपये को कमजोर स्तर पर सहारा देने में मदद कर रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 92.35 पर खुला और दिन के सबसे निचले स्तर 92.47 तक आया।

आंकड़े दो वर्षों में अमेरिका के बाद यूएई भारतीय कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा ओडीआई निवेश गंतव्य बनकर उभरा

संघर्ष से देश की 800 छोटी कंपनियों के 12,000 करोड़ के निवेश खतरे में

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते देश की कम से कम 800 छोटी एवं मझोली कंपनियों के निवेश पर खतरा मंडरा रहा है। इन कंपनियों ने पिछले छह महीनों में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 12,000 करोड़ (1.3 अरब डॉलर) का निवेश किया है।

आरबीआई के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ओडीआई) आंकड़ों से पता चलता है कि खुदरा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि 280 भारतीय कंपनियों ने करीब 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में अमेरिका के बाद यूएई भारतीय कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा ओडीआई निवेश गंतव्य बनकर उभरा है। **मुंबई की कॉफी रोस्टर कंपनी सब को कॉफी** ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के वित्तपोषण के लिए यूएई में 2.10 लाख डॉलर भेजे थे। लाइफस्टाइल ब्रांड ब्रह्म लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ने 20 लाख डॉलर का निवेश किया है। हॉस्पिटैलिटी कंपनी इदम नेचुरल वेलनेस ने इस साल की शुरुआत में 6.80 लाख डॉलर का निवेश किया। हालांकि, ये सभी निवेश अगस्त-सितंबर, 2025 के बाद हुए हैं।

इन कंपनियों ने भी यूएई में किया है निवेश

*छह महीनों में यूएई में निवेश करने वाली कंपनियों में ग्रेविस फूड्स जैसे नाम भी शामिल हैं, जिसके पास भारत में बास्किन रॉबिन्स का लाइसेंस है। इस कंपनी ने 1.14 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। **हल्दीराम स्नैक फूड्स** ने यूएई में 28 लाख डॉलर और ओयो की सहायक कंपनी ओयो प्रॉपटेक ने खाड़ी देशों में 1.10 करोड़ डॉलर का निवेश किया है।*

छोटी कंपनियों के लिए कई जोखिम

जानकारों का कहना है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में कारोबार करने वाले भारतीय लघु एवं मझोले उद्यम (एसएमई) स्थिर परिचालन वातावरण की तुलना में कहीं अधिक जोखिम में हैं। भारतीय एसएमई के लिए सबसे बड़ा खतरा आमतौर पर सिर्फ पारंपरिक अर्थों में राजनीतिक ही नहीं, बल्कि एकाग्रता का जोखिम होता है।

कई छोटी कंपनियां एक ही बाजार में निवेश करती हैं। सीमित आपूर्तिकर्ता आधार पर निर्भर होती हैं या प्रवर्तकों के नेतृत्व वाले कार्यान्वयन पर अत्यधिक निर्भर होती हैं।

■ *ऐसी स्थिति में माल ढुलाई, ग्राहकों की आवाजाही, भुगतान समय या स्थानीय परियोजना कार्यान्वयन में थोड़ी रुकावट नकदी प्रवाह पर भारी प्रभाव डाल सकती है।*

मानसिक स्वास्थ्य की चिंता

सरकारी हेल्पलाइन 'टेली-मानस' पर दर्ज की गयी 34 लाख कॉल्स केवल सांख्यिकीय डाटा नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समाज के भीतर गहराई तक पैठ बना चुके मानसिक घावों और सामूहिक बेचैनी का जीवंत साक्ष्य हैं. इतनी विशाल संख्या में लोगों का सहायता के लिए फोन उठाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि 'चिंता का संकट' अब हमारे निजी जीवन और घरों के भीतर तक अपनी जड़ें जमा चुका है. इस रिपोर्ट के सबसे भयावह आंकड़े देश के युवा और मध्यम वर्ग की मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं, जो आज भारी तनाव, नींद की कमी, और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. प्राप्त कॉल्स में से एक बड़ा हिस्सा आत्महत्या के विचारों और गंभीर एंग्जायटी से संबंधित होना इस ओर इशारा करता है कि भारत एक 'साइलेंट पेंडेमिक' के मुहाने पर खड़ा है. सोशल मीडिया के युग ने हमें आभासी रूप से तो जोड़ा है, लेकिन वास्तविक मानवीय संबंधों में एक बड़ी खाई पैदा कर दी है. यह 'डिजिटल लोनलीनेस' एक नयी बीमारी के रूप में उभरा है, जहां व्यक्ति भीड़ के बीच भी स्वयं को एकाकी महसूस करता है. 'टेली-मानस' जैसी पहल ने उन लोगों को एक सुरक्षित मंच प्रदान किया है जो 'पागलपन' के सामाजिक ठप्पे या लोक-लाज के डर से क्लीनिक जाने से कतराते थे. फोन पर पहचान गुप्त रखने की सुविधा ने उस 'स्टिग्मा' को काफी हद तक कम किया है, जो मानसिक बीमारियों के साथ सदियों से जुड़ा हुआ है. किंतु, केवल कॉल सुन लेना इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है. चौंतीस लाख कॉल्स की यह बाढ़ बुनियादी ढांचे पर गंभीर सवाल उठाती है कि क्या हमारे पास इन लाखों पीड़ितों के लिए प्रशिक्षित काउंसलर्स उपलब्ध हैं? भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. प्रति लाख आबादी पर विशेषज्ञों की उपलब्धता वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है. शहरी क्षेत्रों में कुछ हद तक सुविधाएं सुलभ हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में स्थिति और भी विकट है. 'टेली-मानस' की वास्तविक सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह कॉल करने वालों को केवल तात्कालिक सांत्वना देती है या उन्हें दीर्घकालिक उपचार और सामाजिक सहयोग तंत्र से जोड़ने में सफल होती है. सरकार को मानसिक स्वास्थ्य हेतु आवंटित बजट में व्यापक वृद्धि करनी चाहिए और इसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का अनिवार्य हिस्सा बनाना आवश्यक है. हमें शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर संवाद करने का वातावरण निर्मित करना होगा.

'टेली-मानस' पर दर्ज की गयी 34 लाख कॉल्स हमारे समाज के भीतर गहराई तक पैठ बना चुके मानसिक घावों और सामूहिक बेचैनी का जीवंत साक्ष्य हैं. प्राप्त कॉल्स में से एक बड़ा हिस्सा आत्महत्या के विचारों और गंभीर एंग्जायटी से संबंधित है.

राज्यसभा चुनाव में और ताकतवर हुई भाजपा

नीरजा चौधरी
राजनीतिक विश्लेषक
neerja_chowdhury@yahoo.com

देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को हुए चुनाव परिणाम के अंतिम नतीजे एनडीए के पक्ष में रहे. इससे जहां एनडीए को और मजबूती मिली है, वहीं भाजपा की शक्ति काफी बढ़ गयी है. भाजपा ने महाराष्ट्र से शरद पवार को निर्विरोध राज्यसभा में आने दिया, वहीं बिहार से नीतीश कुमार राज्यसभा में आये. सच मानिए, तो यह भाजपा की एक सोची-समझी रणनीति है. गैर एनडीए दलों की बात करें, तो वे राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत गंभीर, बहुत आक्रामक नहीं दिखे.

देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को हुए चुनाव के अंतिम नतीजे एनडीए के पक्ष में रहे. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाले एनडीए को जहां 22 सीटों पर जीत मिली वहीं, विपक्ष को 15 सीटों से संतोष करना पड़ा. इस चुनाव के बाद राज्यसभा में जहां एनडीए को और मजबूती मिली है, वहीं भाजपा की शक्ति भी काफी बढ़ गयी है. यदि हम राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें, तो पायेंगे कि बिहार, ओडिशा और हरियाणा में भाजपा ने उन सीटों पर तो जीत दर्ज की ही, जिन पर उसकी जीत तय मानी जा रही थी, उसने तीन ऐसी सीटें भी जीत लीं, जिनमें क्रॉस वोटिंग हुई. इस कारण बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, राजद के उम्मीदवार के पास जीत के लिए पर्याप्त 41 वोट की बजाय 35 वोट ही थे, पर बीएसपी और औवैसी की पार्टी एआइएमआइएम के मतों को मिलाकर वोट पर्याप्त हो जा रहे थे. परंतु राजद के एक और कांग्रेस के तीन विधायक दूसरी तरफ चले गये और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की हार हो गयी. इस तरह भाजपा ने विपक्ष के खेमे में सेंध लगायी और उसके उम्मीदवार को हराने में सफल हो गयी.

इस चुनाव को भाजपा का शो माना जा रहा है, पर ऐसा चुनाव में होता रहता है कि एक-दो लोग इधर-उधर चले जाते हैं. इस चुनाव का असली महत्व यह है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़कर राज्यसभा के सदस्य बने हैं. और ऐसा लगता है कि यह उनकी मर्जी से हुआ है. सच मानिए, तो यह भाजपा की एक सोची-समझी रणनीति है. क्योंकि यह सभी जानते हैं कि वह बिहार में सरकार का नेतृत्व करना चाह रही थी, परंतु ऐसा माना जा रहा था कि इसमें अभी छह-आठ महीने की देरी है. यहां दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मनाना इतना आसान नहीं लग रहा था. लेकिन यह सब कुछ तीन महीने के अंदर ही हो गया. दरअसल, ऐसा करने की वजह भाजपा द्वारा एक प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने की हामी है. दिल्ली में नीतीश कुमार को क्या भूमिका दी जायेगी- उन्हें कोई मंत्रालय दिया जाता है या कुछ और भूमिका दी जाती है- यह देखने वाली बात होगी. यहां जो बात महत्वपूर्ण है, वह यह कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद चूंकि भाजपा बिहार में नेतृत्व की भूमिका में रहेगी, ऐसे में जनता दल (यू) के जो 12 लोकसभा सांसद हैं, उन पर उसका नियंत्रण बढ़ेगा. इसके साथ-साथ, भाजपा का यह प्रयास भी रहेगा कि लोकसभा में उसके सहयोगी दलों के जितने भी सांसद हैं, वे टस से मस न हों, इधर से उधर न जाने पायें और उसके पास लोकसभा में संख्या बल पर्याप्त बना रहे.

यह बात भी उल्लेखनीय है कि भाजपा ने महाराष्ट्र से शरद पवार को निर्विरोध राज्यसभा में आने दिया है. यदि शरद पवार की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो बहुत संभव है कि भाजपा उसे निर्विरोध चुनकर राज्यसभा नहीं आने देती. यहां मेरा अनुमान कहता है कि भाजपा ने ऐसा इसलिए किया है, क्योंकि लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के आठ सांसद हैं, जो जरूरत पड़ने पर भविष्य में भाजपा का साथ दे सकते हैं. तो शरद पवार की खिलाफत न करने की भाजपा की नीति का अर्थ यही है कि वह उनकी नजरों में अच्छी बनी रहे, ताकि समय आने पर वह उनका समर्थन ले सके. जहां तक नीतीश कुमार की बात है, तो उनके लिए राज्यसभा में आना भी भाजपा के लिए लाभ की बात है. एक बात तो साफ है कि बिहार में भाजपा की पकड़ मजबूत हो जायेगी, क्योंकि वह दोनों जगह सत्ता में है. एक बात और, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय जिस तरह की मुश्किलें हैं, उसका असर घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है. चूंकि इस समय एक अनिश्चितता का माहौल है, ऐसे में भाजपा यह सुनिश्चित करना चाह रही थी कि लोकसभा में उसके सांसदों और लोकसभा में उसके समर्थन पर कोई आंच न आये. तो भाजपा के लिए नीतीश कुमार और शरद पवार का राज्यसभा में आना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है.

अब बात गैर एनडीए दलों की, तो वे राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत गंभीर, बहुत आक्रामक नहीं दिखे. यह पता होते हुए भी कि भाजपा के पास कितनी बड़ी मशीनरी है और वह अपनी एक-एक सीट के लिए किस तरह विस्तार से रणनीति बनाती है, किस तरह से तैयारी करती है, विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और उसके लोग खिसक गये. जबकि भाजपा की रणनीति को देखते हुए उनकी तैयारी दोगुनी-तिगुनी होनी चाहिए थी, पर सच कहूं, तो उनकी तैयारी कहीं नहीं दिखी. इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और इस बार भी ऐसा ही हुआ. चुनाव में साफ दिखा कि गैर एनडीए दलों में एकता नहीं बन पायी थी. इनके बीच का असंतोष सामने आ गया. इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि टैरिफ को लेकर, ईरान युद्ध को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर इन दिनों विपक्ष जितना आक्रामक रहा है, उतनी आक्रामकता चुनाव जीतने के मामले में वह नहीं दिखा पाया. यह तो वही बात हो गयी कि आप भले ही संसद में, देशभर में मुद्दों को उठाते रहिए, उन पर बातें करते रहिए, पर यदि चुनाव ही नहीं जीत पा रहे हैं, तो इसका क्या लाभ. इस तरह की चीजें आगे न हों, इसके लिए विपक्ष को इकट्ठे मिलकर चलना होगा और विस्तार से चुनाव जीतने की योजना बनानी होगी. भाजपा की रणनीति को देखते हुए अपनी रणनीति बनानी होगी और हर चुनाव को गंभीरता से लेना होगा.

दरअसल, विपक्ष के खराब प्रदर्शन की वजह यह भी है कि वह अपनी योजनाओं को विस्तारित करने में चूक जाता है, क्योंकि उसका संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है, कांग्रेस का तो बिल्कुल भी नहीं है. यदि बूथ लेवल पर आपके कार्यकर्ता नहीं हैं, जो आपकी बात लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को पार्टी के पक्ष में कर सकें, तो आप मात खायेंगे ही. जब आपके पास वैसी सांगठनिक शक्ति ही नहीं है, जो आपके लोगों को एकजुट रख सके, तो वही होगा, जो राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ. विपक्ष यदि अपने लोगों को समेट कर नहीं रख पाया, तो उसे इस बारे में सोचना होगा और अपने भीतर की खामियों को दुरुस्त करना होगा. अंत में, बस इतना ही कि यह एक महत्वपूर्ण चुनाव रहा, जिसे लंबे समय तक याद रखा जायेगा.

(बातचीत पर आधारित)
(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास आधारित दृष्टिकोण जरूरी

पद्मश्री अशोक भगत
सचिव, विकास भारती, झारखंड
vikasbharti1983@gmail.com

भारत में नक्सलवाद व उग्रवाद दशकों से एक गंभीर चुनौती रही है. पर वर्तमान में जारी सरकारी आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि हिंसा संबंधित घटनाएं उल्लेखनीय रूप से कम हुई हैं. ऐसे में सरकार, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे पूर्व में हिंसाग्रस्त प्रदेशों में स्थानीय निर्णय लेने की शक्ति विकसित हो, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके.

भारत में नक्सलवाद व उग्रवाद दशकों से राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक विकास और ग्राम स्तर की व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती रही है. दलित, वंचित समुदाय के अधिकारों व उत्थान के लिए वर्ग संघर्ष की एक शुरुआत ने देश, राज्य और पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों को विगत दशकों में विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है और विकास की गति को स्थिर करने का प्रयास किया है. पिछली कई सरकारों ने आर्थिक व सामाजिक तथा अन्य उपायों के संयोजन से इस समस्या के समाधान का प्रयास किया है. वर्तमान में जारी सरकारी आंकड़े और विशेषज्ञों के मत यह संकेत दे रहे हैं कि हिंसा संबंधित घटनाएं उल्लेखनीय रूप से कम हुई हैं. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न गैर-सरकारी स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 2014-2015 में उग्रवादी घटनाएं चरम पर थीं. यदि पूरे दशक की बात करें, तो इस अवधि में उग्रवादी हिंसा की कुल 7,744 घटनाएं हुईं. आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2025 के बीच न केवल उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आयी है, बल्कि आम नागरिक और सुरक्षा बलों की तुलना में कहीं ज्यादा उग्रवादी मारे गये हैं.

वर्ष 2015 से पहले प्रतिवर्ष अमूमन 500 से ज्यादा हिंसा और प्रति हिंसा की घटनाएं दर्ज की जाती थीं, जो कम होकर 200 के आसपास रह गयी हैं. निःसंदेह, इससे साबित होता है कि चरमपंथियों के खिलाफ सरकार ने बेहद सटीक और प्रभावशाली रणनीति अपनायी है. इससे अब उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अमन और शांति साफ दिखने लगी है. हालांकि, इसके साथ-साथ नयी चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं. इन चुनौतियों का जब तक सार्थक समाधान नहीं होगा, तब तक उग्रवाद की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सबसे बड़ी चुनौती है. इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, जंगल, जल और कृषि भूमि व्यापक रूप से उपलब्ध हैं. यदि इन संसाधनों का स्थानीय समुदायों के हित में उपयोग किया जाये, तो दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि संभव है. सरकारी तंत्र इन क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी कंपनियों को आमंत्रित कर रही हैं, लेकिन स्थानीय संसाधनों के वितरण में जब तक स्थानीय समुदायों का हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक स्थायी शांति की कल्पना करना बेमानी है. संसाधनों की पारदर्शी साझेदारी और स्थानीय लोगों को भूमि व वन अधिकार देने से विकास की गति तेज होगी. क्योंकि उग्रवाद अपने उत्थान से पतन की अवस्था में पहुंचने तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक ताने-बाने को अपूरणीय क्षति पहुंचा चुका है. इस मामले में सरकार को बेहद सतर्कता से काम लेना होगा.

दूसरी बड़ी चुनौती शासन की है. इसके लिए सरकार ने कई स्तरों पर काम किया है, परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना स्थायी शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे स्थानीय समुदायों में निर्णय लेने की शक्ति आती है. पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार और वित्तीय शक्ति देकर शासन-सेवा के बीच की दूरी कम की जा सकती है. हालांकि सैद्धांतिक रूप से सरकार ने ग्राम पंचायती संस्थाओं को कई प्रभावशाली अधिकार दिये हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर आज भी यहां नौकरशाही हावी है. जन सरोकार से टूटने की स्थिति ने धीरे-धीरे इसकी जड़ें कमजोर की हैं. पांचवी अनुसूची के लिए सरकार ने पेसा लागू किया है, इसे और सशक्त बनाने की जरूरत है. उग्रवाद प्रभावित जिलों में शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, स्वरोजगार योजनाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने से स्थायी शांति में मदद मिलने की पूरी संभावना है. यही नहीं, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय बुनियादी सेवाएं भी कमजोर हैं. सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल व इंटरनेट सुविधा जैसी मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाती हैं, जिससे असंतोष को हतोत्साहित किया जा सकता है.

सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में की गयी पहल के तहत स्वशासन की संस्थाओं, पंचायती राज और ग्राम सभा को केंद्र बिंदु बनाकर विकास की गति को आगे बढ़ाने की जरूरत है. अफसरशाही को नियंत्रण में रखकर स्थानीय स्वशासन को विकास की धुरी बनाकर सरकार जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे. जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की अवधारणा को बल देकर उग्रवाद को सदा के लिए नष्ट किया जाये. आत्मसमर्पण कर चुके या उग्रवाद प्रभावित युवाओं के पुनर्वास हेतु योजनाओं को मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है. जनता के हितों के लिए बेहतर विकल्प की परिकल्पना को साकार करने का यह उचित अवसर है. आज स्थितियां पहले से बेहतर नजर आती हैं और जब हिंसा कम होती है, तो विकास आधारित दृष्टिकोण और स्थानीय शासन तंत्र को भरोसेमंद रूप से संभाला जा सकता है. सरकार, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे पूर्व में हिंसाग्रस्त प्रदेशों में स्थानीय निर्णय लेने की शक्ति विकसित हो, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

विदेश नीति को लेकर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाये नेपाल

हाल ही में हुए चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की भारी जीत के बाद, नेपाल की विदेश नीति पर बहस फिर से शुरू हो गयी है. हालांकि, विदेश नीति के मूल सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि वे राष्ट्रीय हितों की रक्षा की अवधारणा पर आधारित हैं. राष्ट्रीय हितों के सिद्धांतों में कम से कम तीन कारक शामिल हैं- मूल, महत्वपूर्ण और परिधीय हित. ये सभी हित अंतर्निहित और परस्पर जुड़े हुए हैं. अतः, यह तर्क दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय हित स्थायी हैं. यही कारण है कि सरकार में बार-बार परिवर्तन होने के बावजूद विदेश नीति काफी हद तक स्थिर रहती है. हालांकि, जब भी कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है, जो किसी देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, तो विदेश नीति के दृष्टिकोण और रणनीतियों को पुनर्व्यवस्थित या पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता होती है. जब कोई पड़ोसी देश गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा हो, या किसी व्यापक भू-राजनीतिक संघर्ष में उलझा हो, तो विदेश नीति को (पुनः) समायोजित करने की आवश्यकता पड़ सकती है. इसी प्रकार, वैश्विक भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र में कोई भी बड़ा बदलाव, जो विश्व राजनीति में मौजूदा शक्ति संरचनाओं को प्रभावित करता है, देशों को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर सकता है. इन तीनों स्थितियों को समग्र रूप से देखा जाये, तो वर्तमान में ये केवल आंशिक रूप से ही मौजूद हैं, और ये नेपाल की विदेश नीति में बड़े बदलावों की मांग नहीं करती हैं. इस समय पश्चिम एशिया में उथल-पुथल मची हुई है और पश्चिम में भी रोजगार के अवसर घट रहे हैं. इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, नेपाल को अपने उन पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे, जिनकी आर्थिक वृद्धि तेजी से हो रही है और जो प्रमुख बाजारों के रूप में उभर रहे हैं. अब समय आ गया है कि हम विदेश नीति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं.

-चंद्र देव भट्ट

बोधि वृक्ष

पंचतत्व का सम्मान

भारत में पंचतत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को सम्मान देने तथा उनका आभार जताने की परंपरा रही है. क्योंकि यह शरीर, धरती, सौर मंडल और ब्रह्मांड- सब कुछ पंचतत्वों का खेल है. इस संस्कृति में हम जिन लोगों की पूजा करते हैं, चाहे वह शिव हों, राम हों या कृष्ण- वे उन सभी मुश्किलों से गुजरे, जिनसे ज्यादातर मनुष्य गुजरते हैं. हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हालात चाहे जो भी रहे हों, चाहे उन्हें जीवन में कैसी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़ा हो, वे अपनी भीतरी प्रकृति से कभी नहीं भटके. नदी कई तरह से ऐसी ही होती है. चाहे कैसे भी लोग उसे छुएं, बहने की प्रकृति के कारण वह हमेशा शुद्ध रहती है. इस संस्कृति में हमने नदियों को सिर्फ जल भंडार की तरह नहीं देखा. हमने उन्हें जीवनदायी देवी-देवताओं के रूप में देखा. तर्क की सीमाओं में बंधे विचारशील मन को यह बात मूर्खतापूर्ण या आदिम लग सकती है. नदी तो केवल नदी है, वह देवी कैसे हो सकती है? यदि ऐसे व्यक्ति को आप किसी कमरे में तीन दिन तक बिना पानी के कैद कर दें और फिर उसे एक गिलास पानी दिखायें, तो वह उसके आगे सिर झुकायेगा. हमने कभी नदियों को भौगोलिक इकाई की तरह नहीं देखा. हमने उन्हें जीवन को बनाने वाले सामान की तरह देखा, क्योंकि हमारे शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा भी जल है. जब भी हम जीवन की खोज करते हैं, तो सबसे पहले एक बूंद पानी ढूंढते हैं. जब हम जीना भूल जाते हैं, जब हम अपने जीवन को बनाने वाली चीजों का सम्मान नहीं करते- जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस जल को पीते हैं और जो आकाश हमें थामे रखता है- जब हमारे मन में उनके लिए कोई सम्मान और श्रद्धा नहीं होती, तो वे हमारे अंदर बहुत अलग तरह से बर्ताव करते हैं. यदि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सफल होना चाहते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर के तत्व इसमें मदद करें. यदि वे मदद नहीं करते, तो कुछ भी कारगर नहीं होगा. अब समय है कि हम पंचतत्वों के साथ सम्मान से पेश आने की संस्कृति को वापस लायें.

-सद्गुरु जग्गी वासुदेव

कुछ अलग

आज हमारा जीवन एप पर चल रहा है

मुरली मनोहर श्रीवास्तव
टिप्पणीकार
writermurli@gmail.com

आज किसी से संपर्क करना आसान नहीं है, भले ही यह दिखता आसान हो. फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मोबाइल नंबर, इनमें से कुछ भी पास न होने पर दूसरों से संपर्क करना दूभर हो जायेगा. मोबाइल खोने पर किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, इसलिए कि किसी का नंबर याद नहीं है, सारे नंबर मोबाइल में सेव हैं. फेसबुक हो या कोई अन्य माध्यम, सब अघोषित रूप से एप हैं. बिजली का बिल भरना हो, गैस का या कोई अन्य भुगतान करना हो, एप के बिना कुछ भी संभव नहीं है. मैंने एक गोलगप्पे वाले को देखा था, उसके यहां बहुत भीड़ रहती थी, सो वह पैसे कैश न ले कर स्कैन कराता था. यहां तक कि ई-रिक्शा वाले भी दस रुपये का भुगतान कैश न होने पर स्कैनर से करने को कहते हैं. फोटो कॉपी का भुगतान करना हो, आज वह भी बिना स्कैनर के नहीं किया जा सकता.

कहने का अर्थ यह है कि आज हमारा जीवन एप पर चल रहा है और एप मोबाइल पर. मोबाइल बंद और जिंदगी ठप. लेकिन इस एप बेस्ड लाइफ की मुश्किलें भी बहुत अधिक हैं. बिना इंटरनेट के कोई भी एप काम नहीं करता. आज की तारीख में किसी भी मोबाइल का सस्ते से सस्ता प्लान भी ढाई-तीन सौ रुपये महीना से कम नहीं पड़ता है. इसके बाद डाटा यूज की लिमिट है. जरा सोचिए, यह आसान-सी दिखती जिंदगी कितनी मुश्किल और किस कदर सिस्टम पर निर्भर है. मुश्किल यह भी है कि हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अभी भी इस तरह स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं है. नतीजा, आपको स्थान-स्थान पर सुविधा केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र मिल जायेंगे. दावे-प्रतिदावे और तथ्य को देखने पर इस एप की तस्वीर बड़ी भ्रामक और धुंधली नजर आती है. हम भले ही दावा करें कि देश में इंटरनेट और मोबाइल उपभोक्ता की संख्या 95 करोड़ पार कर गयी है, पर यह उस जनसंख्या को कुछ भी देने में नाकाम रही है, जो स्मार्ट नहीं हैं.

समस्या यह है कि यह आवाज बड़ी हो कर भी समस्या के स्तर पर अनसुनी है. पंचानबे करोड़ एप उपभोक्ता के बाद जो जनसंख्या बची, वह अनजाने ही हाशिये पर खड़ी है. उसका दुर्भाग्य यह है कि न तो वह स्मार्ट है, न ही एप की दुनिया से परिचित. वह विवशता के चलते या सक्षम न होने के कारण एप विहीन है. इससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है. सो लाइफ @ एप डॉट कॉम बहुत सुविधाजनक भले हो, अभी भी देश की वास्तविक स्थिति सामने लाने में असमर्थ है. उसका इस देश की आत्मा से सरोकार होना बाकी है. भारत की आत्मा आज भी उस ग्राम में बसती है, जो स्मार्ट नहीं, भोली-भाली और सरल है.

आपके पत्र

भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई चुनौती

फरवरी 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.2% के 10 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गयी, जो अर्थव्यवस्था में गहरे संरचनात्मक संकट का संकेत है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 36.75% भार वाले खाद्य व पेय पदार्थ महंगाई के प्रमुख कारण बने हुए हैं. मांस, तेल, फल और टमाटर की कीमतों में 45% तक वृद्धि आपूर्ति शृंखला की कमजोरी को दर्शाती है. पश्चिम एशिया तनाव से गैस व उर्वरक लागत बढ़ी है. सोना 48.2% और चांदी 160% महंगे हुए. आपूर्ति आधारित महंगाई के कारण ब्याज दर बढ़ाने में दुविधा बनी हुई है.

प्रसिद्ध यादव, पटना

होर्मुज पर अमेरिका की रणनीति विफल

युद्ध की परिस्थितियों में ईरान की अडिग रणनीति के सामने अमेरिका की नीति कमजोर पड़ती नजर आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि नाटो सहयोगी होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में मदद नहीं करते, तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का भविष्य प्रभावित हो सकता है. उनका तर्क है कि यह समुद्री मार्ग अमेरिका से अधिक चीन और अन्य देशों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हें उठानी चाहिए. हालांकि सहयोगियों ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है.

युगल किशोर राही, छपरा

डॉ रमण कुमार
चेयरपर्सन, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया

डॉ अखिलेश यादव
डायरेक्टर, आर्थोपेडिक्स, मैक्स हॉस्पिटल, वैशाली

दुनियाभर में दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और दूसरी क्रॉनिक बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इन बीमारियों के पीछे एक बड़ा कारण शरीर में होने वाली सूजन यानी इन्फ्लेमेशन है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सूजन क्या है, कब खतरनाक होती है, किन लक्षणों से पहचान सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है. बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ.

शरीर में गंभीर गड़बड़ी का संकेत है इन्फ्लेमेशन

सूजन हमेशा बुरी नहीं होती. यह शरीर की रक्षा करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो यही सूजन कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत बन सकती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी लगभग 70 प्रतिशत बीमारियों की जड़ में किसी-न-किसी रूप में इन्फ्लेमेशन मौजूद रहती है.

अक्सर हम सूजन को केवल चोट या मोच से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शरीर के अंदर होने वाली सूजन दिखाई नहीं देती. दरअसल, यह धीरे-धीरे बढ़ती है और लंबे समय तक रहने पर कई गंभीर रोगों का संकेत हो सकती है. कभी-कभी ऑटोइम्यून डिजीजेज जैसे- रूमैटाइड आर्थराइटिस, लुपुस, सोरियासिस, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज आदि के चलते भी सूजन हो सकती है. ऑटोइम्यून बीमारियों में इम्यून सेल्स, स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती हैं, जिससे लगातार सूजन रहती है.

जैविक प्रतिक्रिया है सूजन

इन्फ्लेमेशन शरीर की एक प्राकृतिक जैविक प्रतिक्रिया है. जब शरीर को चोट लगती है, संक्रमण होता है या कोई बाहरी हानिकारक तत्व शरीर में प्रवेश करता है, तब हमारी रोग-प्रतिरोधक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं. यही प्रक्रिया सूजन कहलाती है. सूजन का मतलब है कि शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में हल्की और थोड़े समय की सूजन सामान्य मानी जाती है, लेकिन जब बिना किसी साफ कारण के शरीर में सूजन होने लगे या लंबे समय तक बनी रहे, तब यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है. सूजन हमारे शरीर का सामान्य हिस्सा नहीं होता है, इसलिए इसमें दर्द महसूस होता है.

अंदरूनी अंगों पर भी प्रभाव

सूजन केवल चेहरे व त्वचा पर दिखाई देने वाली लालिमा या दर्द तक सीमित नहीं होती. यह शरीर के अंदरूनी अंगों, जैसे- दिल, दिमाग, आंत, किडनी, जोड़ों और त्वचा को भी प्रभावित कर सकती है. जब सूजन लगातार बनी रहती है, तो यह स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगती है और धीरे-धीरे क्रॉनिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

कब खतरनाक हो जाती है सूजन

विशेषज्ञों के अनुसार, सूजन तब नुकसानदायक मानी जाती है, जब यह हफ्तों या महीनों तक बनी रहे. शरीर के एक हिस्से से फैलकर पूरे शरीर में असर करने लगे. रक्त के साथ अंगों तक पहुंचने लगे. स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगे. बार-बार होने लगे. दर्द, थकान या कमजोरी लगातार बनी रहे. लंबे समय तक रहने वाली सूजन रक्त वाहिकाओं, जोड़ों, मस्तिष्क, दिल और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है.

शरीर में सूजन बढ़ने के लक्षण

सूजन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देती. समय पर जांच और सही जीवनशैली से कई बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है.

लगातार थकान : अगर पर्याप्त आराम के बाद भी थकान बनी रहती है, तो यह शरीर में सूजन का संकेत हो सकता है.

वजन बढ़ना या कम न होना : लंबे समय की सूजन मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है. इससे शरीर में चर्बी जमा होने लगती है.

पाचन संबंधी परेशानी : पेट फूलना, गैस, कब्ज, दस्त या पेट दर्द आंतों की सूजन से जुड़ा हो सकता है.

मस्तिष्क प्रभावित होना : एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, उदासी या चिंता इसके लक्षण हो सकते हैं.

जोड़ों में दर्द और अकड़न : लंबे समय की सूजन हड्डियों और जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है. आर्थराइटिस में ऐसा होता है.

मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं सूजन

- **एक्यूट इन्फ्लेमेशन :** यह सूजन अचानक होती है और कम समय तक रहती है. चोट, संक्रमण, जलने या किसी एलर्जी के कारण हो सकती है. आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर दो सप्ताह में ठीक हो जाती है.
- **सब-एक्यूट इन्फ्लेमेशन :** यह एक्यूट और क्रॉनिक सूजन के बीच की अवस्था होती है. यह सूजन लगभग 2 से 6 सप्ताह तक रह सकती है.
- **क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन :** यह लंबे समय तक रहने वाली सूजन है. आमतौर पर 6 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है. यह इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी, तनाव, मोटापा, खराब खान-पान और जीवनशैली से जुड़ी होती है. क्रॉनिक सूजन सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यह धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाती रहती है.

सूजन कम करने के घरेलू उपाय

- हल्दी वाला दूध पीना लाभकारी माना जाता है.
- नमक मिले गुनगुने पानी से सिकाई करने से आराम मिलता है.
- कुछ मामलों में बर्फ की सिकाई फायदेमंद होती है.
- हल्दी और प्याज का लेप लगाने से बाहरी सूजन कम हो सकती है.
- खजूर और पौष्टिक आहार शरीर को ताकत देते हैं
- लंबे समय तक रहने वाली सूजन में डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

सूजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ

- ज्यादा चीनी और मीठे पेय
- तले हुए और फास्ट फूड
- प्रोसेस्ड स्नैक्स
- मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट
- ज्यादा नमक वाला भोजन
- ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट
- कुछ लोगों में दूध और दुग्ध उत्पाद
- अत्यधिक प्रोसेस्ड वनस्पति तेल

सूजन से बचने के उपाय

सूजन को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है.

- सप्ताह में कम-से-कम 150 मिनट व्यायाम करें.
- ताजे फल और सब्जियां खाएं.
- धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहें.
- वजन संतुलित रखें, पर्याप्त नींद लें.
- तनाव कम करें, प्रदूषण और रसायनों से बचें.
- ज्यादा प्रोसेस्ड भोजन से बचें.
- स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से शरीर की सूजन कम रहती है और दिल, दिमाग और बाकी अंग लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं.

सूजन किन बीमारियों का संकेत

अगर सूजन का कारण स्पष्ट नहीं है, तो यह अंदरूनी बीमारी का लक्षण हो सकता है.

किडनी की समस्या : हाथ-पैर और चेहरे में सूजन किडनी के ठीक से काम न करने का संकेत हो सकता है. जब किडनी विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकाल पाती, तो शरीर में सूजन होने लगती है.

थायराइड की गड़बड़ी : अचानक वजन बढ़ना, गर्दन या पैरों में सूजन होना हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण हो सकता है.

दिल की कमजोरी : दिल सही तरह से रक्त पंप न करे तो शरीर में पानी जमा होने लगता है. इससे पैरों और हाथों में सूजन दिखाई देती है.

लिवर की खराबी : पेट में सूजन और दर्द लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है.

डीप वेन थ्रोंबोसिस : पैरों की नसों में खून का थक्का बनने से सूजन और दर्द होता है.

ऑटोइम्यून बीमारियां : रूमेटाइड आर्थराइटिस, लुपुस, सोरायसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं अपने ही ऊतकों पर हमला करती हैं.

बातचीत व आलेख : शमीम खान

ओरल हेल्थ डे : 20 मार्च

ओरल हेल्थ रहेगा अच्छा, तो सेहतमंद रहेंगे आप

गंभीर बीमारी बन सकती इन्फेक्शन

मुंह के इन्फेक्शन का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. इससे डायबिटीज, ब्लड सेल्स डिसआर्डर, ओरल कैंसर, कॉर्डियोवास्कुलर संबंधी रोग आदि हो सकते हैं. दरअसल, ओरल हेल्थ के बिगड़ने का प्रमुख कारण मुंह में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं.

थोड़ी-सी कोशिश का बड़ा लाभ

ओरल हेल्थ और चमकते दांत हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का आधार हैं. हम डेली लाइफ में थोड़ी-सी देखरेख और हाइजीन की आदतों को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं. ओरल हेल्थ पर ध्यान न दिये जाने पर दांतों में प्लैक जमा हो सकते हैं. इनसे बचने के लिए ओरल हाइजीन के साथ धूम्रपान, तंबाकू और शराब के सेवन से दूर रहें.

सेंसेटिविटी जैसी कई अन्य समस्याएं

ओरल हाइजीन का ख्याल न रखने से दांतों के इनेमल में दरारें पड़ने, टूटने या घिसने, मसूड़ों की समस्या जैसे विकार देखे जा सकते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर दांतों की सेंसेटिविटी पर होता है, जिसके कारण दांतों में दर्द, ठंडा-गर्म के उपयोग से सनसनाहट, मसालेदार भोजन करने पर जलन हो सकती है.

प्लैक की वजह से बनती है कैविटी

दांतों की साफ-सफाई ठीक से न करने पर दांतों के बीच में और गम-लाइन के आसपास पीले रंग के चिपचिपे प्लैक या टार्टर की परत जमने लगती है. इस प्लैक से दांतों और मसूड़ों के बीच दूरी बढ़ जाती है, जिसमें प्लैक इकट्ठा होता रहता है. इन्फेक्शन बढ़ने से मसूड़े लाल हो जाते हैं और उनमें से पस और खून बहने लगता है.

ऐसे करें दांतों की सफाई

दांतों की सफाई के लिए 2-2-2 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए. यानी दिन में 2 बार ब्रश करें, ब्रश कम-से-कम 2 मिनट तक करें और वर्ष में 2 बार दांत का चेकअप कराएं. जरूरी हो तो दांतों की प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं.

- कुछ भी खाने के बाद ब्रश न कर पाएं, तो कुल्ला जरूर करें. इससे दांतों में फंसे खाने के टुकड़े बाहर निकल जाते हैं और दांतों में बैक्टीरिया नहीं पनपते. रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें.
- साफई के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट प्रयोग करें. झाग ज्यादा होने से दांत साफ होते हैं.
- गोल ब्रीसेल्स वाले के सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करें. ब्रश 3 महीने पर या ब्रीसेल्स खराब होने पर बदल लें. खराब ब्रश से मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.
- बहुत दबा कर ब्रश न करें. ब्रश को 45 डिग्री कोण पर पकड़ कर आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर की तरफ धीरे-धीरे घुमाते हुए हल्के हाथों से ब्रश करें.
- ब्रश करने के बाद जीभ की सफाई जरूर करें.
- दांत में कुछ फंसे, तो डेंटल फ्लॉस का उपयोग करें.

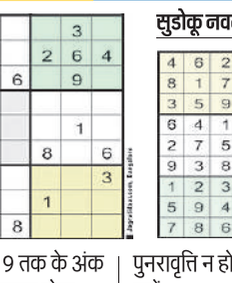

मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट टीबी : नयी दवाओं से तेज उपचार संभव

डॉ एसपी राय
सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, मुंबई

मेडिकल साइंस में तेजी से हुई प्रगति से अब टीबी जैसी बीमारी का तेज इलाज संभव है. फिर भी यह रोग पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक दुनियाभर से टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है. जानें कैसे टीबी के खतरे को कम करने में दें योगदान.

हाल के वर्षों में टीबी के इलाज में बड़ी प्रगति हुई है. मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के इलाज के लिए देश में 6 महीने की नयी उपचार पद्धति 'BPaLM' रेजिमेन को मंजूरी दी गयी है. पहले इस प्रकार की टीबी का इलाज 18 से 20 महीने तक चलता था. BPaLM रेजिमेन चार दवाओं का संयोजन है- B(बी) : बेडाक्विलिन, Pa(पा) : प्रीटोमैनिड, L(एल) : लिनेजोलिड, M(एम) : मॉक्सीफ्लॉक्सासिन. इन दवाओं को पूरी तरह गोलियों के रूप में दिया जाता है. यह उपचार उन मरीजों को दिया जाता है, जिनके शरीर में टीबी के जीवाणु पहली पंक्ति की दवाओं- आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथेमबुटोल और पाइराजिनामाइड के प्रति प्रतिरोधी हो चुके होते हैं.

वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च

टीबी के मामलों में कमी

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, भारत में 2015 के बाद से टीबी के नये मामलों में लगभग 21 प्रतिशत कमी आयी है. 2015 में प्रति लाख आबादी पर 237 मामले थे, जो 2024 में घटकर 187 रह गये.

टीबी के विविध प्रकार

टीबी को राजयक्ष्मा, क्षय रोग या तपेदिक भी कहा जाता है. यह रोग हवा के जरिये फैलता है. जब संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, तो उसके मुंह से निकली सूक्ष्म बूंदों से दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं. लगभग 80 से 85 प्रतिशत मरीज फेफड़ों की टीबी यानी पल्मोनरी टीबी से ग्रस्त होते हैं. समय पर इलाज से यह पूरी तरह ठीक हो सकती है. जब जीवाणु खून के जरिये शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाते हैं, तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है. यह हड्डियों, रीढ़, लिंफ नोड्स, आंत, लिवर, गले और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है. करीब 15 प्रतिशत मरीज इस प्रकार की टीबी से ग्रस्त होते हैं.

सक्रिय और असक्रिय टीबी

- सक्रिय टीबी में जीवाणु सक्रिय होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं और रोग फैल सकता है.
- असक्रिय या लेटेंट टीबी में जीवाणु शरीर में होते हैं, लेकिन सक्रिय नहीं होते. ऐसे में लक्षण नहीं होते और रोग नहीं फैलता.

ये हो सकते हैं लक्षण

- तीन सप्ताह से अधिक खांसी
- खांसते समय खून आना
- अचानक वजन कम होना
- बुखार, भूख कम लगना
- कमजोरी और थकान
- सीने में दर्द, रात में पसीना
- एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रभावित अंग के अनुसार लक्षण.

किन लोगों को ज्यादा खतरा

एचआइवी से ग्रस्त लोग, टाइप-2 डायबिटीज के मरीज, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग, कुपोषण से पीड़ित लोग, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली वाले लोग

किन जांचों से चलता है पता

फेफड़ों की टीबी के लिए बलगम की जांच की जाती है. जरूरत पड़ने पर स्प्यूटम कल्चर, एक्स-रे, सीटी स्कैन या एमआरआइ कराया जाता है. एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में पेशाब, फ्लूइड या बायोप्सी की जांच भी की जा सकती है.

इलाज पूरा करना बहुत जरूरी

कुछ मरीज दवा बीच में छोड़ देते हैं, जिससे रोग दोबारा हो सकता है. इसे रिलेप्स कहा जाता है. लगभग 2 से 3 प्रतिशत मरीजों में टीबी फिर से हो सकती है. इससे बचने के लिए दवा नियमित लें, इलाज पूरा करें, डॉक्टर से संपर्क बनाये रखें.

खान-पान और इम्युनिटी का महत्व

आहार में दूध, दही, मट्ठा, दाल, सोयाबीन, अंडा, मछली, मांस, मौसमी फल, विटामिन-सी युक्त फल, अंकुरित अनाज आदि शामिल करें. जंक फूड और नशे से बचें. टीबी के मरीजों के लिए विटामिन-डी बहुत जरूरी है. सुबह की धूप लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रिकवरी जल्दी होती है. जरूरी है कि मरीज समय पर जांच कराए, डॉक्टर की सलाह माने और पूरा इलाज करे. सही जानकारी, सही दवा और मजबूत इम्यूनिटी से टीबी को हराया जा सकता है.

बातचीत : विवेक शुक्ला

राशिफल — डॉ एनके बेरा

- **मेष :** आत्मविश्वास की वृद्धि होगी. नयी कार्ययोजनाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी.
- **वृष :** आत्मविश्वास बढ़ेगा. बुद्धि व विवेक का भरपूर सदुपयोग करें.
- **मिथुन :** समय पर सभी महत्वपूर्ण कार्य बनते नजर आयेंगे. धन लाभ होगा.
- **कर्क :** आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. धन का लाभ होगा. शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.
- **सिंह :** वाहन-मकान या भूमि के सौदे अभी स्थगित करें. सक्रियता बनाये रखें.
- **कन्या :** प्रेम-प्रसंगों में उलझन होगा. विरोधियों से परेशानी हो सकती है.
- **तुला :** नौकरीपेशा वाले जातकों की सेवाशर्तों में सुधार होगा.
- **वृश्चिक :** लाभदायक प्रेरक-प्रसंगों की अभिवृद्धि होगी. संकल्पित कार्य पूरे होंगे.
- **धनु :** विद्या, बुद्धि व प्रतिभा का विकास होगा. परीक्षा में सफलता मिलेगी.
- **मकर :** सट्टा या लॉटरी से दूर रहें. हर्षदायक समाचार मिलेंगे.
- **कुंभ :** दिमागी तनाव दूर होंगे. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.
- **मीन :** सरकारी तथा न्यायालयीय कार्यों में कठिनाई उत्पन्न होगी.

शब्दपहेली — 2854

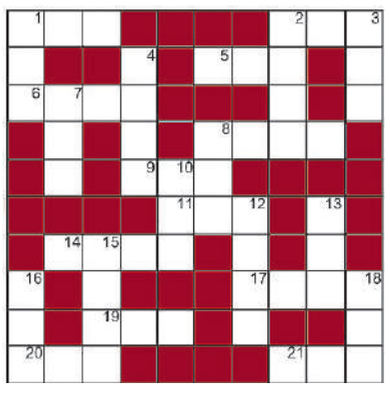

बायें से दायें : 1 गायक, गाने वाला (3), 2 जो अपना न हो, किसी और का (3), 5 धोखा, छल, मिथ्या व्यवहार (3), 6 उपहार, भेंट के रूप में दी जाने वाली वस्तु (4), 8 थाती, धरोहर (4), 9 पृथ्वी, धरा, जमीन (3), 11 दूसरे के अधीन, लाचार, मजबूर (3), 14 द्वार, किवाड़, फाटक (4), 17 बाल्यावस्था (4), 19 चिढ़ना, खिजलाना (3), 20 उमंग, हिलोरा (3), 21 भेद कहना, उघड़ना, बंद न रहना (3).

ऊपर से नीचे : 1 दुर्गम, घना, गहरा, अथाह (3), 2 पाट, जूट (4), 3 भिखमंगा, मांगने वाला, भिखारी (3), 4 अनेक प्रकार का (4), 7 कल्ला, गाल के भीतर का भाग (3), 8 अतिशय, अत्यंत (3), 10 कालिंदी, यमुना (3), 12 मधुर पेय, चीनी आदि का रस (4), 13 वृक्ष, पेड़, पीढ़ा (3), 15 ईख के रस में पकाया हुआ चावल (4), 16 खोपड़ी की हड्डी (3), 18 संपूर्ण शरीर को पानी से धोना (3).

सुडोकू नवताल — पहेली नंबर 6246

			2			3		
		9		8		2	6	4
1				3	6		9	
4		3						
	8			2			1	
						8		6
	4		7	5				3
3	7	5		4		1		
	2				8			

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने हैं. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है.
- आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो. इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सुडोकू नवताल - 6245 का हल

4	6	2	3	5	8	9	1	7
8	1	7	9	2	6	3	5	4
3	5	9	1	7	4	8	2	6
6	4	1	5	3	7	2	8	9
2	7	5	8	4	9	6	3	1
9	3	8	2	6	1	4	7	5
1	2	3	6	9	5	7	4	8
5	9	4	7	8	2	1	6	3
7	8	6	4	1	3	5	9	2

मार्केट अपडेट सेंसेक्स 76,070.84 ↑ +567.99 (0.75%) | निफ्टी 23,581.15 ↑ +172.35 (0.74%) prabhatkhabar.com

अच्छे मूल्यांकन के कारण मेटल और ऑटो शेयरों में बढ़ी खरीदारी

बाजार में लगातार दूसरे दिन भी तेजी दो सत्रों में सेंसेक्स 1506 अंक उछला

एजेंसियां, मुंबई

वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख और मेटल व ऑटो शेयरों में खरीदारी के कारण घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गयी और बीएसइ का सेंसेक्स 568 अंक बढ़त के साथ 76070.84 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 801.41 अंक बढ़ कर 76304.26 अंक तक पहुंच गया था. वहीं एनएसइ का निफ्टी भी 172.35 अंक चढ़ कर 23581.15 पर बंद हुआ. इन दो दिनों की तेजी में सेंसेक्स में 1506 अंकों की उछाल दर्ज की गयी, वहीं एनएसइ के निफ्टी 430 अंक चढ़ गया. बीएसइ मिडकैप इंडेक्स एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी रही. सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी ऑटो ने अपनी रैली को आगे बढ़ाया, जो पिछले सत्र की गति को जारी रखते हुए 2% से ज्यादा बढ़ गया. इसके अलावा मेटल (2.82%),कैपिटल गुड्स (2.17%) शेयरों में बढ़त रही.

निवेशकों को 3.48 लाख करोड़ रुपये का लाभ

बीएसइ में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन मंगलवार को बढ़कर 433.30 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. शुक्रवार को यह 429.82 लाख करोड़ रुपये पर था. इस तरह बीएसइ में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप दो दिन में करीब 3.48 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है. दूसरे शब्दों में निवेशकों की संपत्ति में 3.48 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

एक्सप्लेनर बाजार की तेजी के प्रमुख कारण

वैल्यू बाइंग : पिछले कुछ दिनों की शेयर बाजार में जारी गिरावट के बाद निवेशकों ने कई सेक्टरों में खरीदारी शुरू की. अच्छे मूल्य पर उपलब्ध शेयरों में निवेशकों ने रुचि दिखायी. खासकर ऑटो, मेटल और रियल्टी सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार को ऊपर उठाने में मदद की.

वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती ने घरेलू बाजार में सकारात्मक संकेत दिये. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली. जापान का निक्की 225 करीब 0.4% चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉप्सी करीब 1.63% उछल गया. हांगकांग का हैंगसेंग भी बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजार तेजी के रुख के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे.

एक्सपर्ट व्यू

शशांक भारद्वाज
सीनियर वीपी
चॉइस ब्रोकिंग

अब शेयर विशेष में बहुत अच्छी उछाल दिख सकती है

सोमवार को जो तेजी आयी, वह दबे पांव सी तेजी थी. उसके बाद अगले दिन भी तेजी रही. जब कोई तेजी बिना किसी कारण के प्रारंभ होती है एवं अगले दिन भी बनी रहती है, तो यह एक नयी बड़ी तेजी का संकेत तथा आधार मानी जाती है. यह इस बात का संकेत होता है कि मार्केट में बॉटम बन गया है. अब शेयर विशेष में बहुत अच्छा उछाल दिख सकता है, यदि अमेरिका ईरान युद्ध में कोई बड़ा नकारात्मक कारक न आ जाए. नीची पीई पर उपलब्ध अच्छे शेयरों में आक्रामक क्रय किया जा सकता है.

क्विक बाइट्स

जियो पेमेंट्स बैंक ने यूपीआइ आधारित नकदी निकासी सेवा शुरू की

नयी दिल्ली. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक ने अपने 'बिजनेस करिस्पोंडेंट टचपॉइंट्स' के माध्यम से यूपीआइ आधारित नकद निकासी की सुविधा शुरू की है. यह कदम डिजिटल भुगतान परिवेश को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बिजनेस करिस्पोंडेंट टचपॉइंट्स बैंकिंग का एक ऐसा माध्यम हैं, जहां ग्राहक बैंक शाखा जाए बिना अपने बैंकिंग लेन-देन कर सकते हैं.

रेनो की 'डस्टर' नये अवतार में लौटी, कीमत ₹10.49 लाख से शुरू

नयी दिल्ली. रेनो ने मंगलवार को भारतीय बाजार में अपनी मध्यम आकार की एसयूवी 'डस्टर' के पूरी तरह नये अवतार को 10.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया. नयी डस्टर के टर्बो पेट्रोल संस्करण को बिक्री के लिए जारी करते हुए कहा कि देशभर में इसकी डिलिवरी अब शुरू हो गयी है. हालांकि, 31 मार्च तक बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को यह संस्करण 10.29 लाख रुपये की शोरूम कीमत पर ही मिल जायेगा.

इनोविजन के आइपीओ को 3.32 गुना अभिदान मिला

नयी दिल्ली. टोल प्लाजा प्रबंधन सेवा प्रदाता इनोविजन लिमिटेड के आइपीओ को मंगलवार को शेयर बिक्री के अंतिम दिन 3.32 गुना अभिदान मिला. निवेशकों की ठंडी प्रतिक्रिया के बाद इनोविज़न लिमिटेड ने पिछले सप्ताह अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की समापन तिथि 17 मार्च तक बढ़ा दी थी और मूल्य दायरा भी कम कर दिया था. आइपीओ में 63,99,943 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 2,12,70,519 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं.

जेपी एसोसिएट्स का अधिग्रहण करेगी अदाणी ग्रुप

नयी दिल्ली. एनसीएलटी ने मंगलवार को दिवाला प्रक्रिया के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी. जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल) ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने 17 मार्च, 2026 को अपने आदेश में अदाणी एंटरप्राइजेज की समाधान योजना को मंजूरी दी.

इपीएफ पेंशन सम्मानजनक करने की जरूरत, ₹1,000 प्रति माह पर्याप्त नहीं

- संसदीय समिति ने की समीक्षा की सिफारिश

एजेंसियां, नयी दिल्ली

संसद की एक समिति ने मंगलवार को इपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये की तत्काल और व्यापक समीक्षा की सिफारिश की. समिति ने कहा कि इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है. यह सिफारिश ऐसे समय की गयी है जब पेंशनधारक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि 1,000 रुपये से गुजर-बसर करना मुश्किल है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशनधारकों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर नौ मार्च से जंतर-मंतर पर तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन भी किया था. श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2026-27)' पर अपनी 15वीं रिपोर्ट में कहा कि महंगाई बढ़ने के बावजूद कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह काफी समय से अपरिवर्तित है.

बजटीय सहायता बढ़ाने की संभावना तलाशा जाए

समिति का सुझाव है कि मंत्रालय योजना के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने की संभावना तलाशे, ताकि पेंशनधारकों को वर्तमान जीवन यापन लागत के अनुरूप उचित न्यूनतम पेंशन प्राप्त हो सके और योजना के अंतर्गत आने वाले लाखों सेवानिवृत्त श्रमिकों को अधिक सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान की जा सके. समिति ने प्राथमिकता के आधार पर एक स्थायी समन्वय एवं संवाद बोर्ड के गठन की भी सिफारिश की है.

सुरक्षित निवेश की मांग में तेजी, सोना ₹1,050 हुआ मजबूत, चांदी ₹6,000 चढ़ी

एजेंसियां, नयी दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को कीमती धातुओं की कीमतों में दो प्रतिशत तक का उछाल आया. चांदी 6,000 रुपये बढ़कर 2.62 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी, जबकि सोना बढ़कर 1.61 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है. चांदी की कीमत 6,000 रुपये या 2.34 प्रतिशत बढ़कर 2,62,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गयी. सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने में लगातार तीन दिन की गिरावट का सिलसिला टूट गया और इसकी कीमत 1,050 रुपये या लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 1,61,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गयी. विश्लेषकों ने कहा कि सर्राफा की कीमतों में यह उछाल भू-राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश वाली आस्तियों की मांग से प्रेरित था. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि जब तक फेडरल रिजर्व कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं देता, तब तक कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है.

रुपया 92.40 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर

मुंबई. अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया मंगलवार को 12 पैसे टूटकर अपने सबसे निचले स्तर 92.40 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ. पश्चिम एशिया संकट के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी से रुपये में गिरावट आयी. विदेशी घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान भी रुपये को कमजोर स्तर पर सहारा देने में मदद कर रहा है.

संडीला में ज्ञानधारा का किसान संवाद, डेयरी प्रबंधन पर जोर

संवाददाता, पटना

ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 17 मार्च को संडीला स्थित प्लांट में किसान एवं वितरक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 किसानों और वितरकों ने भाग लिया. कार्यक्रम में डॉ एमआर गर्ग ने पशु पोषण के वैज्ञानिक पहलुओं पर जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के उत्पाद वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किये जाते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है. वहीं डॉ जेएन पांडेय ने पशु आहार की गुणवत्ता, सही उपयोग और गर्मी के मौसम में पशुओं के रखरखाव पर महत्वपूर्ण

सुझाव दिये. कंपनी के ऑपरेशनल हेड दुर्गेश अवस्थी ने संस्था के विजन और किसान पहले की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर रितु अग्रवाल के नेतृत्व में कंपनी किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. मौके पर हितेंद्रपाल सिंह, रेजा मोहम्मद खान, राघवेंद्र सेंगर सहित कंपनी के अधिकारी, वितरक और किसान उपस्थित रहे.

देश में 40 प्रतिशत स्नातकों को नहीं मिल पा रही नौकरी

रिपोर्ट

एजेंसियां, नयी दिल्ली

देश में 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 6.3 करोड़ स्नातकों में से 1.1 करोड़ बेरोजगार हैं और स्नातक होने के एक वर्ष के भीतर बहुत कम लोगों को ही निश्चित वेतन वाली नौकरी मिल पाती है. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट 'भारत में कामकाज की स्थिति-2026' में पाया गया कि बेरोजगार के रूप में पंजीकरण कराने के एक वर्ष के भीतर केवल करीब सात प्रतिशत स्नातकों को स्थायी वेतन वाली नौकरी मिल पाती है. रिपोर्ट में कहा गया कि स्नातक बेरोजगारी दर उच्च बनी हुई है. 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर करीब 40 प्रतिशत और 25 से 29 वर्ष आयु वर्ग में 20 प्रतिशत है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में उच्च शिक्षा में नामांकन दर भी बढ़ी है जिससे युवा स्नातकों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है. इस स्थिति से उच्च बेरोजगारी दर के साथ बेरोजगार स्नातकों की संख्या भी बढ़ गयी है.

नीता अंबानी को केआइआइटी ने किया सम्मानित

भुवनेश्वर. रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं चेयरपर्सन नीता अंबानी को यहां आयोजित एक समारोह में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआइएसएस) ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया. केआइआइटी ने कहा कि श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहन मुनासिंघे ने सोमवार को यहां पुरस्कार दिया.समारोह में 40 हजार आदिवासी छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने पारंपरिक नृत्य और प्रस्तुतियों के साथ अंबानी का स्वागत किया.

नीलांचल इस्पात के विलय को टाटा स्टील बोर्ड ने दी मंजूरी

एजेंसियां, नयी दिल्ली

टाटा स्टील के निदेशक मंडल ने मंगलवार को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआइएनएल) के अपने साथ विलय और अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स पीटीई (टीएसएचपी) में दो अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दे दी. टाटा स्टील ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि निदेशक मंडल ने मणिपाल हॉस्पिटल्स इस्टर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मेडिका टीएस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (मेडिका टीएस हॉस्पिटल) में 1.49 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है. टाटा स्टील के निदेशक मंडल ने एनआइएनएल, टाटा स्टील और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच विलय योजना को मंजूरी दे दी है. टाटा स्टील ने चार जुलाई 2022 को ओडिशा स्थित एनआईएनएल का अधिग्रहण अपनी पूर्व अनुषंगी टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट्स (टीएसएलपी) के माध्यम से 12,100 करोड़ रुपये में पूरा किया था.

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक जीडीपी का 20%

नयी दिल्ली. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है. 'नैसकॉम ग्लोबल कॉन्फ्लूएंस 2026' में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत के जीडीपी में लगभग 13% का योगदान करती है. उन्होंने कहा कि डिजिटल क्षेत्र की वृद्धि दर व्यापक अर्थव्यवस्था की तुलना में दोगुनी होगी.

ग्लैमर प्रभात

अली फजल और ऋचा चड्ढा ने मनायी छठवीं वेडिंग एनिवर्सरी

मुंबई. बॉलीवुड के क्वर्की कपल अली फजल और ऋचा चड्ढा ने 17 मार्च 2020 को रजिस्टर्ड मैरिज की थी. शादी का खुलासा दोनों ने 2022 में किया था, जब परिवार के साथ मिलकर शादी और रिसेप्शन फंक्शन मनाया गया. अब उनकी शादी को छह साल पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके पर अली फजल ने पत्नी ऋचा को सोशल मीडिया पर प्यारी फोटोज के साथ विश किया. अली ने कहा कि ये फोटोज उनकी फेवरेट हैं और इन्हें शेयर करने का इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी एनिवर्सरी पार्टनर. आज का दिन लिखा गया था, बाकी सारे दिन परोस दिये गये हैं. बहुत प्यार के साथ, अली."

'घरवाली पेड़वाली' में दर्शकों को भा रहे लतिका के देसी लुक्स

मुंबई. सुपरनैचुरल हॉरर-कॉमेडी शो 'घरवाली पेड़वाली' में लतिका की भूमिका निभा रहीं अभिनेत्री प्रियंवदा कांत अपने आकर्षक देसी अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. मौजूदा ट्रैक में वह रंग-बिरंगे घाघरा-चोली, लेयर्ड और घेरदार कॉस्ट्यूम्स में नजर आ रही हैं, जो उनके रहस्यमयी और शालीन किरदार को खूबसूरती से उभारते हैं. एंडटीवी के शो 'घरवाली पेड़वाली' के बारे में प्रियंवदा कहती हैं कि शो की शुरुआत में लाल दुल्हन वाली ड्रेस लतिका की पहचान बन गयी थी, लेकिन अब विभिन्न पारंपरिक लुक्स में प्रयोग ताजगी और रोमांच जोड़ता है. ज्वेलरी, झुमके, चूड़ियां और मांग टीका पूरे लुक को पूरा करते हैं.

वर्ष : 30, **अंक** 310, **रजिस्ट्रेशन** : आर एन 66055/96, **पोस्टल रजिस्ट्रेशन** : पी टी-42/2009, **अखबार के स्वामी** न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लि. के लिए **मुद्रक** एवं **प्रकाशक** आशुतोष चौबे द्वारा न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लि., प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013 से मुद्रित एवं प्रकाशित, **संपादक** (पटना संस्करण) : रंजीत प्रसाद सिंह*, **संपादक** (बिहार) : अजय कुमार, **प्रधान संपादक :** अंकित शुक्ला, **फोन** : कार्यालय : 0612-2540550, 9264427606, 9264427607, **इ-मेल** : patna@prabhatkhabar.in (*पीआरपी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)

Stay Ahead Of Competition
Join The Aspirants Community.

✅ Receive Earliest Newspapers updates from 5 AM with All Editions

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ **International Newspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International
[Genaral & Exam related]

Click Here

♦ **Editorials [English & Hindi]**

[National + International Editorials]